



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39]

नई दिल्ली, शनिवार, 27 सितम्बर, 1975/आश्विन 5, 1897

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazette of India Extraordinary were published up to the 31st March 1975 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
107.	का० भा० 146(घ) दिनांक 19 मार्च, 1975	उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स (वैगन्ज डिबीजन) मोकाया, बिहार द्वारा 15 फरवरी, 1974 से पूर्व किये गये या दिये गये और इस आदेश के निकाले जाने के दिनांक से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं पत्राढो, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों के प्रवर्तन तथा उक्त दिनांक से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं तथा दायित्वों का निरन्तर करना।
S.O. 146(E) dated the 19th March, 1975.		Ministry of Industry and Civil Supplies.	Suspending operation of Contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into given or made by Messrs Britannia Engineering Works (Wagons Division) Mokameh, Bihar before the 15th February, 1974 and in force before the date of issue of the order, along with all the rights, obligations, privileges and liabilities accruing or arising thereunder before the said date.

1	2	3	4
108. सा० प्रा० 147(अ) दिनांक 20 मार्च, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	रिचर्डसन एण्ड क्रुडन लिमिटेड (उपक्रम अर्जन और अन्तरण अधिनियम, 1972 (1972 का 78) के अधीन नियमों का बनाना।	Making rules under the Richardson and Cruddan Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972 (78 of 1972).
S.O. 147(E) dated the 20th March, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.		
109. का० प्रा० 148(अ) दिनांक 20 मार्च, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	सम्मिश्र बोर्ड (सम्मिश्र आसाम राज्य के लिए आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड) के संबंध में पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 61) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करना।	Making order in exercise of the powers conferred by Section 87 of the North-Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 (81 of 1971) in regard to the Composite Board (Assam State Electricity Board, constituted for the Composite State of Assam).
S.O. 148(E) dated the 19th March, 1975	Ministry of Energy		
का० प्रा० 149 (अ)	ऊर्जा मंत्रालय	यह निर्देश करने के लिए आदेश करना कि आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड तथा मेघालय राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा सम्मिश्र आसाम राज्य के लिए गठित आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड के उपक्रम, भास्तिता, अधिकार, दायित्व और कर्मचारी तथा विनिर्दिष्ट ग्रहण कर लिये जायेंगे।	Making order to direct that the undertakings, assets, rights, liabilities and employees of the Assam State Electricity Board constituted for the composite State of Assam shall be taken over by the Assam State Electricity Board and Meghalaya State Electricity Board as specified.
S.O. 149(E) dated the 20th March, 1975	Ministry of Energy		
110. का० प्रा० 150(अ), दिनांक 21 मार्च, 1975	पैट्रोलेियम और रसायन मंत्रालय	भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलेियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 1873, 18 मई, 1970 में संशोधन।	Amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals No. S.O. 1873, dated 18th May, 1970.
S.O. 150(E), dated the 21st March, 1975.	Ministry of Petroleum and Chemicals.		
111. का० प्रा० 151(अ) 118 चख/आई० डी० आर० ए०/75 दिनांक 21 मार्च, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मैससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (प्रसम) लिमिटेड, चन्द्रपुर के संबंध में इस आदेश के निकाले जाने के दिनांक से पूर्व प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, पंजाबों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों और उक्त दिनांक से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं तथा दायित्वों का निरन्तरित करना।	Suspending operation of contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in regard to M/s. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur in force before the date of issue of this order and rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date.
S.O. 151(E)/18 FB/IDRA/75, dated the 21st March, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.		
112. का० प्रा० 152(अ), दिनांक 25 मार्च, 1975	भारत परिसीमत आयोग	बिहार राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमित के लिए भारत परिसीमत आयोग की प्रस्थापनाएं सह्युक्त सदस्यों की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित और 22 अप्रैल, 1975 वह दिनांक है जिसको या जिसके बाद उक्त प्रस्थापनाओं पर विचार करना है।	

1	2	3	4
	S.O. 152(E), dated the 25th March, 1975.	Delimitation Commission, India.	Proposals of the Delimitation Commission, India for delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Bihar with the dissenting proposals of Associate members and 22nd April, 1975 is the date on or after which the proposals are to be considered.
113.	का० प्रा० 153 (अ), दिनांक 25 मार्च, 1975	वित्त मंत्रालय	अधिसूचना सं० का० प्रा० 225(अ), दिनांक 30 मार्च, 1974 को अतिक्रान्त करते हुए साढ़े सात प्रतिशत दर के रूप में नियत करना जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की खतुर्थ अनुसूची के भाग-क के नियम 6 के खण्ड (ख) में संबंधित की गई है।
	S.O. 153(E), dated the 25th March, 1975.	Ministry of Finance	In supersession of notification No. S.O. 225(E), dated the 30th March, 1974 fixing seven and a half per cent as the rate referred to in clause (b) of Rule 6 of Part A of the Fourth Schedule to the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
114.	का० प्रा० 154 (अ), दिनांक 26 मार्च, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	ट्रैक्टर (वितरण और बिक्रय) नियमन आदेश, 1971 में संशोधन करने के लिये आदेश।
	S.O. 154(E), dated the 26th March, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Order to amend the Tractors (Distribution and State) Control Order, 1971.
115.	का० प्रा० 155(अ), दिनांक 26 मार्च, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	आदेश सं० का० प्रा० 322(अ), दिनांक 24 मई, 1974 का शुद्धि-पत्र।
	S.O. 155(E), dated the 26th March, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Corrigendum to Order No. S.O. 322(E), dated the 24th May, 1974.
116.	का० प्रा० 156(अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/75, दिनांक 26 मार्च, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 725 (अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72 दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में संशोधन।
	S.O. 156(E)/18A/IDRA/75, dated the 26th March, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Amendment in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA 72, dated the 25th November, 1972.
117.	का० प्रा० 157(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975	श्रम मंत्रालय	कोटा स्थित राजस्थान परमाणु शक्ति प्रायोजना में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित हड़ताल को प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 157(E), dated the 29th March, 1975.	Ministry of Labour	Prohibiting any strike in connection with any dispute in the Rajasthan Atomic Power Project Kotah.
118.	का० प्रा० 158(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975	श्रम मंत्रालय	कलकत्ता के निगम के प्रतिष्ठानों में किसी भी विवाद से संबंधित किसी भी हड़ताल को प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 158(E), dated the 29th March, 1975.	Ministry of Labour	Prohibiting any strike in connection with any industrial dispute in the establishments of the Corporation of Calcutta.
119.	का० प्रा० 159(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3616, दिनांक 10 अक्टूबर, 1968 का अतिक्रमण करते हुए बरो को, जो कोयले और कोक पर उत्पादन शुल्क के रूप में लागू होगी, नियत करना।
	S.O. 159(E), dated the 29th March, 1975.	Ministry of Engery	In supersession of the late Ministry of Steel, Mines and Metals notification No. S.O. 3616 dated the 10th October, 1968 fixation of rates at which the duty of excise shall be levied on coal and coke.
120.	S.O. 160(E), dated the 31st March, 1975.	Delimitation Commission, India.	Publishing the dissenting proposals received from the Associate Members for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Punjab in addition to those published by Notification No. 282/PB/75 dated the 10th March, 1975.

1	2	3	4
121.	का० घा० 161(अ), दिनांक 31 मार्च, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	निदेश देना कि 24 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० का० घा० 52(अ) 31 जुलाई, 1975 तक प्रवृत्त रहेगी।
	S.O. 161(E), dated the 31st March, 1975.	Ministry of Agriculture & Irrigation	Directing that the Notification No. S.O. 52(E) dated the 24th January, 1975 shall remain in force upto the 31st July, 1975.
122.	का० घा० 162(अ), दिनांक 31 मार्च, 1975	श्रम मंत्रालय	नियोक्तों को भविष्य निधि के मासिक प्रभिदाय को न्यासी बोर्ड को अन्तर्गत करने के लिए तथा न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि संचयनों को यथा निविष्ट विनिहित करने के लिए निदेश देना।
	S.O. 162(E), dated the 31st March, 1975.	Ministry of Labour	Directing the employers to transfer the monthly provident fund contributions to the Board of Trustees and Board of Trustees to invest the provided fund accumulations in the specified manner.
	का० घा० 163(अ), दिनांक 31 मार्च, 1975	श्रम मंत्रालय	भविष्य निधि प्रभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को बाध्यकर निर्गमों को कम करके यथा निविष्ट नमूने के अनुसार विनिहित करने के लिए निदेश देना।
	S.O. 163(E), dated the 31st March, 1975.	Ministry of Labour	Directing to invest in accordance with the specified pattern the accumulations out of the provident fund contributions interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings.
123.	का० घा० 164(अ), दिनांक 31 मार्च, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ, रोडेसिया, पाकिस्तान तथा चीन के तिब्बत प्रदेश को छोड़कर किसी भी देश से भारत में निविष्ट व्यौरों के मास के आयात के लिए सामान्य अनुमति देना।
	S.O. 164(E), dated the 31st March, 1975	Ministry of Commerce	Giving general permission to import into India from any country in the world except the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Pakistan and Tibet region of China, any goods of the description specified.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० अ० 4128.—यसः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 116-रामपुर खास निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम शंकर, ग्राम किठावा, पोस्ट थरई, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम शंकर को ससब के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है।

[स० उ० प्र०-वि० सं०/116/74(58)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th August, 1975

S.O. 4128.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Shanker, Village Kithwan, P.O. Tharaee, District Rae Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Shanker to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(58)]

आदेश

क्र० प्र० 4129.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 116-रामपुर खास निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम राज सिंह, ग्राम नरई पुर, काथो, पोस्ट दखवापुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री श्याम राज सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/116/74(59)]

ORDER

S.O. 4129.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Raj Singh, Village Naree Pur Kagho, P.O. Dakhwapur, Distt. Pratappgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Raj Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(59)]

आदेश

क्र० प्र० 4130.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 116-रामपुर खास निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामकिशोर, ग्राम हिमाउपुर, पोस्ट भुदरहा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रोति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम किशोर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/116/74(60)]

ORDER

S.O. 4130.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Kishor, Village Himayupur, P.O. Bhudaha, District Pratappgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Kishor to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(60)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

क्र० प्र० 4131.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 320-नरैनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्र शेखर आश्रम, रामराज परिषद् कुटीर, खोही, चित्रकूट, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री चन्द्र शेखर आश्रम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/320/74(92)]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4131.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Shekhar Ashram, Ram Raj Parishad Kutir, Khohi Chitrakoot, District Bandan, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Shekhar Ashram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(92)]

आदेश

क्रा० प्रा० 4132.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 320-नरैनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मध्यादीन, ग्राम व पोस्ट गोकिया, जिला बांदा उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मध्यादीन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/320/74(93)]

ORDER

S.O. 4132.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maiya Din, Village and Post Gokhiya, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maiya Din to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(93)]

आदेश

क्रा० प्रा० 4133.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 320-नरैनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेवा लाल, मोहल्ला गांधी गंज, अतर्रा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेवा लाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/320/74(94)]

ORDER

S.O. 4133.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mewa Lal, Mohalla Gandhiganj, Atarra, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mewa Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(94)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

क्रा० प्रा० 4134.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 92-बांगरमन निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल सत्तार, मुहल्ला राहतगंज, पो० सफीपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अप्रत्याशित पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अब्दुल सत्तार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/92/74(104)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4134.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Sattar, Mohalla Rahatganj, Post Safipur, District Unnao, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 92-Bangarman assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Sattar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/92/74(104)]

आदेश

का० आ० 4135.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरीशंकर, मुहल्ला 27-दुर्गा प्रसाद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरीशंकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से,

[सं० उ० प्र-वि० सं०/57/74(105)]

ORDER

S.O. 4135.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Shanker, Mohalla 27-Durga Prasad, Pilibhit, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 57-Pilibhit assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Shanker to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order,

[No. UP-LA/57/74(105)]

आदेश

का० आ० 4136.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अखतर हुसैन अम्सारी, मुहल्ला गेखवाँद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अखतर हुसैन अम्सारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र-वि० सं०/57/74(106)]

ORDER

S.O. 4136.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Akhtar Husain Ansari, Mohalla Shekhchand, Pilibhit, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 57-Pilibhit assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Akhtar Husain Ansari to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/57/74(106)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1975

का० आ० 4137.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल वारिस खाँ, ग्राम बरईपुर, पोस्ट अहियापुर, जिला राय बरेली उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल वारिस खाँ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से

[सं० उ० प्र-वि० सं०/109/74(113)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1975

S.O. 4137.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Waris Khan, Village Baraipur, P.O. Ahiyapur, District Rae Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareilly assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Waris Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(113)]

आदेश

क्रा०प्रा० 4138.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमेश चन्द्र, ताड़तला, छोटी बाजार, राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घोषित बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रपञ्च स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10A के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रमेश चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रपञ्च विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/109/74(114)]

ORDER

S.O. 4138.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh Chandra, Tar Talla, Chhoti Bazar, Rae Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareilly assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh Chandra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(114)]

आदेश

क्रा०प्रा० 4131.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम आसरे, ग्राम वपोष्ट नकपुलहा, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घोषित बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रपञ्च स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10A के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम आसरे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रपञ्च विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/109/74(115)]

ORDER

S.O. 4139.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Asrey, Village & P.O. Nakphulaha, District Rae Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareilly assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Asrey to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(115)]

आदेश

क्रा०प्रा० 4140.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 105-सरोजिनी नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छेदा सिंह, ग्राम रायपुर राजा, डा० इटीन्जा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घोषित बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

श्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री छेवा सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

आदेश से

[सं०उ०प्र०-वि०स०/10/5/74(117)]

ORDER

S.O. 4140.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chheda Singh, Village Raipur Raja, P.O. Itaunja, District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 105-Sarojini-nagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chheda Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,

[No. UP-LA/105/74(117)]

आदेश

क्र० प्र० 4141.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 105-सरोजिनी नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरसिंह यादव, ग्राम कुल्ले खेड़ा, डा० अर्जुन गंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं—

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नरसिंह यादव को संसद के किसी भी सदन के लिये किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/105/74(117)]

ORDER

S.O. 4141.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nar Singh Yadav, Village Kulli Khera, P.O. Arjun-ganj, District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate

for election to the U.P. Legislative Assembly from 105-Saro-jini-nagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nar Singh Yadav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/105/74(118)]

क्र० प्र० 4142.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री करन सिंह, ग्राम रतुपुरा, डा० हरगनपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री करन सिंह को संसद के किसी भी सदन के लिये किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/19/74(122)]

ORDER

S.O. 4142.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karan Singh, Village Ratupura, P.O. Harganpur, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(122)]

आदेश

क्र० प्र० 4143.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किशन सिंह, मुहल्ला चाहणीरी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

श्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री किशन सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/19/74(123)]

ORDER

S.O. 4143.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishan Singh, Mohalla Chahsherin Bijnor Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kishan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. UP-LA/19/74(123)]

आदेश

का० प्रा० 4144.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरथू सिंह, ग्राम गौसपुर सादत, डा० कोतवाली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नरथू सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/19/74(124)]

ORDER

S.O. 4144.—Whereas the election Commission is satisfied that Shri Nathu Singh, Village Ghauspur Sadat, P.O. Kotwali, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for

election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathu Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(124)]

आदेश

का० प्रा० 4145.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कृपो देवी, मोहल्ला कायस्थ सराय, नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्रीमती कृपो देवी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/19/74(125)]

ORDER

S.O. 4145.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Kripo Devi, Mohalla Kaysth Sarai, Nagina, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Kripo Devi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(125)]

प्रावेश

क्र० प्र० 4146.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 10-अल्मोड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरीश चन्द्र मेल्कानी, ग्राम नील पहाड़ी (जलना), डाकखाना पहाड़पानी, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गिरीश चन्द्र मेल्कानी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/10/74(126)]

ORDER

S.O. 4146.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girish Chandra Melkani, Village Neelpahri (Jalna), P.O. Paharpani, District Nainital, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 10-Almora assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girish Chandra Melkani to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/10/74(126)]

प्रावेश

क्र० प्र० 4147 --यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 373-अलीगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल मतीन, मकान नं० 576, मुहल्ला कनबरीगंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अब्दुल मतीन को संसद् के किसी भी सदन के किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/373/74(128)]

ORDER

S.O. 4147.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Matin, House No. 576, Mohalla Kanwariganj, District Aligarh Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 373-Aligarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Matin to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/373/74(128)]

प्रावेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

क्र० प्र० 4148.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन के लिए बंका सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंकिम मेहर ग्राम फुलमूठी, डाकघर, संकारी, जिला-बोलनगीर (उड़ीसा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का भी कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है -

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बंकिम मेहर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उड़ीसा-वि० सं०/113/74(1)]

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1975

S.O. 4148.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dutia Meher, Village Phulmuthi, P.O. Sankara, District Bolangir (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Binka constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dutia Meher to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/113/74(1)]

आदेश

क्र० प्र० 4149.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन के लिए बंकीपासी सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बासुदेव पाधान, ग्राम बंकीपासी, डाकघर बंहुडामल, जिला बोलनगीर (उड़ीसा), अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बासुदेव पाधान को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उड़ीसा-वि०सा०/113/74 (2)]

ORDER

S.O. 4149.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Basudeb Padhan, Village Bankipali, P.O. Beheramal District Bolangir (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Binka constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Basudeb Padhan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/113/74 (2)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त 1975

क्र० प्र० 4150.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 203-देवरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विजय बहादुर, ग्राम कोल्हुवा, पो० तथा जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा घोषित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री विजय बहादुर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०सा०/203/74(131)]

ORDER

New Delhi, the 28th August, 1975

S.O. 4150.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vijay Bahadur, Village Kolhua, Post & District Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 203-Deoria assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vijay Bahadur to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/203/74(131)]

S.O. 4151.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 116C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission of India hereby publishes the order of the Supreme Court of India pronounced on 7 August 1975 on an appeal from the judgment and order dated 23 April 1974, of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in Election Petition No. 9 of 1972.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1159 OF 1974

Vadrevu Bhadri Raju

... Appellant

vs.

Kalania Ibrahimhai Kasambhai & Ors.

... Respondents

ORDER

Appeal not pressed. Dismissed. No costs.

Sd/-
(A. ALAGIRISWAMI) J.

Sd/-
(P. K. GOSWAMI) J.

Sd/-
(N. L. UNTWALLA) J.

NEW DELHI,
August 7, 1975.

[No. 82/GJ/9/72]

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1975

क्रा० आ० 4152.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-इसौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कमला देई हरिजन ग्राम बेनीपुर पोस्टमायंग जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयत्न स्वीकृत नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती कमला देई हरिजन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/124/74(132)]

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4152.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Kamla Devi Harijan, Village Benipur, Post Mayang, District Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 124-Issauli assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Kamla Devi Harijan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/124/74(132)]

आदेश

क्रा० आ० 4153.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 296-राजपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामेश्वर, ग्राम ब पोस्ट आफिस गौरीकरण, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयत्न स्वीकृत नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामेश्वर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/296/74(133)]

ORDER

S.O. 4153.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rameshwar, Village and P.O. Gauri Karan, District Kanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 296-Rajpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rameshwar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/296/74(133)]

आदेश

क्रा० आ० 4154.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 125-सुल्तानपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनोहर लाल जायसवाल, पारकीस गंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयत्न स्वीकृत नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनोहर लाल जायसवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/125/74(134)]

ORDER

S.O. 4154.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manohar Lal Jaiswal, Parikinsganj, Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 125-Sultanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manoharlal Jaiswal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/125/74(134)]

आदेश

क्र० प्रा० 4155.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 125-सुल्तानपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम उदित, ग्राम प्रतापपुर, जिला मुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम उदित को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/125/74(135)]

ORDER

S.O. 4155.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Udit, Village Pratappur, District Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 125-Sultanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Udit to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/125/74(135)]

आदेश

क्र० प्रा० 4156.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-चांदा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम अतार मोहल्ला नशीपुर मुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम अतार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/127/74(136)]

ORDER

S.O. 4156.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Avtar, Mohalla Nabipur, Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 127, Chanda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Avtar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years for the date of this order.

[No. UP-LA/127/74(136)]

आदेश

क्र० प्रा० 4157.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 140-सिदौर (प्र० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इन्द्रपति ग्राम सलेमपुर डाक घमौसी जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री इन्द्रपति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/140/74(137)]

ORDER

S.O. 4157.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Indrapati, Village Salempur, Post Dhanauli, District Bara Banki, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 140, Sidohaur (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Indrapati to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years for the date of this order.

[No. UP-LA/140/74(137)]

प्रादेश

नई, दिल्ली 1 सितम्बर, 1975

कां० प्र० 4158—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1972 में हुए मणिपुर विधान सभा के निर्वाचन के लिए 36-हैरोक निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मायबम निभाई लेईरोंगपेन यैरीपोक बी० पी० ओ० यैरीपोक उप खण्ड श्रावसाज, मणिपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रपेशित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उक्त निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मायबम निभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० मणि-वि० सं०/36/72]

New Delhi, the 1st September, 1975

S.O. 4158.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maibam Nimai, Leirongthel Yairipok, B.P.O. Yairipok, Thoubal Sub-Division, Manipur, a contesting candidate for General Election to the Manipur Legislative Assembly, held in March, 1972 from 36-Heirok constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri Maibam Nimai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MR-LA/36/72]

प्रादेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1975

कां० प्र० 4159—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 218-मुधरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल सिंह भारद्वाज, 192-कुर्मी टोला, जिला भाजमगढ़ उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये

गये नियमों द्वारा प्रपेशित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गोपाल सिंह भारद्वाज को संसद के किसी भी सदन के साथ किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है ।

प्रादेश से,

[सं० उ०प्र०-वि०सं०/218/74(139)]

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4159.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Singh Alde, 192. Kurmi Tola, Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 218, Mubarakpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Singh Alde to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/218/74(139)]

प्रादेश

कां० प्र० 4160.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 219-मुहम्मदाबाद गोहाता(प्र०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महाश्वरी ग्राम लकमहज, बाकखाना सुल्तानपुर, जिला भाजमगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रपेशित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री महाश्वरी को संसद के किसी भी सदन के साथ किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०सं०/219/74(140)]

ORDER

S.O. 4160.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahabali, Village Chaksahja, P.O. Sultanpur, District Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 219. Mohamadabad Gohna (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahabali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/219/74(140)]

प्रादेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4161.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 48-आवला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोती चन्द्र, पुक्का कटरा, तहसील आणला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रयत्न स्पष्टीकरण नहीं नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यापारिक नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोती चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है ।

प्रादेश से,

[सं० उ०प्र०-वि०स०/48/74(141)]

ए० एन० सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1975

S.O. 4161.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Moti Chandra, Pucca Katra, Tahsil Aonla, District Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 48, Aonla Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said act, the Election Commission hereby declares the said and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,
[No. UP-LA/48/74(141)]
A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1975

प्राय-कर

का० प्रा० 4162.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, प्राय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा,

यह अधिसूचना 1-4-1975 से प्रभावी है ।

[सं० 1014 (फा०सं० 203/37/75-प्रा०कर० II)]

टी०पी० हुनहुनवाला, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 2nd August, 1975

INCOME TAX

S.O. 4162.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA.

The notification takes effect from 1-4-1975.

[No. 1014 (F. No. 203/37/75-ITA.II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4163.—केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री एस० के० चावला, पी०सी० शर्मा, एस० रामचन्द्रानी, गोर्धन दास और एच०जी० मुंजल को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिसूचना सं० 722 (फा०सं० 404/221/74-आई०टी०सी०सी० तारीख 24 सितम्बर, 1974, 448 (फा० सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 27 अगस्त, 1973, 385 (फा०सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 18 जून, 1973 और 448 (फा०सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 27 अगस्त, 1973 के अधीन की गई क्रमशः सर्वश्री एस० एम० भटनागर, एन० एन० सेठ, जगदेव सिंह यादव, सी० आर० स्याल और बी० पी० मेहदीरता की नियुक्तियां उस तारीख से रद्द की जाती हैं जिस तारीख को सर्वश्री एस० के० चावला, श्री पी०सी० शर्मा, श्री एस० रामचन्द्रानी, श्री गोर्धन दास और श्री एच० जी० मुंजल कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं ।

यह अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को सर्वश्री एस० के० चावला, पी० सी० शर्मा, श्री एस० रामचन्दानी, गोर्धन दास और एन० जी० मुंजल कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1015 (फ० सं० 404/35/75—आई टी सी सी)]

New Delhi, the 4th August 1975

S.O. 4163.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Sarvashri S. K. Chawla, P. C. Sharma, I. S. Ramchandani, Gordhan Dass and H. G. Munjal, who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

The appointments of Sarvashri M. M. Bhatnagar, N. N. Seth, Jagdev Singh Yadav, C. R. Cyal and V. P. Mehndiratta as Tax Recovery Officers made vide Notifications No. 722 (F. No. 404/221/74-ITCC) dated 24th September, 1974, 448 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 27th August, 1973, 385 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 18th June, 1973 and 448 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 27th August, 1973 respectively, are hereby cancelled with effect from the date Shri S. K. Chawla, Shri P. C. Sharma I, Shri S. Ramchandani, Shri Gordhan Dass and Shri H. G. Munjal, take over as Tax Recovery Officers.

This Notification shall come into force with effect from the date S/Shri S. K. Chawla, P. C. Sharma I, Shri S. Ramchandani, Gordhan Dass and H. G. Munjal take over charge as Tax Recovery Officers.

[No. 1015 (F. No. 404/35/75-ITCC)]

का० भा० 4164.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम० ए० सुब्रह्मण्यम को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिसूचना सं० 374 (फ० सं० 404/291/72-आई०टी०सी०सी०) तारीख 4 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई श्री ए० कृष्णमूर्ति की नियुक्ति 18 अगस्त, 1975 से रद्द की जाती है।

यह अधिसूचना 18 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1017 (फ० सं० 404/94/75-आई०टी०सी०सी०)]

S.O. 4164.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri M. A. Subramaniam who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

The appointment of Shri A. Krishnamurthy made under Notification No. 174 (F. No. 404/291/72-ITCC) dated the 4th September, 1972 is hereby cancelled with effect from 18th August, 1975.

This Notification shall come into force with effect from the 18th August, 1975.

[No. 1017 (F. No. 404/94/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

का० भा० 4165.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) द्वारा गठित, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर की पंक्ति के प्रत्येक अधिकारी को उक्त उप-खंड के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 1026 (फ० सं० 403/102/74-आई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 8th August, 1975

S.O. 4165.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said sub-clause, every officer of or above the rank of a Superintendent of Police of the Delhi Special Police Establishment, constituted by the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946).

[No. 1026 (F. No. 403/102/74-ITCC)]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० भा० 4166.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री अजीत सिंह और एस० पी० उप्पाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिसूचना सं० 1001 (फ० सं० 404/97/75-आई०टी०सी०सी०) तारीख 30 जुलाई, 1975 के अधीन की गई श्री जे० बी० भारद्वाज की नियुक्ति रद्द की जाती है।

यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को पैरा 1 में वर्णित अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1029 (फ० सं० 404/97/75-आई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 12th August, 1975.

S.O. 4166.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri Ajit Singh and S. P. Uppal who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

The appointment of Shri J. B. Bhardwaj made under Notification No. 1001 (F. No. 404/97/75-ITCC) dated the 30th July, 1975 is hereby cancelled.

This Notification shall come into force with effect from the date the officers mentioned in para 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1029 (F. No. 404/97/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का०आ० 4167—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री अनिल कुमार राय, श्री पी० के० देव मलिक और निमा दोर्जा लामा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को ऊपर वर्णित अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1032 (फा० सं० 404/77/75-आई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4167.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri Anil Kumar Roy, Shri P. K. Deb Mallick and Nima Dorjay Lama, who are Gazette Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

This Notification shall come into force with effect from the date the Officers mentioned above take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1032 (F. No. 404/77/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

आय-कर

का०आ० 4168—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री पी० एम० वैद्य को, जो केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिसूचना सं० 171 (फा० सं० 404/274/72-आई०टी०सी०सी०), तारीख 1 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई श्री टी० के० आर्जे कुट्टी की नियुक्ति उस तारीख से रद्द की जाती है जिस तारीख को श्री पी० एम० वैद्य कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को श्री पी० एम० वैद्य कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1041 (फा० सं० 404/63/75-आई०टी०सी०सी०)]

श्री० पी० मित्तल, उप-सचिव

New Delhi, the 16th August, 1975

S.O. 4168.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri P. M. Vaidya, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

The appointment of Shri T. K. George Kutty made under Notification No. 171 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated 1st September, 1972 is hereby cancelled with effect from the date Shri P. M. Vaidya takes over as Tax Recovery Officer.

This Notification shall come into force with effect from the date Shri P. M. Vaidya takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1041 (F. No. 404/63/75-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

आदर्श

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

स्टाम्प

का. आ. 4169.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उस शुल्क से जो केरल वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले तेलीस लाख रुपये मूल्य के बचन पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं. 36/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/47/75-सीमा-शुल्क-7]

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1975

STAMPS

S.O. 4169.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes of the value of thirtythree lakhs of rupees, to be issued by the Kerala Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 36/75-Stamp/F. No. 471/47/75-Cus. VII]

आदर्श

का.आ. 4170.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि पुनर्वित्त निगम, मुम्बई को उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले सोलह करोड़ और पचास लाख रुपये अंकित मूल्य के बचनपत्रों के रूप में 3456 बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मद्धे प्रभार्य नों लाख और नब्बे हजार रुपये मात्र समीकित स्टाम्प शुल्क का संवाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं. 37/75-स्टाम्प/फा. संख्या 471/67/75-सीमा-शुल्क-7]

ORDER

S.O. 4170.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agricultural Refinance Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of Nine lakhs and ninety thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on 3456 bonds in the form of promissory notes of the face value of sixteen crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the said corporation.

[No. 37/75-Stamps/F. No. 471/67/75-Cus. VII]

आदेश

क्र.आ. 4171.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले एक सौ सैंतीस लाख और पचास हजार रुपये मूल्य के वचन पत्रों के रूप में बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं. 38/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/63/75-सीमा-शुल्क 7]

ORDER

S.O. 4171.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of one hundred thirtyseven lakhs and fifty thousand rupees, to be issued by the Karnataka State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 38/75-Stamps/F. No. 471/63/75-Cus. VII]

आदेश

क्र. आ. 4172.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले, दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं. 39/75-स्टाम्प फा. सं. 471/72-75-सीमा-शुल्क]

ORDER

S.O. 4172.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of two crores and seventy-five lakhs of rupees, to be issued by the National Co-operative Development Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 39/75-Stamps/F. No. 471/72/75-Cus. VII]

आदेश

क्र.आ. 4173.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो जम्मू-कश्मीर वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं. 40/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/65/75-सीमा-शुल्क 7]

ORDER

S.O. 4173.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures to the value of twenty-seven lakhs and fifty thousand rupees, to be issued by the Jammu and Kashmir State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 40/75-Stamps/F. No. 471/65/75-Cus. VII]

आदेश

क्र.आ. 4174.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस शुल्क से, जो गुजरात राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले चार सौ चालीस लाख रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[संख्या 41/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/46/75-सीमा-शुल्क 7]

डी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4174.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of four hundred and forty lakhs of rupees to be issued by the Gujarat State Financial Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 41/75-Stamps/F. No. 471/46/75-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Ninth Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (2) of rule 6 rule of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the pension sanctioning authority, before passing any final order regarding reduction in the amount of pension, or gratuity, or both, shall serve upon the person concerned a notice specifying the reduction proposed to be made in such amount and the grounds therefore, and call upon such person to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time as may be allowed by

that authority, such representation as such person may wish to make against the proposed reduction and take into consideration the representation, if any, submitted by such person before passing the final order."

[No. F.5(3)-EV(A)/72]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, 30 जनवरी, 1975

का० प्रा० 4176.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का सं० 46) की धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसरण में रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति को गैर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये विकासोन्मुख डिजाइन "नियोजित परिवार—सब के लिये धन" के उत्कीर्णन सहित 50 रुपये 10 रुपये और 10 पैसे के मूल्यवर्ग के सिक्कों के रूप में मुद्रा भारत से बाहर ले जाने अथवा भेजने की अनुमति देता है:

परंतु भेंट देने (अर्थात् गैर व्यावसायिक प्रयोजनों) के लिये भारत से बाहर भेजे जानेवाले प्रत्येक मूल्यवर्ग के सिक्कों की संख्या किसी भी समय दो से अधिक न हो;

परंतु प्रागे यह भी कि उपहार देने के प्रयोजन के लिये भारत से बाहर सिक्के ले जाने के दृष्टिकोण यात्रियों के मामले में सिक्कों की संख्या 50 रुपये और 10 रुपये के प्रत्येक मूल्य वर्ग के 2 सिक्कों से अधिक न हो;

परंतु यह भी कि जब सिक्के भारत से बाहर भेजे जाते हैं तब उन्हें भेजने वाला व्यक्ति—

(क) जब सिक्के वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से भेजे जाते हों तब हवाई परतन अथवा बंदरगाह के सीमा शुल्क प्राधिकारियों,

(ख) जब सिक्के डाक से भेजे जाते हैं तब डाक प्राधिकारियों, को लिखित रूप में यह घोषणा देना है कि भेजे जाने वाले सिक्कों की संख्या और प्रकार इस अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप हैं।

व्याख्या: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये विकासोन्मुख डिजाइन वाले सिक्के का अर्थ ऐसा सिक्का है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1974 को विषम जनसंख्या वर्ष मनाये जाने के लिये विकासोन्मुख डिजाइन सहित जारी किया गया हो।

[सं० एफ० ई० आर० ए० 24/75-आर० बी]

एस० एम० शिरालकर, उप-नायक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Central Office.

Bombay, the 30th January, 1975

S.O. 4176.—In pursuance of sub-section (2) of section 13 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, (No. 46 of 1973) the Reserve Bank is pleased to permit any person to take or send out of India for non-commercial purposes currency in the form of Development Oriented Design Coins with the inscription of "Planned Families—Food for All" of denominations of Rs. 50, Rs. 10 and 10 Paise:

Provided that the number of coins of each denomination sent out of India for making gifts (i.e. non-commercial purposes) does not at any one time exceed two;

Provided further that in case of passengers desirous of taking out of India for purposes of presentation, the number of coins does not exceed 2 coins each of denominations of Rs. 50 and Rs. 10;

Provided also that where the coins are being sent out of India, the person sending them out furnishes a declaration in writing that the number and kind of coins sent are in conformity with the requirements of this notification, to—

(a) the customs authorities at the air or sea port, where the coins are sent out by air or sea;

(b) the postal authorities, where the coins are despatched by post.

Explanation: For purposes of this Notification, "Development Oriented Design Coin" means a coin bearing a development oriented design issued to mark the year 1974 as World Population year by the United Nations.

[No. F.E.R.-A 24/75-R.B.]

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी 1975

का० प्रा० 4177.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये, सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में, उन्हें सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग तथा सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

तालिका

अधिकारी का पद	सरकारी स्थान के वर्ग तथा कार्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
1	2
क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली।	पंजाब नेशनल बैंक के या उसकी ओर से किराये पर लिये गये या इसके द्वारा अधिगृहीत वे स्थान जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, बंबई क्षेत्र, बंबई।	पंजाब नेशनल बैंक के या उसकी ओर से किराये पर लिये गये या इसके द्वारा अधिगृहीत वे स्थान जो बंबई के महानगरीय शहर के भीतर पड़ते हैं।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कलकत्ता क्षेत्र, कलकत्ता।	पंजाब नेशनल बैंक के या उसकी ओर से किराये पर लिये गये या इसके द्वारा अधिगृहीत वे स्थान जो कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में स्थित हैं।

[सं० 7(9)बी० प्रो० III/74]

मे० सा० उमगावकर, अधीक्षक सचिव

Department of Banking

(1)

(2)

New Delhi, the 20th August, 1975

S.O. 4177.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)

The Regional Manager, Punjab National Bank, Delhi Region, Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab Na-
--	--

The Regional Manager, Punjab National Bank, Bombay Region, Bombay.

tional Bank and situated within the local limits of the Union Territory of Delhi.

Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab National Bank within the metropolitan city of Bombay.

The Regional Manager, Punjab National Bank, Calcutta Region, Calcutta.

Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab National Bank and situated within the metropolitan city of Calcutta.

[No. 7(9)BO.III/74]

M.B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 1975

का० प्रा० 4178.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अगस्त 1975 के दिनांक 29 को समाप्त हुए सप्ताह के लिये खेबा इन विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	29,84,12,000		सोने का सिक्का और मुलियन:—		
संचलन में नोट	6205,77,05 000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,58,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
जारी किये गये कुल नोट		6235,61,17,000	विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,55,000
			रुपये का सिक्का		15,95,40,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	...	5915,39,22,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे बाणिज्य पत्र		...
कुल देयताएं		6235,61,17,000	कुल आस्तियां		6235,61,17,000

दिनांक : 3 सितंबर, 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर

29 अगस्त 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	29,84,12,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,70,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	5,06,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	42,16,38,000
(स्विकरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	...
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	933,79,30,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	603,36,34,000
जमा राशियां:—		निर्भर**	687,99,24,000

देयताएं	रुपये	अस्तित्व	रुपये
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम:--	
(i) केन्द्रीय सरकार	52,28,35,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	---
(ii) राज्य सरकारें	10,90,89,000	(ii) राज्य सरकारों को †	94,15,41,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:--	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	577,52,32,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को @	37,27,35,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,43,57,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को @@	305,63,58,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,48,76,000	(iii) दूसरों को	9,83,36,000
(iv) अन्य बैंक	77,36,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:--	
		(i) राज्य सरकारों को	69,63,80,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,54,14,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	---
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	87,20,00,000
(ग) अन्य	1135,93,26,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
वैय बिल	163,96,73,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
अन्य देयताएं	706,54,05,000	राज्य सहकारी बैंकों को कृ ण और अग्रिम	93,26,14,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	320,98,06,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	---
		अन्य अस्तित्व	347,50,18,000
रुपये	3685,85,29,000	रुपये	3685,85,29,000

*नकदी, आवधिक जमा और प्रत्यकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं।

@भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम किये गये 23,92,00,000/- रुपये शामिल हैं।

@@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

दिनांक: 3 सितंबर, 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर
[सं० फ० 10(1)/75-बी० आ० I]
ए० व० मोरचन्दानी, अवर सचिव

S.O. 4178.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 29th day of August 1975
ISSUE DEPARTMENT
New Delhi, the 6th September, 1975

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	29,84,12,000		Gold Coin and Bullion :--		
Notes in circulation	6205,77,05,000		(a) Held in India	182,52,58,000	
Total notes issued		6235,61,17,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,55,000
			Rupee Coin		15,95,40,000
			Government of India Rupee Securities		5915,39,22,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
Total liabilities		6235,61,17,000	Total Assets		6235,61,17,000

K. R. PURI, Governor

Dated the 3rd day of September, 1975.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 29th August, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	29,84,12,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,70,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	5,06,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund .	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	42,16,38,000
Deposits :—		(b) External
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	933,79,30,000
(i) Central Government	52,28,35,000	Balances Held Abroad*	603,36,34,000
(ii) State Governments	10,90,89,000	Investments**	687,99,24,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	577,52,32,000	(i) Central Government
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,43,57,000	(ii) State Governments†	94,15,41,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,48,76,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	77,36,000	(i) Scheduled Commercial Banks@	37,27,35,000
(c) Others	1135,93,26,000	(ii) State Co-operative Banks@ @	305,63,58,000
Bills Payable	163,96,73,000	(iii) Others	9,83,36,000
Other Liabilities	706,54,05,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	69,63,80,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,54,14,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
		(b) Investments in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	93,26,14,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	320,98,06,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
		Other Assets	347,50,18,000
Rupees	3685,85,29,000	Rupees	3685,85,29,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

@Includes Rs. 23,92,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 3rd day of September, 1975.

K.R. PURI, Governor.

[F. No. 10/1/75-BO-I]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

भुवनेश्वर, 24 जुलाई, 1975

का० प्रा० 4179.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का सदुपयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, भुवनेश्वर, के उपसमाहर्ता को समाहर्ता के अधिकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 173 जी (4), के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 1/1975—सी० सं० IV (4) 2-सीई/72]

Collector of Central Excise, Customs

Central Excise

Bhubaneswar, the 24th July, 1975

S.O. 4179.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise in the Collectorate of Central Excise & Customs, Bhubaneswar, to exercise the powers of Collector under rule 173-G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[Notification No. 1/1975—C. No. LV(4)2-CE/72]

कलकत्ता, 24 जुलाई, 1975

का० प्रा० 4180.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का सदुपयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता के उप समाहर्ताओं को अपनी सीमा के अधीन समाहर्ता के अधिकार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944 नियम 173 जी (4), के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 2/1975—सी सं० IV (8) 2-सीई/72]

एच० एल० बनर्जी, समाहर्ता

Calcutta, the 24th July, 1975

S.O. 4180.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collectors of Central Excise in the Collectorate of Central Excise, Calcutta to exercise the powers of Collector under rule 173G(4) of the Central Excise Rules, 1944 in their respective jurisdiction.

[Notification No. 2/1975—C. No. IV(8)2-CE/72]

H. L. BANERJEE, Collector

मदुरै, 25 जुलाई, 1975

का० प्रा० 4181.—1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस कार्यालय की दिनांक 23-9-71 की अधिसूचना (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सी० सं० IV/16/83/71 में प्राथमिक संशोधन करते हुए, मैं एतद्द्वारा, उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मदुरै को 1944 की केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क नियमावली के 173 जी (4) नियम के अधीन (स्व० नि० पर नि० का० के अधीन काम करने वाले) अभिनियमिताओं को आर० जी० I प्ररूप में लेखे रखने से छूट देने और इन लेखों के स्थान पर अभिनियमिताओं के निजी लेखों की स्वीकार करने से सम्बन्धित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूँ।

प्राधिकार: दिनांक 5-7-75 का बोर्ड पत्र का० सं० 215/5/74-के० उ० 6

[प्रधिसूचना सं० 2/75-सी० सं० IV/16/55/75-के० उत्पा०-2]

एम० एस० सुब्रामनियम, समाहर्ता

THE CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Central Excises

Madurai, the 25th July, 1975

S.O. 4181.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in partial modification of this Office Notification (Central Excises) C. No. IV/16/83/71 dated 23-9-1971, I hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise, Madurai, to exercise the powers of Collector under Rule 173G(4) of Central Excise Rules, 1944, and to exempt any manufacturer from maintaining accounts in Form RG 1 (for assesses working under SRP) and to accept the private Accounts of the manufacturer in lieu thereof.

Authority: Board's letter F. No. 215/5/74-CX. 6 dated 5-7-1975.

[Notification No. 2/75—C. No. IV/16/75 CX. 2]

M. S. SUBRAMANYAM, Collector

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बंगलूर, 2 अगस्त, 1975]

का० प्रा० 4182.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, इस समाहर्तालय के अधीनस्थों को, उक्त नियमावली के 96-घ और 96-ङ नियमों के अधीन सूती कपड़ों/सूती यार्न को एक कारखाने से दूसरे कारखाने में ले जाने के लिये बी-5 (प्ररूप में) सामान्य बन्ध पत्रों की स्वीकार करने से सम्बन्धित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 3/75-सी सं०-8/1/75-ख-2]

ई० आर० श्रीकन्टिया, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Bangalore, the 2nd August, 1975

S.O. 4182.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules 1944, I hereby empower the Superintendents of Central Excise in this Collectorate to accept B-5 General Bonds for the purpose of movement of Cotton Fabrics/Cotton yarn from one factory to another under Rules 96D and 96E of Central Excise, Rules, 1944.

[Notification No. 3/75—C. No. IV/8/1/75 B. 2]

E. R. SRIKANTIA, Collector

कार्यालय आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश

भोपाल, 3 सितम्बर, 1975

क्रा० प्रा० 4183. — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन दिनांक 31-3-1975 तक के व्यक्तिगत व्यक्तियों की सूची भाग 'घ' के लिये (i)-नी माह से अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि एक वर्ष तीन माह से अधिक न हुई हो, भाग 'घ' के लिये (ii) एक वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि दो वर्ष तीन माह से अधिक न हो, भाग 'स' के लिये (iii)-दो वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम और (iv)-भुगतान न की गई कुल रकम के लिये है।

अनुसूची

क्रमांक	निर्धारितियों के नाम और पूरा पता	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	मे० रामदीन सिंह चौहान एंड कं०, छुविया	1,56,746	—	25,942	182,688
2.	श्री ए० ए० पटेल, इंदौर	5,429	46,919	—	50,348
3.	श्री एम० एम० भंडारी, इंदौर	211	1,684	142,527	144,422
4.	श्री हुकमीचन्द चिमनलाल, इंदौर	121	76	599,944	560,141
5.	श्री मंगलचन्द चिमनलाल, इंदौर	121	76	554,541	554,738
6.	मे० स्वयम्भरलाल मोटर सर्विस (प्रा०) लि० इंदौर	1,468	59,560	—	61,028
7.	श्री सगरमल स्पि० ए० बीव, सिहस लि०, इंदौर	7,310	10,055	102,674	120,039
8.	श्री कबीर अहमद हाजी अब्दुल करीम, भोपाल	25,494	5,656	46,567	77,717
9.	श्री अब्दुल करीम प्रोप० आफ करीम, भोपाल	8,478	3,000	25,133	36,611
10.	श्री अहमद नाथू प्राप० आफ करीम, भोपाल	8,211	2,832	25,952	36,995
11.	श्री कबीर अहमद प्रा० आफ करीम, भोपाल	7,893	2,772	20,427	31,092
12.	श्री रोककसिंह नानकसिंह, इंदौर	—	60,465	—	60,465
13.	मे० यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लि०, ग्वालियर	—	—	100,465	100,465
14.	मे० एस० पी० आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०, ग्वालियर	—	—	74,266	74,266
15.	मे० सरदार सिंह अमरसिंह, डिमरनी	—	—	633,810	633,810
16.	श्री गुलाबचंद यादव, एस० ई० एस० कान्फेक्टर, पचमडी	—	—	122,414	122,414
17.	श्री बलवंतसिंह एंड संस, बैतूल	—	—	452,594	452,594
18.	श्री हरजेंद्रसिंह करतारसिंह, बैतूल	—	—	48,078	48,078
19.	मे० जियालाल श्यामलाल, बैतूल	—	47,212	99,145	146,357
20.	श्री जयवंतसिंह मेहरसिंह, बोरकेही सेह० मुलताई बैतूल	—	—	49,526	49,526
21.	मे० किशनसहाय कुंदनलाल, घोड़ाडोगरी, जिला बैतूल	—	—	68,575	68,575
22.	मे० करमसिंह अतरसिंह, घोड़ाडोगरी जिला बैतूल	—	—	166,813	166,813
23.	मे० किशनसहाय भागीरथ, घोड़ाडोगरी, जिला बैतूल	—	—	45,012	45,012
24.	श्री कन्हैयालाल शोभाराम मेहतो, जुवाड़ी, पो० प्रा० घोड़ाडोगरी जिला बैतूल	—	—	28,689	28,689
25.	श्री करमसिंह अतरसिंह, बैतूल	—	—	34,968	34,968
26.	श्री मोतीलाल मेहतो, जुवाड़ी घोड़ाडोगरी	—	—	55,764	55,764
27.	मे० पटेल मोतीलाल मेहसी एंड कं०, जुवाड़ी घोड़ाडोगरी	—	—	2,02,700	202,700
28.	श्री रामसिंह केशरसिंह, घोड़ाडोगरी	—	—	30,164	30,164
29.	श्री ज्वालासिंह लधासिंह, सोहागपुर	—	—	49,484	49,484
30.	श्री खंदनमल, गंज बैतूल	—	—	37,956	37,956
31.	मे० बालसा जूनेजा टिम्बर ट्रेडिंग कं०, गु० नो० टि० मा०, इंदौर प्रोप० वारसिंह त्रिलोकिकसिंह	—	—	28,912	28,912
32.	श्री ब्रह्मनारायण रामेश्वर, इंदौर	—	—	3,47,532	3,47,532
33.	श्री जी० पुष्पतिनाथ, सियागंज, इंदौर	—	—	43,320	43,320
34.	मे० मंगलचंद हुकमीचंद, इंदौर	—	—	3,47,279	3,74,279
35.	मे० महादेव होजरी (प्रा०) लिमि०, (फैक्ट्री), इंदौर	—	—	1,03,195	1,02,195
36.	श्री प्रोकरलाल मिश्रलाल, मंवेसौर	—	—	6,56,104	6,56,104

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, M.P.

Bhopal, the 3rd Sept. 1975

S.O. 4183.—List of defaulters as on 31-3-1975 u/s 287 of the I.T. Act, 1961(i) is for Part 'A'—Amount in default for periods exceeding nine months but not exceeding one year and three months; (ii) for Part 'B'—Amount in default for periods of one year and three months and above but not exceeding two years and three months; (iii) for Part 'C'—Amount in default of two years and three months and above and (iv)—for Total amount in default.

SCHEDULE

S. No.	Name of the assessee and full address	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	M/s. Ramding Singh Chauhan & Co. Chudia	1,56,746	..	25,942	182,688
2.	Shri A.A. Patel, Indore	3,429	46,919	..	50,348
3.	Shri N.M. Bhandari, Indore	211	1,684	142,527	144,422
4.	Shri Hukamchand Chimanlal, Indore	121	76	559,944	560,141
5.	Shri Mangalchand Chimanlal, Indore	121	76	554,541	554,738
6.	M/s. Swayamberlal Motor Service (P) Ltd., Indore	1,468	59,560	..	61,028
7.	M/s. Sagarmal Spg. & Wvg. Mills Ltd. Indore	7,310	10,055	102,674	120,039
8.	M/s. Kabir Ahmed Hazi Abdul Karim Bhopal	25,494	5,656	46,567	77,717
9.	Shri Abdul Karim P/O above	8,478	3,000	25,133	36,611
10.	Shri Ahmed Nathu P/O above	8,211	2,832	25,952	36,995
11.	Shri Kabir Ahmed P/O above	7,893	2,772	20,427	31,092
12.	Shri Ronaksing Nanaksingh, Indore	60,465	..	60,465
13.	M/s. United Transport Pvt. Ltd., Gwalior	100,465	100,465
14.	M/s. M.P. Automobiles (P) Ltd., Gwalior	74,266	74,266
15.	M/s. Sardarsingh Amarsingh, Timarni	633,810	633,810
16.	Shri Gulabchand Yadav, M.E.S. Contractor, Pachmar, Itarsi	122,414	122,414
17.	Shri Balwant Singh & Sons, Betul	452,594	452,594
18.	Shri Harjendar Singh Kartar Singh, Betul	48,078	48,078
19.	M/s. Jiyalal Shyamlal, Betul	47,212	99,145	146,357
20.	Shri Jaswant Singh Mehar Singh, Borkehi, Teh. Multai, Betul	49,526	49,526
21.	M/s. Kishan Sahay Kundanlal, Ghoradongri	68,575	68,575
22.	M/s. Karam Singh Attar Singh Ghoradongri	166,813	166,813
23.	M/s. Kishan Sahay Bhagirath, Ghoradongri	45,012	45,012
24.	M/s. Kanhiyalal Sobaram Mehto, Juwadi P.O. Ghoradongri, Betul	28,689	28,689
25.	Shri Karam Singh Attarsingh, Betul	34,968	34,968
26.	Shri Motilal Mehto, Juwadi, Ghoradongri	55,764	55,764
27.	M/s. Patel Moti Lal Mehto & Co., Juwadi, Ghoradongri	2,02,700	202,700
28.	Shri Ram Singh Keshar Singh, Ghoradongri	30,164	30,164
29.	Shri Jawala Singh Ladha Singh, Sohagpur	49,474	49,484
30.	Shri Chandanmal, Ganj, Betul	37,956	37,956
31.	M/s. Khalsa Juneja Timber Trading Co., Indore Prop. : Darsingh Trilok-singh	28,912	28,912
32.	Shri Badrinarayan Rameshwar, Indore	3,47,532	3,47,532
33.	Shri G. Pushpathinath, Siyaganj, Indore	43,320	43,320
34.	M/s. Mangalchand Hukamichand, Indore	3,74,279	3,74,279
35.	M/s. Mahadeo Hosiery Pvt. Ltd., Indore	1,03,195	1,03,195
36.	Shri Onkarlal Mishrilal, Mandsaur	6,56,104	6,56,104

कां० 4184.—घायकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन दिनांक 31-3-1974 तक के व्यक्तिकी व्यक्तियों की सूची, भाग 'ज' के लिये (i)-नी माह से अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि एक वर्ष तीन माह से अधिक न हुई हो; भाग 'ब' के लिये (ii) एक वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि दो वर्ष तीन माह से अधिक न हो; भाग 'स' के लिये (iii)-दो वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम (iv) और भुगतान न की गई कुल रकम के लिये है।

अनुसूची

क्रमांक	निर्धारितियों के नाम और पूरा पता	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	मे० स्वयम्भरलाल मोटर सर्विस प्राय० लि०, इंदौर	59,560	--	--	59,560
2.	,, सगरमल स्पि०एण्ड वीवि० मिल्स लि०, इंदौर	10,055		1,02,674	1,12,729
3.	श्री रोनकसिंह नारायणसिंह, इंदौर	60,465	-	--	60,465
4.	,, ए०ए० पटेल, इंदौर	81,208	--	--	81,208
5.	,, एन० एम० मशानी, इंदौर	1,684	--	1,42,527	1,44,211
6.	मे० जियालाल श्याम लाल, बैतूल	47,212		2,08,466	2,55,678
7.	,, एस०के० शेष रसूल मोटर ट्रांसपोर्ट क० प्रा० लि०, जबलपुर	68,498	73,960	2,62,949	3,05,407
8.	,, हीरजी कल्याणजी जासानी, राजनाथगाव	27,640		73,643	1,01,283
9.	,, मदनलाल शंकरलाल, बारासिखी	600	27,443	51,289	79,332
10.	,, प्रभुदयाल पतिराम, रायपुर	58,680		3,62,166	4,20,846
11.	,, पीलालाल बैनराम, दुर्ग	6,907	88,565	707	94,197
12.	,, पालुराम घनानिया, रायगढ़	86,975		4,19,297	536,272
13.	,, रामचंद्र भूरा, सिवनी	1,587	17,014	--	18,601
14.	,, सुदर्शन ट्रांसपोर्ट प्राय० लि०, बिलामपुर	58,680		1,51,469	2,10,149
15.	श्री हुकमोच्चन्द विमललाल, इंदौर	-	2,742	5,57,202	5,59,944
16.	मे० अमरसिंह संतकुमार, जबलपुर	-	40,434		40,434
17.	,, हरबन्ससिंह मानिक, जबलपुर		90,520		90,520
18.	,, श्यामनारायण त्रिबेदी, जबलपुर		60,259	-	60,259
19.	एस० बहादुरसिंह, मोटर स्टैंड, जबलपुर		1,56,748	47,598	2,04,346
20.	मे० पुरुषोत्तमवास मोवा, रायगढ़		32,585	2,466,691	24,99,276
21.	,, सोहनलाल सुरेशचन्द्र, भाटापारा		4,680	1,21,791	1,26,471
22.	श्री बघीनारायण रामेश्वर, इंदौर			3,47,532	3,47,532
23.	,, मंगलचन्द विमललाल, इंदौर			3,94,055	3,94,055
24.	मे० महादेव होजरी क०, इंदौर			1,05,606	1,05,606
25.	,, मंगलचन्द हुकमोच्चन्द, इंदौर			3,60,759	3,60,759
26.	श्री पाशुपतिनाथ, इंदौर			43,320	43,320
27.	,, ओकरलाल मिश्रीलाल, मयसौर			8,56,104	6,56,104
28.	मे० यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, ग्वालियर (प्रा०) लि०, ग्वालियर			1,00,465	1,00,465
29.	,, एम० पी० फाटोमोबाइल (प्रा०) लि०, ग्वालियर			49,162	49,162
30.	श्री मजूर हुसैन, प्रो० साधना ट्रेडर्स, भोपाल			4,01,872	4,01,872
31.	मे० न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लि०, भोपाल			12,55,653	12,55,653
32.	,, भोपाल टेक्सटाइल्स लि०, भोपाल			2,78,022	2,78,022
33.	मे० सरदारसिंह अमरसिंह, डिमरली			6,33,810	6,33,810
34.	श्री गुलाबचन्द यादव, पंचमढ़ी			1,39,640	1,39,640
35.	मे० ज्वालासिंह लघामिह, मुहानपुर			56,348	56,348
36.	,, बलबन्तसिंह एन्ड संस, बैतूल			3,22,644	3,22,644
37.	श्री चांदमल, बैतूल			37,956	37,956
38.	,, धनवीरसिंह किशनलाल, फारेस्ट कान्ट्रैक्टर, षोडाडोगरी			96,107	96,107
39.	मे० जियालाल श्याम लाल, बैतूल			2,08,466	2,08,466
40.	श्री जसबन्तसिंह मेहरसिंह, वरदेही, मेह० मुलसाई जिला बैतूल			49,526	49,526
41.	मे० किशन सहाय किशनलाल, षोडाडोगरी			68,575	68,575
42.	,, करमसिंह अमरसिंह, षोडाडोगरी	--	--	1,66,813	1,66,813
43.	,, केशव सहाय भागीरथ, षोडाडोगरी	--	--	45,022	45,022

44. श्री कन्हैयालाल शोभाराम मेहता, जूबाड़ी, धोडाडोगरी	--	--	28,689	28,689
45. ,, करतारसिंह अतरसिंह, बैतुल	--	--	34,968	34,968
46. ,, मोतीलाल मेहता, एंड कं० बैतुल	--	--	55,764	55,764
47. मे० पटेल मोतीलाल मेहता, एंड कं०, बैतुल	--	--	2,02,700	2,02,700
48. श्री रामसिंह केसरसिंह, धोडाडोगरी	--	--	55,164	55,164
49. मे० रामधु सिंह जगन्नाथ, एंड कं० गुडिया, पो० आ० छिछोली, बैतुल	--	--	25,942	25,942
50. ,, खालसा जुनेजा, टिम्बर ट्रेडिंग, कं०, गु०ना०टि०भा० हंदौर, प्रोप० वरसिंह त्रिलोकसिंह	--	--	28,912	28,912
51. नव भारत कन्स्ट्रक्शन कं०, जबलपुर	--	--	41,858	41,858
52. जगदीश कुमार अर्जुनभाई	--	--	32,520	32,520
53. श्री मोतीलाल चावला द्वारा एम० आर० चावला जबलपुर	--	--	35,863	35,863
54. अन्बुलकरीम अन्बुलशकर, जबलपुर	--	--	1,17,938	1,17,938
55. मे० मेहताब सिंह, एंड संस, जबलपुर	--	--	52,173	52,173
56. श्री धरमदास अग्रवाल, प्रो० रामशरण नाथूला (हि०स०प०) कटनी	--	--	2,56,926	2,56,926
57. ,, अमृतलाल अनन्द, रावपुर	--	--	1,02,948	1,02,948
58. ,, बी०एल० गुप्ता, दुर्ग	--	--	69,779	69,779
59. मे० गुप्ता, कन्स्ट्रक्शन कं०, दुर्ग	--	--	58,838	58,838
60. ,, केमरीलाल एंड कं०, रायपुर	--	--	27,875	27,875
61. ,, शिवनारायण प्रभुबयाल, सिवनी	--	--	6,32,381	6,32,381
62. ,, श्याम सिंह एंड संस, राजनाथगढ़	--	--	85,325	85,325
63. श्री शिवभाई, द्वारा मे० राजेन्द्र टिम्बर, कं०, रायपुर	--	--	37,238	37,238
64. ,, उद्यमीराम रामस्वरूप, रायगढ़	--	--	2,07,124	2,07,124
65. ,, हरजेन्द्रसिंह करतारसिंह, बैतुल	--	--	48,078	58,078

[क्रमांक सी० एम० 10/74/75 दि० आ०शा०]

के० जगन्नाथन, धायुक्त

S.O. 4184.—List of defaulters as on 31-3-1975 u/s. 287 of the I. T. Act, 1961 (i) is for Part 'A' —Amount in default for periods exceeding nine months but not exceeding one year & three months (ii) for Part 'B' —Amount in default for periods of one year and three months & above but not exceeding two years and three months; (iii) for Part 'C' —Amount in default of two years and three months & above and (iv) for Total amount in default.

SCHEDULE

S. No.	Name of assessee and full address	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	2	3	4	5	6
1.	M/s. Swyamberlal Motor Service Pvt. Ltd. Indore	59,560	59,560
2.	M/s. Sagarmal Spg. & Wvg. Mills, Indore	10,055	..	1,02,674	1,12,729
3.	Shri Ronak Singh Narainsingh, Indore	60,465	60,465
4.	Shri A.A. Patel, Indore	81,208	81,208
5.	Shri N.M. Bhandari, Indore	1,684	..	1,42,527	144,211
6.	M/s. Jiyalal Shyamlal, Betul	47,221	..	2,08,466	255,678
7.	M/s. S.K. Sheikh Rasool Motor Transport Co. Pvt. Ltd., Jabalpur	68,498	73,960	2,62,949	305,407
8.	M/s. Hirji Kalyanji Jassani, Rajnandgaon	27,640	..	73,643	101,283
9.	M/s. Madanlal Shankarlal, Warasconi	600	27,443	51,289	79,332
10.	M/s. Prabhudayal Patiram, Raipur	58,680	..	3,62,166	420,846
11.	M/s. Pilalal Chaitram, Durg	6,907	86,565	707	94,197
12.	M/s. Paluram Dhanania, Raigarh	86,975	..	4,49,297	536,272
13.	M/s. Ramchand Bhura, Seoni	1,587	17,014	..	18,601
14.	M/s. Sudarshan Transport Pvt. Ltd. Bilaspur	58,680	..	1,51,469	210,149
15.	Shri Hukmichand Chimanlal, Indore	..	2,742	5,57,202	559,944
16.	M/s. Amarsingh Sant Kumar, Jabalpur	..	40,434	..	40,434
17.	M/s. Harbanssingh Manik, Jabalpur	..	90,520	..	90,520
18.	M/s. Shyam Narayan Trivedi, Jabalpur	..	60,259	..	60,259
19.	S. Bahadur Singh, Motor Stand, Jabalpur	..	1,56,748	47,598	204,346

1	2	3	4	5	6
20.	M/s. Pureshotamdas Moda, Raigarh	..	32,585	24,66,691	24,99,276
21.	M/s. Sohanlal Sureshchand, Bhatapara	..	4,680	1,21,791	1,26,471
22.	Shri Badrinarayan Rameshwar, Indore	3,47,532	3,47,532
23.	Shri Mangalchand Chimanlal, Indore	3,94,055	3,94,055
24.	M/s. Mahadeo Hosiery Factory, Indore	1,05,606	1,05,606
25.	M/s. Mangalchand Hukmichand Indore	3,60,759	3,60,759
26.	Shri G. Pashupatinath, Indore	43,320	43,320
27.	Shri Onkarlal Mishrilal, Mandasaur	6,56,104	6,56,104
28.	M/s. United Transport Gwalior (P) Ltd., Gwalior	1,00,465	1,00,465
29.	M/s. M.P. Automobiles (P) Ltd., Gwalior	49,162	49,162
30.	Sati Manzoor Hussain Prop : Sadhna Traders, Bhopal	4,01,872	4,01,872
31.	M/s. New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal	12,55,653	12,55,653
32.	M/s. Bhopal Textiles Ltd., Bhopal	2,78,022	2,78,022
33.	M/s. Sardarsingh Amarsingh, Timarni	6,33,810	6,33,810
34.	Shri Gulabchand Yadav, Pachmarhi	1,39,640	1,39,640
35.	M/s. Jawalal Singh Ladha Singh, Sohagpur	56,348	56,348
36.	M/s. Balwant Singh & Sons, Betul	3,22,644	3,22,644
37.	Shri Chandmal, Betul	37,956	37,956
38.	Shri Dhanvirsingh Kishanlal, Forest Contractor, Ghoradongri	96,107	96,107
39.	M/s. Jiyalal Shyamlal, Betul	2,08,466	2,08,466
40.	Shri Jaswant Singh Mehar Singh, Bardehi, Teh. Multani, Betul	49,526	49,526
41.	M/s. Kishan Sahaya Kishanlal, Ghoradongri	68,575	68,575
42.	M/s. Karam Singh Attarsingh, Ghoradongri	1,66,813	1,66,813
43.	M/s. Keshav Sahaya Bhagirath, Ghoradongri	45,022	45,022
44.	Shri Kanhiyalal Shobharam Mehto, Juwadi, Ghoradongri	28,689	28,689
45.	Shri Kartarsingh Attarsingh, Betul	34,968	34,968
46.	Shri Motilal Mehto & Co., Betul	55,764	55,764
47.	M/s. Patel Motilal Mehto & Co., Betul	2,02,700	2,02,700
48.	Shri Ramsingh Kesharsingh, Ghoradongri	55,164	55,164
49.	M/s. Ramdhusingh Jagannath Singh & Co., Gudia, P.O. Chicholi, Betul	25,942	25,942
50.	M/s. Khalsa Juneja Timber Trading Co., GNTM, Indore Prop : Darsingh Trilok-singh	28,912	28,912
51.	Nav Bharat Const. Co., Jabalpur	41,858	41,858
52.	Jagdish Kumar Chaturbhujbhai, Jabalpur	32,520	32,520
53.	Shri Motilal Chawla C/o M.R. Chawla, Jabalpur	35,863	35,863
54.	Shri Abdul Karim Abdul Shakoor, Jabalpur	1,17,938	1,17,938
55.	M/s. Mehtab Singh & Sons, Jabalpur	52,173	52,173
56.	Shri Dharamdas Agarwal Prop : Ramsaran Nathulal (HUF), Katni	2,56,926	2,56,926
57.	Shri Amritlal Anand, Raipur	1,02,948	1,02,948
58.	Shri B.L. Gupta, Durg	69,779	69,779
59.	M/s. Gupta Construction Co., Durg	58,838	58,839
60.	M/s. Konriwal & Bros, Raipur	27,875	27,875
61.	M/s. Shivanarain Prabhudayal, Seoni	6,32,381	6,32,381
62.	M/s. Shyamsingh & Sons, Rajnandgaon	85,325	85,325
63.	Shri Shivbhai C/o M/s. Rajendra Timber Co., Raipur	37,238	37,238
64.	Shri Udmiram Ramswaroop, Raigarh	2,07,124	2,07,124
65.	Shri Harjinder Singh Kartar Singh, Betul	48,078	48,078

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आवेश

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

का०प्र० 4185.—सर्वश्री इन्चेक टायर्स लि० कलकत्ता के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को 12,00,000 रुपये (बारह लाख रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/बी०/1401467 दिनांक 27-7-1974 इससे संलग्न सूची के अनुसार कच्ची सामग्री/संघटकों के आयात के लिए प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने (सर्वश्री इन्चेक टायर्स लि०, कलकत्ता) उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई है या अस्थायित्व हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस पर 9,45,883 रुपये (नौ लाख पैंतालिस हजार आठ सौ तिरासी रुपये मात्र) का उपयोग करना बाकी था। लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत कराया गया था।

3. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी०/बी०/1401467 दिनांक 27-7-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है या अस्थायित्व हो गई है और निवेश देता है कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति भ्रम से जारी की जा रही है।

[संख्या रज० 22/4/73-74/प्रार०एस-2]

आई०बी० चुनकत, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 11th September, 1975

S.O. 4185.—M/s. State Trading Corporation of India Ltd, New Delhi, were granted Import Licence No. P/D/1401467 dated 27-7-1974, with Letter of Authority in favour of M/s. Incheck Tyres Ltd., Calcutta, for import of Raw Materials/Components as per list attached to it valued at Rs. 12,00,000 (Rs. Twelve Lakhs only).

2. They (M/S. Incheck Tyres Ltd., Calcutta) have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an un-utilized balance of Rs. 9,45,883/-. (Rs. Nine lakhs forty-five thousand eight hundred and eighty only). The licence was registered with Customs House, Bombay.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs purposes Copy of Import Licence No. P/D/1401467 dt. 27-7-1974 has been lost or misplaced and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Rubber/22/4/73-74/RM II]

I. V. CUNKATH, Dy. Chief Controller

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आवेश

अहमदाबाद, 11 सितम्बर, 1974

का०प्र० 4186.—सर्वश्री केमो क्राफ्ट, पछाली गोलवाड, बिल्लीमोरा को ईथिल ग्राफीसोपिल एमिनोडायजो बेंजीन क्लोरोसिनकेट आदि के आयात के लिए लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253, दिनांक 16-9-74 मूल्य 26037 रु० (छब्बीस हजार सैंतीस रुपये मात्र), पी०/एस०/1403254, दिनांक 16-9-74 मूल्य 13018 रुपये (तेरह हजार अठ्ठारह रुपये मात्र) एवं पी०/एस०/1403255, दिनांक 16-9-74 मूल्य 13018 रुपये (तेरह हजार अठ्ठारह रुपये मात्र) स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253, दिनांक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति), पी०/एस०/1403254, दिनांक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां) एवं पी०/एस०/1403255, दिनांक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंसों की मूल प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई हैं।

अपने दायरे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253 एवं पी०/एस०/1403255 दोनों का दिनांक 16-9-74 है की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एवं लाख सैंत संख्या : पी०/एस०/1403254, दिनांक 16-9-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क प्रतियां खो गई हैं और निवेश देता हूँ कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253 एवं पी०/एस०/1403255 दोनों का दिनांक 16-9-74 है, की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एवं लाख-सैंत संख्या : पी०/एस०/1403254, दिनांक 16-9-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[सं० 1653/एन यू/4338/पी 33/ए एम-74/एस एस आई]

डी० डिसूजा, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy-Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Ahmedabad, the 11th September, 1974

S.O. 4186.—M/s. Kemo Kraft, Pachhali Golwad, Billimora has been granted Import licence No. P/S/1403253 dated 16-9-74 for Rs. 26037/-(Rs. Twenty Six thousand and thirty seven only), P/S/1403254 dated 16-9-74 for Rs. 13018/-(Rs. Thirteen thousand and eighteen only) and P/S/1403255 dated 16-9-74 for Rs. 13018/-(Rs. Thirteen thousand and eighteen only) for item Ethyl Oxyethyl Aminodiaz benzene Chlorozincate etc.

They have applied for duplicate copies of licene No. P/S/1403253 dt. 16-9-74 (Custom purpose copy), P/S/1403254 dt. 16-9-74 (Custom and Exchange purpose copies) and P/S/1403255 dt. 16-9-74 (Custom purpose copy) on the ground that the original above copies have been lost without having been registered with any Custom authority.

In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the Custom purpose copies of licence Nos. P/S/1403253 and P/S/1403255 dt. 16-9-74 and Exchange and Custom purpose copies of licence No. P/S/1403254 dt. 16-9-74 have been lost and direct that the duplicate of the said copies of the licences should be issued the applicant firm.

The original custom purpose copies of licence Nos. P/S/1403253 and P/S/1403255 dt. 16-9-74 and exchange and customs purpose copies of licence No. P/S/1403254 dated 16-9-74 are cancelled.

[No. 1653/NU/4338/P. 33/AM-74/SSI]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)
बुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1975

का०प्रा० 4187.—पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (i) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद तालुका विरमगाम के लिये भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 (ii) के पृष्ठ संख्या 1288 से 1292 तक दिनांक 29-3-75 को प्रकाशित का०प्रा० संख्या 959 के द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12017/1/75 एल०एंड०एल० दिनांक 12-3-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़ें।

अनुसूची

गांव	हंसलपुर	सुरेश्वर	तालुका	विरमगाम	जिला	अहमदाबाद	गुजरात राज्य
के स्थान पर							पढ़ें
क्रमांक	तक	क्रमांक	तक				
	एच ए वर्गमील	एच ए वर्गमील					
796	0 35 15	796	0 25 15				
936	0 23 95	936	0 23 92				

[सं० 12017/1/75 एल०एंड०एल०]
टी०पी० सुब्रह्मन्यम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 13th September, 1975

S. O. 4187.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/1/75-L&L Dt. 12-3-75 published vide S.O. No. 959 dated 29-3-75 from page No. 1288 to 1292 of the Gazette of India Part II Section 3(ii) for Taluka Viramgam Distt. Ahmedabad Gujarat State, under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Village : Hansalpur-Sureshwer		Tal : Viramgam	
Distr. : Ahmedabad.			
Gujarat State.			
For		Read	
S. No.	<u>Extent</u>	S. No.	<u>Extent</u>
	H.A.Sq. M.		H.A.Sq. M.
796	0—35—15	796	0—25—15
936	0—23—95	936	0—23—92

[No. 12017/1/75-L&L].

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1975

का०प्रा० 4188.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2245, तारीख 20 अगस्त, 1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान में की भूमियों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 599.52 एकड़ (लगभग) या 242.61 हेक्टेयर (लगभग) भूमियां अर्जित की जानी चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 599.52 एकड़ (लगभग) या 242.61 हेक्टेयर (लगभग) भूमियां अर्जित की जाती हैं।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांकों का निरीक्षण उपायुक्त, हजारी बाग के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, कीसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरमंगा हाउस, (बिहार) में किया जा सकता है।

अनुसूची

यामोदर नदी तल

वर्षा करमपुरा कोयला क्षेत्र

क्रा० सं० राजस्व 48/74

तारीख 19-11-74 (शीट सं० 1)

जिसमें अर्जित भूमियां दर्शित हैं)

“(खंड ‘क’)

सभी अधिकार

क्रम	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	अंगो	बर्कागांव	97	हजारी-बारा		भाग
2.	उरीमारी	”	155	”	”	”
3.	तोकीसूद	रामगढ़	1	”	”	”
4.	कीरीगारा	”	2	”	”	”
5.	साकुल	”	21	”	”	”

कुल क्षेत्र:— 199.50 एकड़ (लगभग)

या:—80.73 हेक्टेयर (लगभग)

अंगो ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—1670 (भाग)

उरीमारी ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—757 (भाग)

तोकीसूद ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—1,485 और 137 (भाग)

कीरीगारा ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—1 और 2003

सीमा वर्णन

ए-बी—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् ग्रंथों और देवगढ़ ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है, तत्पश्चात् तोकीसूब ग्राम में प्लाट सं० 137 (दामोदर नदी) से होकर दामोदर नदी के दक्षिण तट तक जाती है।

बी-सी—लाइन तोकीसूब, कीरीगारा और सांकुल ग्रामों में दामोदर नदी के आंशिक दक्षिण तट के साथ-साथ जाती है।

सी-डी—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् सांकुल ग्राम के प्लाट सं० 2003 और सिप्राय ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ और उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 757 और 752 की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

डी-ई—लाइन उरीमारी ग्राम में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है।

ई-एफ—लाइन उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 757 से होकर (जो उरीमारी बंड (बलरामपुर परियोजना) के लिए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की आंशिक सामान्य सीमा का भाग है) जाती है।

एफ-जी—लाइन दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो ग्राम उरीमारी के प्लाट सं० 757 और ग्राम सांकुल के प्लाट सं० 2003 की आंशिक सामान्य सीमा है), पोतंगा ग्राम के प्लाट सं० 1974 और सांकुल ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, पोतंगा ग्राम के प्लाट सं० 1876 और कीरीगारा के ग्राम प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, अस्वा ग्राम के प्लाट सं० 374 और तोकीसूब ग्राम के प्लाट सं० 485, अस्वा ग्राम के प्लाट सं० 374 और तोकीसूब ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, ग्रंथों ग्राम के प्लाट सं० 1670 और तोकीसूब ग्राम के प्लाट सं० 1 (जो उरीमारी बंड (बलरामपुर परियोजना) के लिए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है) की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

जी-एच—लाइन ग्रंथों ग्राम के प्लाट सं० 1670 (दामोदर नदी) से होकर जाती है।

एच-ए—लाइन ग्रंथों ग्राम में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है और आरम्भ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

खण्ड 'ख'

डा० सं० राजस्व/48/74--

तारीख 19-11-74

(शीट सं०--II)

(जिसमें अर्जित भूमियां दर्शित हैं)।

सभी अधिकार

क्रम	ग्राम	धाना संख्या	धाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
------	-------	-------------	-------------	------	---------	------------

1.	बसरिया	माण्डू	38	हजारीबाग	भाग	
2.	बुन्दू	माण्डू	39	हजारीबाग	भाग	

कुल क्षेत्र :— 95.13 एकड़ (लगभग)

या 38.50 हेक्टेयर (लगभग)

बसरिया ग्राम में अर्जित प्लाट सं०—231, 433 और 434

बुन्दू ग्राम में अर्जित प्लाट सं०—561 (भाग)

सीमा वर्णन

आई-जे—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् गीड़ी ग्राम के प्लाट सं० 514 और बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 434 की सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

जे-के—लाइन दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 434 और बुंदुआ ग्राम के प्लाट सं० 66, बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 231 और बुंदुआ ग्राम के प्लाट सं० 197, बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 433 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 1, बुन्दु ग्राम के प्लाट सं० 561 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 20 की सामान्य सीमा है) बुन्दु ग्राम के प्लाट सं० 561 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 25 की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ (जो दामोदर नदी तल में, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम की 1957 धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित खण्ड-II की आंशिक सामान्य सीमा है) जाती है।

के-एल—लाइन बुन्दु ग्राम के प्लाट सं० 561 से होकर (जो दामोदर नदी तल में, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित खण्ड-II की आंशिक सामान्य सीमा का भाग है) जाती है।

एल-आई—लाइन बुन्दु और बसरिया ग्रामों में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है और आरम्भ बिन्दु 'आई' पर मिलती है।

खण्ड-ग

डा० सं० राजस्व/48/74

तारीख 19-11-74

(शीट सं० 3)

(जिसमें अर्जित भूमियां दर्शित हैं)

सभी अधिकार

क्रम	ग्राम	धाना संख्या	धाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	सिकर्का	माण्डू	136	हजारीबाग	भाग	
2.	परिगाडा	"	137	"	"	
3.	हेसला	"	138	"	"	
4.	बैनगारा	रामगढ़	57	"	"	
5.	हेहल	"	58	"	"	
6.	बुदुआ	"	59	"	"	
7.	उलांग	"	78	"	"	
8.	छोटकना	"	79	"	"	

कुल क्षेत्र : 304.89 एकड़ (लगभग)

या 123.38 हेक्टेयर (लगभग)

सिकर्का ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—243, 429, 516 और 1010।

परिगाडा ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—138

हेसला ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—122 और 123।

बैनगारा ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—1220 और 1221।

हेहल ग्राम अर्जित प्लाट संख्या :—1

बुदुआ ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—1।

उलांग ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—1, 112, 418, 419 और 578

छोटकना ग्राम में अर्जित प्लाट सं० :—1।

सीमा-वर्णन

"(Block—'A')"

एम-एन—लाइन बामोदर नदी से होकर अर्थात् सिक्रा ग्राम के प्लॉट सं० 1 और 243 की सामान्य सीमा, बोरधारा ग्राम के प्लॉट सं० 304 और चैनगारा ग्राम के प्लॉट सं० 1220 की सामान्य सीमा (जो नदी तल खण्ड-II में कोयला वाले क्षेत्र (ग्रैंजिंग और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र की प्राथमिक सामान्य सीमा) के साथ-साथ जाती है।

एन-ग्रो—लाइन चैनगारा, डेहल, बुदुघा, उलांग, छोटकना ग्रामों में बामोदर नदी के दक्षिण तट के साथ-साथ जाती है।

ग्रो-पी—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् छोटकना ग्राम के प्लॉट सं० 1 की पूर्वी सीमा और हेसला ग्राम के प्लॉट सं० 123 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ) जाती है।

पी-एम—लाइन हेसला, किरिगाड़ा, सिक्रा ग्रामों में बामोदर नदी के बाएं तट के साथ-साथ जाती है और बारंभ-बिन्दु 'एम' पर मिलती है।

[सं० का० 25/14/73-सी 5/सैल]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4188.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 2245 dated the 20th August, 1974, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 599.52 acres (approximately) or 242.61 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 599.52 acres (approximately) or 242.61 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the office of National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Damodar River Bed
South Karanpura Coalfield

DRG No. Rev. /48/74

Dated 19-11-74

(Sheet No. 1)

(Showing lands acquired)

All Rights

S. Village No.	Thana	Thana number	District	Area Remarks
1. Ango	Barkagaon	97	Hazaribagh	Part
2. Urimari	"	155	"	"
3. Tokisud	Ramgarh	1	"	"
4. Kirigara	"	2	"	"
5. Sankul	"	21	"	"
Total area :—199.50 acres (approximately) or :—80.73 hectares (approximately)				

Plot number acquired in village Ango :—1670 (part).

Plot number acquired in village Urimari :—757 (part).

Plot numbers acquired in village Tokisud :—1, 485 & 137 (part).

Plot number acquired in village Kirigara :—1.

Plot numbers acquired in village Sankul :—1 & 2003.

BOUNDARY DESCRIPTION

A—B Line passes through Damodar River (i.e. along the part common boundary of villages Ango and Deogarh) then passes through plot number 137 (River Damodar) in village Tokisud upto Right Bank of Damodar River.

B—C Line passes along the part Right Bank of Damodar River in villages Tokisud, Kirigara and Sankul.

C—D Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot number 2003 of village Sankul and plot number 1 of village Seal, and also along the common boundary of plot numbers 757 and 752 of village Urimari).

D—E Line passes along the part left Bank of River Damodar in village Urimari.

E—F Line passes through plot number 757 of village Urimari (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, for Urimari Block (Balrampur Project).

F—G Line passes along the part Central line of River Damodar (which is the part common boundary of plot number 757 of village Urimari and 2003 of village Sankul along common boundary) of plot number 1864 of village Potonga and plot number 1 of village Sankul, along common boundary of plot number 1876 of village Potonga and plot number 1 of Village Kirigara, along common boundary of plot number 374 of village Aswa and 485 of village Tokisud, along part common boundary of plot number 1670 of village Ango and 1 of village Tokisud (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 for Urimari Block (Balrampur Project).

G—H Line passes through plot number 1670 (River Damodar) of village Ango.

H—A Line passes along the part left Bank of River Damodar in village Ango and meets at starting point 'A'.

BLOCK 'B'
DRG No. Rev/48/74
Dated 19-11-74
(Sheet No. II)
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Basaria	Mandu	38	Hazaribagh		Part
2.	Bundu	"	39	"		"
			Total area : 95.13 acres (approximately) or 38.50 hectares (approximately)			
Plot numbers acquired in village Basaria			231, 433 & 434			
Plot number acquired in village Bundu			561 (part.)			

BOUNDARY DESCRIPTION

I-J—Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot number 514 of village Gidi and plot number 434 of village Basaria.

J-K—Line passes along the part Central line of River Damodar (which is the common boundary of plot number 434 of village Basaria and 66 of village Dundua, plot number 231 of village Basaria and 66 of village Dundua, plot number 231 of village Basaria & 197 of village Dundua, plot No. 433 of village Basaria and 1 of village Chordhara, plot number 561 of village Bundu and 20 of village Chordhara, part common

boundary of plot number 561 of village Bundu and 25 of village Chordhara (which forms part common boundary of Block II notified under section 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Damodar River Bed).

K-L—Line passes through plot number 561 of village Bundu (which forms part common boundary of Block-II notified under section 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Damodar River Bed).

L-I—Line passes along the part left Bank of River Damodar in villages Bundu and Basaria and meets at starting point 'I'.

BLOCK 'C'
DRG No. Rev/48/74
Dated 19-11-74
(Sheet No. III)
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sirka	Mandu	136	Hazaribagh		Part
2.	Arigada	"	137	"		"
3.	Hesla	"	138	"		"
4.	Chaingara	Ramgarh	57	"		"
5.	Hehal	"	58	"		"
6.	Ghutua	"	59	"		"
7.	Urlang	"	78	"		"
8.	Ghhotakana	"	79	"		"

Total area : 304.89 acres (approximately)
or 123.38 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Sirka : 243, 429, 516 & 1010.
Plot number acquired in village Arigada : 138.
Plot numbers acquired in village Hesla : 122 & 123.
Plot numbers acquired in village Chaingara : 1220 & 1221.

Plot number acquired in village Hehal : 1.
Plot number acquired in village Ghutua : 1.
Plot numbers acquired in village Urlang : 1, 112, 418, 419 & 576.

Plot number acquired in village Chhotakana : 1.

BOUNDARY DESCRIPTION

M-N—Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot numbers 1, & 243 of village Sirka common boundary of plot number 304 of village Chordhara

and 1220 of Village Chaingara (which forms part common boundary of the area notification U/s 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 in River Bed Block-II).

N-O—Line passes along the Right Bank of River Damodar in villages Chaingara, Hehal, Ghutua, Urlang, Chhotakana,

O-P—Line passes through Damodar River (i.e. along the eastern boundary of plot number 1 of village Chhotakana and eastern boundary of plot number 123 of village Hesla.

P-M—Line passes along the left Bank of River Damodar in villages Hesla, Arigada, Sirka and meets at starting point 'M'.

सई विल्सी, 5 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4189.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला बांधे क्षेत्र (ध्वंश और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के द्वारा 'और' खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 690(प्र), तारीख 8 नवम्बर, 1973 की अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना के उपाख्य अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों और अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसूचण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि ;

(क) इस से उपाख्य अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि ; और

(ख) इस से उपाख्य अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमियों में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों ;

का ध्वंश किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि को तथा उक्त अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमियों में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन पर कार्य करने उन्हें प्राप्त करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जित किया जाता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), कार्यालय "वरभगा हाऊस", राबो में किया जा सकता है ।

अनुसूची—'क'

बोकारो खण्ड-1 (सवांग विस्तारण)

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

उपखण्ड—'क'

जी० प्रार० जी० सं० राजस्व/25/74

तारीख 2-7-74

(अर्जित की गई भूमियों को दर्शित करने हेतु)

सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	धाना	धाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प- निया
1	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
2	अरमो	नवडीह	11	गिरिडीह		भाग
3	गोविन्दपुर	(पेमों)	15

कुल क्षेत्र : 60.75 एकड़ (लगभग)

या 24.58 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० 1282 (भाग) ।
ग्राम अरमो में अर्जित प्लॉट सं० 444 और 776 ।
ग्राम गोविन्दपुर में अर्जित प्लॉट सं० : 2272 (भाग)

सीमा वर्णन

क-ख—रेखा कुनार नदी (ग्राम धरमा में प्लॉट सं० 774 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तथा सवांग और सस्बेरा ग्रामों की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ से होकर जाती है ।

ख-ग-घ—रेखाएं ग्राम सवांग में कुनार नदी के प्रांशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है ।

घ-ङ—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1282 (कुनार नदी) से हो कर जाती है (सवांग कोलियरी के बालू धूति धरातल क्षेत्र के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा है ।

ङ-च—रेखा कुनार नदी की प्रांशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (पर्याप्त सवांग और धरमो ग्रामों, सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है (सवांग रेखांक, बालू धूति धरातल के क्षेत्र के साथ जिसकी सामान्य सीमा भी है) ।

च-छ—रेखा ग्राम गोविन्दपुर में प्लॉट सं० 2772 (कुनार नदी) से होकर जाती है, (सवांग कोयला खान के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है) ।

छ-क—रेखा गोविन्दपुर धरमो ग्रामों में कुनार नदी के प्रांशिक बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और धारम्भ बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

उप-खण्ड—'ख'

सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	धाना	धाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प- नियां
1	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग

कुल क्षेत्र : 82.00 एकड़ (लगभग)

या 33.18 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० :—44 (भाग), 808 (भाग), 809 (भाग), 810 (भाग), 818 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग), 1281 (भाग) और 1295 (भाग) ।

सीमा वर्णन

ज-स-रेखा ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 44, 809, 808, 810 और 818 से हो कर जाती है।

अ-ख-ट-रेखाएं ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 818, 1281, 818, 832 और 831 से हो कर जाती हैं (खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'घ' के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा है)।

ट-ठ-रेखा ग्राम सवांग प्लॉट सं० 831, 832, 1281, 1895 और 1281 से हो कर जाती है। (सवांग कोलियरी के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है)।

ठ-ड-रेखा गोविन्दपुर और सवांग ग्रामों में कुमार नदी के प्रांशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है (खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है)।

ड-उ-ण-त-य-व-ध-न-प-फ-रेखाएं ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1281 और 818 से होकर जाती हैं खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है)।

फ-ब-रेखा ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 818, 809, 818 और 44 से हो कर जाती है।

ब-ज-रेखा प्लॉट सं० 44 की मध्य रेखा के साथ-साथ (अर्थात् सवांग और ससवारा ग्रामों की प्रांशिक सीमा के साथ) जाती है और प्रारंभ बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

अनुसूची-‘ख’
उप-खण्ड-‘ग’

डी०/प्रार०/जी०/सं० राजरव/26/74
तारीख 2-7-74

(उन भूमियों को दर्शित करते हुए जिनमें खनिज के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, प्राप्त करने, पर कार्य करते और उनके से जाने के अधिकार अर्जित किए गए हैं)।

खनन अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना सं०	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-नियां
1.	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
					कुल क्षेत्र : 61.75 एकड़ (लगभग)	
					या 24.99 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० :—818 (भाग), 1281 (भाग), 1282 (भाग) और 1775 (भाग)।

सीमा वर्णन

ग-म-भ-फ-रेखाएं ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 1281 और 818 से हो कर जाती है।

फ-प-न-ध-द-व-त-ण-ड-ड-रेखाएं सवांग ग्राम के प्लॉट सं० 818 और 1281 (सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ड-ड-रेखा सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों में कुमार नदी में प्रांशिक दाएं किनारे (सभी अधिकारों वाले उप-खण्ड 'ख' से साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है) के साथ साथ जाती है।

ठ-ब-रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1775 से हो कर अर्थात् सवांग कोयला खान की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है।

ब-ड-रेखा कुमार नदी की प्रांशिक मध्य रेखा के साथ साथ (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'क' प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

ड-ब-रेखा ग्राम सवांग प्लॉट सं० 1282 से हो कर (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उप-खण्ड 'क' प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

ध-ग-अरेखा कुमार नदी के प्रांशिक दाएं किनारे के साथ साथ (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'क' की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है और प्रारंभ बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

उप-खण्ड-घ

खनन अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	थाना सं०	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-नियां
1.	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
					कुल क्षेत्र : 21.00 एकड़ (लगभग)	
					या 8.50 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० : 803 (भाग), 804 (भाग), 805, 818 (भाग), 825 (भाग), 828 (भाग), 829 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग) और 1281 (भाग)।

सीमा वर्णन

अ-य-रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 818, 804, 818 और 803 से हो कर जाती है।

य-ट-रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 808, 818, 825, 824, 829 और 831 (जिसकी सवांग कोयला खान के साथ भागतः सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ट-अ-रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 831, 832, 818, 1281 और 818 (जिसकी सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है और प्रारंभ बिन्दु अ पर मिलती है।

[सं० फ० 25/24/73-सी 5/सैल]

New Delhi, the 5th September, 1975

S.O. 4189.—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), S.O. No. 690 (E) dated the 8th November, 1973, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and rights specified in the Schedules appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made its report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report the competent authority and after consulting the Government of Bihar is satisfied that;

(a) the land measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto, and;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government

hereby declares that the land, measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in the said Schedule 'A' and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in the said schedule 'B' are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), "Darbhanga House", Ranchi.

SCHEDULE 'A'

BOKARO BLOCK—I (SAWANG EXTENSION)

EAST BOKARO COALFIELD

SUB-BLOCK—'A'

All Rights						DRG No. Rev/26/74 Dated 2-7-74 (Showing lands acquired)
Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
2.	Armo	Nawadli (Bermo)	11	Giridih		Part
3.	Gobindpur	"	15	Giridih		Part
Total Area :						60.75 acres (approximately) or 24.58 hectares (approximately)
Plot number acquired in village Sawang			1282 (Part).			
Plot numbers acquired in village Armo			474 & 776.			
Plot number acquired in village Gobindpur			2772 (Part).			

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B—line passes through Kunar Nadi (i.e. along the Western boundary of plot No. 474 of Village Armo and along the part common boundary of villages Sawang and Sasbera).

B-C-D—lines pass along the part Right Bank of Kunar Nadi in village Sawang.

D-E—line passes through plot number 1282 (Kunar Nadi) of village Sawang (which also forms common boundary with the surface area of Sand Lease of Sawang colliery).

E-F—line passes along the part central line of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Armo, Sawang & Gobindpur) (which also forms common boundary with the Surface area of Sand Lease of Sawang Colliery).

F-G—line passes through plot number 2772 (Kunar Nadi) of village Gobindpur /which also forms part common boundary with Sawang Colliery).

G-A—line passes along the part left Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur & Armo and meet at starting-point 'A'.

SUB-BLOCK—'B'

All Rights						
Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part.
Total area :						82.00 acres (approximately) or 12.18 hectares (approximately)
Plot numbers acquired in village Sawang			44 (Part), 808 (Part), 809 (Part), 810 (Part), 818 (Part), 831 (Part), 832 (Part), 1281 (Part) & 1295 (Part).			

BOUNDARY DESCRIPTION :

H—I—line passes through plot numbers 44, 809, 808, 810 and 818 of village Sawang.

I—J—K—lines pass through plot numbers 818, 1281, 818, 832 and 831 of village Sawang (which also forms common boundary with sub-block 'D' Mining Rights).

K—L—lines passes through plot numbers 831, 832, 1281, 1295, 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

L—M—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur and Sawang (which also forms part common boundary Sub-Block 'C'—(Mining Rihts).

M—N—O—P—Q—R—S—T—U—V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'C' Mining Rights.)

V—W—line passes through plot numbers 818, 809, 818 and 44 of village Sawang.

W—H—line passes along the Central line of plot number 44 (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Sisbera and meets at starting point 'H'.

SCHEDULE—'B'
SUB-BLOCK—'C'

DRG No. Rev/26/74
Dated 2-7-74
(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are acquired).

Mining Rights		Thana	Thana number	District	Area	Remarks
Sl. No.	Village					
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
			Total area : 61.75 acres (approximately) or 24.99 hectares (approximately)			
Plot numbers acquired in village Sawang			818 (Part), 1281 (Part), 1282 (Part) and 1775 (Part).			

BOUNDARY DESCRIPTION :

C—Y—X—V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang.

V—U—T—S—R—Q—P—O—N—M—lines pass through plot numbers 818 and 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

M—L—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Sawang and Gobindpur (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

L—F—line passes through plot number 1775 of village Sawang (i.e. along the part common boundary of Sawang colliery).

F—E—line passes along the part Cential line of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of Sub-Block 'A' All Rights).

E—D—line passes through plot numbers 1282 of villages Sawang (i.e. along the part common boundary of sub-block 'A' All Rights).

D—C—line passes along the part Rights Bank of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of sub-block 'A' All Rights) and meets at starting point 'C'.

SUB-BLOCK—'D'

Mining Rights		Thana	Thana number	District	Area	Remarks
Sl. No.	Village					
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
			Total area : 21.00 acres (approximately) or 8.50 hectares (approximately)			
Plot numbers acquired in village Sawang			803 (Part), 804 (Part), 805, 818 (Part), 825 (Part), 828 (Part), 829 (Part), 831 (Part), 832 (Part) and 1281 (Part).			

[No. 25/24/73—CS/CEL]

BOUNDARY DESCRIPTION :

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

I—Z—line passes through plot numbers 818, 804, 818 and 803 of village Sawang.

Z—K—line passes through plot numbert 803, 818, 825, 828, 829 and 831 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

K—J—I—lines pass through plot numbers 831, 832, 818, 1281 and 818 of village Sawang (which also forms common boundary with Sub-Block 'B' All Rights) and meets at starting point I.

का० प्रा० 4190.—कोयला वाले क्षेत्र (प्रजन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निम्न समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 2895-2901 पर प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय के खान और धातु विभाग की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2630 तारीख 9 अगस्त, 1965 को विद्यमान करती है।

[सं० फ० 19(23)/75(सेल)]

New Delhi, the 10th Sept., 1975

S.O. 4190.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals), No. S. O. 2630 dated the 9th August, 1965, published at pages 2895 to 2901 in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 28th August, 1965.

[No. 19(23)/75 CEL]

क्र०आ० 4191.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाय अनुसूची में वर्णित भूमियों से कोयला प्राप्त होने की संभावना है;

अतः अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उनमें कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आणय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची या उपायुक्त, गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1 कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सब व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सब मान निम्न, चाटे और अन्य दस्तावेजों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को दे दे।

अनुसूची

गोविन्दपुर ब्लॉक

पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र

डाइंग नं० राजस्व/53/74

तारीख 21-12-74

(जिसमें पूर्वोक्षण के लिए अधिसूचित भूमियां वर्णित हैं)

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्दपुर	नवाडीह (बेर्मो)	15	गिरिडीह	भाग

1	2	3	4	5	6
2	आर्मो	नवाडीह (बेर्मो)	11	गिरिडीह	भाग
		कुल क्षेत्र	1660.00 एकड़		(लगभग)
		या	671.77 हेक्टर		(लगभग)

सीमा-वर्णन

ए-बी— लाइन गोविन्दपुर ग्राम से कुनार नदी की आशिक पूर्वो सीमा के साथ साथ जाती है।

बी-सी— लाइन गोविन्दपुर ग्राम से कुनार नदी की आशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है।

सी-डी-ई-एफ— लाइन गोविन्दपुर ग्राम से होकर जाती है।

एफ-ए— लाइन गोविन्दपुर ग्राम से होकर जाती है और आरंभ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[सं० 19/23/75-सैल]

एस०आर०ए० रिजवी, उप-मन्त्रि

S. O. 4191.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue section), Darbhanga House, Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar), or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHDEULE

GOVINDPUR BLOCK

EAST BOKARO COALFIELD

DRG No. Rev/53/74

Dated 21-12-74

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	Govindpur	Nawadih (Berma)	15	Giridih		Part
2	Armo	"	11	"		"
Total Area :			1660.00 acres (approximately)			
			or 671.77 hectares (approximately)			

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B—line passes along the part eastern boundary of River Kunar in village Govindpur.

B-C—line passes along the part Northern boundary of River Kunar in village Govindpur.

C-D-E-F—lines pass through village Govindpur.

F-A—line passes through village Govindpur and meets at starting point 'A'.

[No. 19(23)/75-CEL]

S.R.A. RIZVI, Dy. Secy.,

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

कां.प्र. 4192.—केन्द्रीय सरकार, बहुएकक सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या एल 11011/2/70-पी. एंड. सी. तारीख 8 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की शर्त 1 में, क्रम संख्या (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएँ अन्तः स्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

"(13) पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।

(14) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।"

[सं.एल. 11011/2/70-एल. एंड. सी.]

ना. कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 11th September, 1975

S.O. 4192.—In exercise of the powers conferred by section 5 B of the Mul-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Cooperation) No. L. 11011/2/70-P&C dated the 8th November, 1973 namely:—

In condition I of the said notification, after serial No. (12) and the entries relating thereto, the following serial No. shall be inserted namely:—

(13) Petrofils Cooperative Ltd., New Delhi.

(14) National Heavy Engineering Cooperative Ltd., New Delhi.

[No. L11011/2/70-L&M]

N. KRISHNAMURTHI, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

कां.प्र. 4193.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड(ख)का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित विश्वविद्यालय द्वारा, प्रत्येक के सम्मुख लिखि गई तिथि से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है:—

व्यक्ति का नाम

विश्वविद्यालय का नाम निर्वाचन की तिथि

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| 1. डा० एस० जे० दामनी एम० बी०, गुजरात एफ० सी० पी० ए० एस० के० एम० स्कूल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च, अहमदाबाद-6 | विश्वविद्यालय | 6-2-1975 |
| 2. डा० एम० पी० पाह, प्रिन्सिपल, मैसूर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, बंगलूर | विश्वविद्यालय | 1-5-1975 |
| 3. डा० आर० के० मेंदा, एफ० आर० बम्बई ए० सी० अमर चन्द नेशनल, मद्रास कामा रोड, बम्बई-400001 | विश्वविद्यालय | 21-2-1975 |

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि डा० एम० पी० पाह और आर० के० मेंदा इस परिषद के सदस्य बने रहेंगे और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० 5-13/59-चिकित्सा-1 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः

उक्त अधिसूचना में "खंड (ख) या धारा 3 की उप धारा (1) में निर्वाचित शीर्षक के अधीन" क्रम संख्या 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और इससे संबंधित प्रविष्टियाँ रख ली जायें; नामतः

"11. डा० एस० जे० दामनी, एम० बी०; एफ० सी० पी० ए० एस० के० एम० स्कूल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च, अहमदाबाद-6। [सं० पी० 11013/1/75-एम० पी० टी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4193.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956), the following persons have been elected by the University specified against each of them to be members of the Medical Council of India with effect from the date noted against, each, namely:—

Name of person	Name of University	Date of election
1. Dr. S.J. Damany, MD, FCPS, K.M. School of Post-graduate Medicine and Research, Ahmedabad-6.	Gujarat University	6-2-1975
2. Dr. M.P. Pai, Principal, Kasturba Medical College, Bangalore.	Mysore University	1-5-1975
3. Dr. R.K. Menda, FRCS, Amarchand Mansion, Madame Cama Road, Bombay-400001.	Bombay University	21-2-1975

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Dr. M.P. Pai and Dr. R.K. Menda shall continue to be the member of the said Council and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) or sub-section (1) of Section 3", for serial No. 11 and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be substituted, namely :—

"11— Dr. S.J. Damany, MD, FCPS,
K M. School of Postgraduate Medicine and Research,
Ahmedabad-6".

[No. V. 11013/1/75-MPT]

का० प्रा० 4194.—दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—
उक्त अनुसूची के भाग 1 में;

(1) क्रम संख्या 14 के सामने, "मास्टर आफ डेंटल सर्जरी (प्रोपरेटिव) (डेंटिस्ट्री) एम०डी०एस० (प्रोपरेटिव) केरल" विश्व-विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय :—

"मास्टर आफ डेंटल सर्जरी—एम०डी०एस० (प्रास्थ) केरल (प्रास्थिक डेंटिस्ट्री)।

(2) क्रम संख्या 15 के सामने, मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित बचलर; आफ डेंटल सर्जरी बी०डी०एस० मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित शब्दों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय :—

"मास्टर आफ डेंटल सर्जरी—एम०डी०एस० (प्रोपरेटिव मैसूर (प्रोपरेटिव डेंटिस्ट्री)।

(इस प्रहृता को तभी मान्यता दी जायेगी
बशर्ते कि इसे पहले प्रदान
किया गया हो।)

[सं०बी० 12017/4/74-एम०पी०टी०]
के० सी० मिश्र, अवर सचिव

S.O. 4194.—in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following amendments in the Schedule to the said Act, namely :—

In Part 1 of the said Schedule,—

(i) against serial No. 14 relating to the Kerala University, after the entry "Master of Dental Surgery (Operative Dentistry) M.D.S. (Operative), Kerala", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Dental Surgery

(Prosthetic Dentistry) M.D.S.(Pros.), Kerala";

(ii) against serial No. 15 relating to the Mysore University, after the entry "Bachelor of Dental Surgery
78 GI/75—6

B.D.S. Mysore", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Dental Surgery . . . M.D.S. (Operative),
(Operative Dentistry) Mysore";

(This qualification shall be recognised only when granted before 12-9-1975).

[V. 12017/4/74-MPT]

K. C. MISRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4195.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ग की उप धारा (7) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार श्री पी० एन० बी० कुरुप को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के 27 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या एम 19012/2/75—ए० पी० सी० के अधीन गठित आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है।

[सं० एक्स 19012/2/75—ए० पी० सी०]

पी० बी० हरिहरसंकरन, उप-सचिव

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4195.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 33C of the Drugs and Cosmetics Act 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Shri P. N. V. Kurup, Adviser in Indigenous Systems of Medicine, Ministry of Health and Family Planning to be the Secretary of the Ayurvedic and Unani Drugs Technical Advisory Board constituted under the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Notification No. X.19012/2/75-APC, dated the 27th August, 1975.

[No. X. 19012/2/75-APC]

P. V. HARIHARASANKARAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4196.—भूतपूर्व राजस्व तथा कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 1616 एफ विनांक 25 जुलाई, 1900 के खंड (क) के नियमों के नियम 3 तथा नियम 4 को दृष्टि में रखते हुए, जिनमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, के अनुसार भारत सरकार (1) श्री वेबकी नन्वन प्रसाध सिंह, रतवारा, पो० प्रा० झोली, मुजफ्फरपुर (बिहार), (2) श्री बी० मुकजी, स्टोनी-क्राफ्त, गिलांग (असम) तथा श्री ए० एम० रथनास्वामी, 93, पीटर्स रोड, मद्रास के स्थान पर (1) श्री राम लखन, भूतपूर्व सचिव, विधान, सभा 86 मेलुपुरा, वाराणसी (2) श्री जगन्नाथ प्रसाध सिंह, एडवोकेट, प्रकाश पैटोल पो० श्री० ससाराम, जिला राहतास (बिहार) और (3) श्री एन० महालिंगम, 49 सेंट मेरी रोड, मद्रास को इंडियन पीपल्स फार्मिन् ट्रस्ट के प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है। ये नियुक्तियां तत्काल ही प्रभावी होंगी।

[सं० 15-2/75/एस० आर० 2]

अश्व प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4196.—In accordance with clause (a) of Rule 3 of the Rules published with the late Department of Revenue and Agriculture Notification No. 1616 F dated 25-7-1900 read with Rule 4 thereof as amended from time to time, the Government of India are pleased to appoint (1) Shri Ram Lakhan, Ex-MLA 86 Bhelupura, Varanasi, (2) Shri Jagannath Prasad Singh, Advocate, Prakash Petrol, P.O. Sasaram, Distt. Rohtas (Bihar) and (3) Shri N. Mahalingam 49, St. Mary's Road, Madras as members of the Board of Management, Indian People's Famine Trust with immediate effect vice (i) Shri Devki Nandan Prasad Singh, Ratwara P.O. Dholi, Muzaffarpur (Bihar), (ii) Shri B. Mookherjee, Stonycraft, Shillong (Assam) and (iii) Shri A. M. Rathnaswamy, 93 Peters Road, Madras.

[No. 15-2/75-SR II]

CHANDRA PRAKASH, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

क्र० आ० 4197.—श्री वी० एस० मानेकर ने, जिसे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3496, तारीख 3 दिसम्बर, 1973 द्वारा मौरुगाओ डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अपना पद त्याग दिया है ;

और उक्त सदस्य के पदत्याग से उक्त डॉक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[सं० एल डी जी/6/13/75 (i)]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4197.—Whereas Shri V. S. Manerkar who was appointed as a member of the Mormugao Dock Labour Board by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 3496, dated the 3rd December, 1973, has resigned his office under sub-rule (3) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board by the resignation of the said member ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. LDG/6/13/75(ii)]

क्र० आ० 4198.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के द्वितीय परवचक के साथ पठित डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी० के० उणी को मौरुगाओ डॉक

श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3496, तारीख 15 अप्रैल, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "डॉक कर्मकारों और नौवहन कम्पनियों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत, मद (2) के सामने, "श्री वी० एस० मानेकर" प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "श्री टी० के० उणी" रखी जाएगी।

[सं० एल डी जी/6/3/75(ii)]

वी० शंकरलिंगम्, छावर सचिव

S.O. 4198.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri T. K. Unny as a member of the Mormugao Dock Labour Board and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1220 dated the 5th April, 1965, namely :—

In the said notification under the heading "Members representing the employers of dock workers and shipping companies, against item (2) ; for the entry "Shri V. S. Manerkar", the entry "Shri T. K. Unny" shall be substituted.

[No. LDG/6/13/75 (ii)]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

CORRIGENDUM

(Merchant Shipping)

S.O. 4199.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 442, dated the 31st January, 1975, published on page 614 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th February, 1975 in line 4 for "1970", read "1960".

[No. 12-MAO(146)/74-MA]

D. C. AHIR, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

क्र० आ० 4200.—जम्मू टेलीफोन एक्मब्लेज प्रणाली के स्वामीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के संबंध में एक गार्वेनरिक सूचना जम्मू में प्रेषित भ्रमाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी ; जैसा कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (iii) (ख ख) में अपेक्षित है, वे सभी व्यक्ति, जिन पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, अपनी आपत्ति और सुझाव इस सूचना के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

अनुगाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 8, 9 और 11 फरवरी, 1975 को क्रमशः "इमारत", "सन्देश" तथा "कौमी आवाज" दैनिक समाचारपत्रों में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जनसाधारण ने कोई भी आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (iii) (ख ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 1-10-75 से जम्मू का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा।

जम्मू टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

जम्मू का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि जम्मू नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता जम्मू नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं, लेकिन जिन्हें जम्मू टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यवस्था का किसी भी एकसर्वोच्च से जब तक 5 कि० मी० दूरी के भीतर स्थित अन्य प्रयोग व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदाएगी करेंगे।

[सं० 3-16/74-PHB एन० जो०]

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4200.—Whereas a public notice for revising the local area of Jammu Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Jammu, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 11th February, 1975 in Daily "Quami Awaz", on 8th February 1975 in Daily 'Imarat' and on 9th February, 1975 in Daily 'Sandesh' Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-10-1975 the revised local area of Jammu shall be as under:

Jammu Telephone Exchange System :

The local area of Jammu shall cover an area falling under the jurisdiction of Jammu Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Jammu Municipality limit but who are served from Jammu Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-16/74-PHB]

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का. आ. 4201.—उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना उदयपुर में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ख) में अपेक्षित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वे सभी अपनी आपत्ति और सुझाव इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 7 और 10 जुलाई 1975 को दैनिक समाचार पत्र "जय राजस्थान" में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जनसाधारण से कोई भी आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (3) (ख ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 1-10-1975 से उदयपुर का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

उदयपुर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि उदयपुर नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता उदयपुर नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यवस्था के किसी भी एकसर्वोच्च से जब तक 5 कि. मी. दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदाएगी करेंगे।

[सं. 3-12/74-पी. एन बी (1)]

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 4201.—Whereas a public notice for revising the local area of Udaipur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Udaipur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th July and 10th July 1975 in Daily Newspaper "Jai Rajasthan";

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-10-1975 the revised local area of Udaipur shall be as under :

Udaipur Telephone Exchange System :

The local area of Udaipur shall cover an area falling under the jurisdiction of Udaipur Municipality ;

Provided that the telephone subscribers located outside Udaipur Municipal limit but who are served from Udaipur Telephone Exchange system shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(i)]

का. आ. 4202.—भीलवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना भीलवाड़ा में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ख) में अपेक्षित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वे सभी अपनी आपत्ति और सुझाव इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 7 और 10 जुलाई 1975 को दैनिक समाचार पत्र "नवज्योति" में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपत्ति और सुझाव
उक्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपत्ति और सुझाव

उक्त सूचना पर जनसाधारण से कोई भी आपत्ति सुझाव
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महाविदेशक एतद्द्वारा
घोषणा करते हैं कि 1-10-75 से भीलवाड़ा का संशोधित स्थानीय
क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

भीलवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

भीलवाड़ा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि भीलवाड़ा नगर-
पालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन
उपभोक्ता भीलवाड़ा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें
भीलवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती
है, वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि. मी.
दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्था-
नीय शुल्क वर से अदायगी करेंगे।

[सं. 3-12/74-पी. एच. बी (2)]

S.O. 4202.—Whereas a public notice for revising the
local area of Bhilwara Telephone Exchange System was
published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian
Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at
Bhilwara, inviting objections and suggestions from all persons
likely to be affected thereby, within a period of 30 days
from the date of publication of the notice in the News-
papers;

And whereas the said notice was made available to the
public on 7th July 1975 in Daily Newspaper "Navjyoti"
And whereas no objection and suggestion, have been
received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by
rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General
Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from
1-10-1975 the revised local area of Bhilwara shall be as
under :

Bhilwara Telephone Exchange System.—The local area of
Bhilwara shall cover an area falling under the jurisdiction
of Bhilwara Municipality ;

Provided that the telephone subscribers located outside
Bhilwara Municipal limit but who are served from Bhilwara
Telephone Exchange system shall continue to pay local
tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any
exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(II)]

का. आ. 4203.—जोधपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय
क्षेत्र में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना
जोधपुर में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा
कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ख) में
अपीक्षित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की
सम्भावना है, वे सभी अपनी आपत्ति और सुझाव इस सूचना के
समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर
भेजने का कष्ट करें।

सर्व साधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 10 दिसम्बर,
1974 को "सूर्य राजस्थान" "जलते दीप" और "जनगण" दैनिक
समाचार पत्रों में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जनसाधारण से कोई भी आपत्ति और सुझाव
प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (3) (ख ख) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महाविदेशक एतद्द्वारा
घोषणा करते हैं कि 1-10-75 से जोधपुर का संशोधित स्थानीय क्षेत्र
निम्न प्रकार होगा :

जोधपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

जोधपुर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि जोधपुर नगरपालिका
के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता
जोधपुर नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें जोधपुर
टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यव-
स्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि. मी. दूरी के भीतर
स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शुल्कदर
से अदायगी करेंगे।

[सं. 3-12/74 पी. एच. बी. (3)]

एच. सी. माथुर, निदेशक

S.O. 4203.—Whereas a public notice for revising the
local area of Jodhpur Telephone Exchange System was
published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian
Telephone Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at
Jodhpur, inviting objections and suggestions from all persons
likely to be affected thereby, within a period of 30 days
from the date of publication of the notice in the News-
papers ;

And whereas the said notice was made available to the
public on 10th December 1973 in Daily Newspapers "Tarun
Rajasthan", "Jalte Deep" and "Jangan";

And whereas no objections and suggestions have been
received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by
rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General
posts and Telegraphs hereby declares that with effect from
1-10-1975 the revised local area of Jodhpur shall be as
under ;

Jodhpur Telephone Exchange System.—The local area of
Jodhpur shall cover an area falling under the jurisdiction of
Jodhpur Municipality ;

Provided that the telephone subscribers located outside
Jodhpur Municipal limit but who are served from Jodhpur
Telephone Exchange system shall continue to pay local
tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any
Exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(iii)]

H. C. MATHUR, Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 4204.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890
(1890 का 9) की धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (4)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न वर्गों के मालखिम्बों के
लिए, मालखिम्बों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन
रहते हुए, अधिकतम बहन क्षमता नियत करती है, प्रार्थना:—
क. बड़ी लाइन मालखिम्बे :-

1. अनुज्ञप्त अधिक लदान की सीमा :—

(1) 4 पहिये या 6 पहिये वाले मालखिम्बे में दो मीट्रिक टन की
सीमा तक, जिसमें एक मीट्रिक टन की लदान सहायता में
सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

- (2) बी ओ एक्स, बी ओ आई, बी आर एस, बी प्रो एल, बी सी एक्स, बी ओ बी एस या किसी भी ओ बी एक्स मालखिम्बे के सिवाए किसी बोगी मालखिम्बे में चार मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें दो मीटरिक टन की लदान सह्यता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

2 अधिक लदान की शर्तें

- (1) अधिक लदान केवल $10'' \times 5''$ और $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ धुरे के मालखिम्बों को ही लागू होगा और यह तब जब कि धुरे का व्यास क्रमशः $4.5/8''$ और $4.3/16''$ से नीचे न गिरे।
- (2) बोगी मालखिम्बों की दशा में, भार समवितरित किया जाएगा।
- (3) अधिक लदान, किसी भी परिस्थिति में, भ्रमानक बी एक आर्म पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और केवल मानक ट्रायल बोगी रेल ट्रक (बी आर्से) पर अधिक लदान किया जा सकेगा।
- (4) भारतीय रेल सम्मेलन संगम पथ निर्बंधन नक्शे में यथा उप-दशित अधिकतम अनुज्ञेय धुरी भार को बढ़ाया नहीं जाएगा।

छोटी लाइन मालखिम्बे :—

1 अनुज्ञात अधिक लदान की सीमा :—

- (1) 4 पहिये या 6 पहिये वाले मालखिम्बे में एक मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें $\frac{1}{2}$ मीटरिक टन की लदान सह्यता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।
- (2) बोगी मालखिम्बे में दो मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें एक मीटरिक टन की लदान सह्यता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

2 अधिक लदान की शर्तें

- (1) अधिक लदान केवल $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ और $7'' \times 4''$ धुरे के मालखिम्बों को ही लागू होगा और यह तब जब कि धुरे का व्यास क्रमशः $4''$ और $3.11/16''$ से नीचे न गिरे।
- (2) भारतीय रेल सम्मेलन संगम पथ निर्बंधन नक्शे में यथा उप-दशित अधिकतम अनुज्ञेय धुरी भार को बढ़ाया नहीं जाएगा।

ग. बड़ी लाइन और छोटी लाइन मालखिम्बे :—

किन्हीं 4 पहिये वाले माल खिम्बों, 6 पहिये वाले मालखिम्बों या बोगी मालखिम्बों जिनमें उनके धुरे का व्यास ऊपर विहित सीमाओं से नीचे होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से जिनसे वे अधिक लदान के अयोग्य हो जाते हैं, इस प्रकार अधिक लदान नहीं किया जा सकता, पर यह वशति के लिये कि ऐसे मालखिम्बों में अधिक लदान अनुज्ञात नहीं है, निम्नलिखित विज्ञा होगा :—

“मालखिम्बों के दोनों ओर रहन क्षमता के प्रकीर्ण के साथ-साथ पाइंटों के सामने चार नोक वाला श्वेत तारक 125 एम एम (5'') होगा।”

[सं० 75/एम (एन०)/951/69]
ए० एल० गुप्त, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4204.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 53 of the

Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby fixes the maximum carrying capacity for the various classes of wagons, subject to the conditions, specified in relation to each class of wagons, namely :—

A. Broad Gauge wagons :—

1. Extent of overloading permitted—

- (1) A 4-wheeler or a 6-wheeler wagon may be overloaded to the extent of two tonnes inclusive of the loading tolerance of one tonne.
- (2) A bogie wagon except a BOX, BOI, BRS, BRH, BCX, BOBS or a BOBX wagon may be overloaded to the extent of four tonnes inclusive of the loading tolerance of 2 tonnes.

2. Conditions for overloading—

- (1) The overloading shall apply only to wagons with $10'' \times 5''$ and $9''$ into $4\frac{1}{2}''$ journals provided that the journal diameter is not turned below $4.5/8''$ and $4.3/16''$ respectively.
- (2) In the case of bogie wagons, the load shall be evenly distributed.
- (3) The overloading shall under no circumstance be permitted on non-standard BFRs and only the Standard type bogie rail trucks (BRs) may be overloaded.
- (4) The maximum permissible axle loads, as shown in the Indian Railway Conference Association Track Restriction Map, shall not be exceeded.

B. Metre Gauge Wagons :—

1. Extent of overloading permitted—

- (1) A 4-wheeler or a 6-wheeler wagon may be overloaded to the extent of one tonne including loading tolerance of $\frac{1}{4}$ tonne.
- (2) A bogie wagon may be overloaded to the extent of two tonnes including loading tolerance of 1 tonne.

2. Conditions for overloading :—

- (1) The overloading shall apply only to wagons with $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ and $7'' \times 4''$ journals provided that the journal diameter is not turned below $4''$ and $3.11/16''$ respectively.
- (2) The maximum permissible axle load, as shown in the Indian Railway Conference Association Track Restriction Map, shall not be exceeded.

C. Broad Gauge and Metre Gauge wagons.—A 4-wheeler wagon, a 6-Wheeler wagon or a bogie wagon which can not be so overloaded owing to its journal diameter being below the limits prescribed above or for any other reasons which render them unfit for overloading, shall bear the following marking to indicate that overloading is not permitted on such wagons :—

“A four-pointed white star 125 mm(5'') across the points along side the figure of the carrying capacity on both sides of the wagons.”

[No. 75/M(N)/951/69]
A. L. GUPTA, Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 4205.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री मांझी लाल भागवत प्रसाद, बलुआ पत्थर खान स्वामी, बाहेटा, डाकघर करौली, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान), की बाहेटी बलुआ पत्थर खान, करौली के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री मांजीलाल भागवत प्रसाद, खान स्वामी, करौली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान की बाहेटी बलुआ पत्थर की खानों में नियोजित कर्मकार, सर्वेजन्य स्वीकार के और राष्ट्रीय प्रयत्न-दिनों की मंजूरी के हकदार हैं ? यदि हां तो कितने और किन अवसरों पर और किस तर्ज से ?

[संख्या एल 29011/43/75-डी० ओ० (3बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 4205.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Baharta Sand Stone Mine, Karauli of Shri Mangilal Bhagwat Prasad, Sand Stone Mine Owner, Baharta, Post Office Karauli, District Sawaimadhopur, (Rajasthan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Baharta Sand Stone Mines of Shri Mangilal Bhagwat Prasad, Mine Owner, Karauli, District Sawaimadhopur, Rajasthan are entitled to grant of paid festival and national holidays? If so, how many and on what occasions and from which year?

[No. L-29011/43/75-D.O. 3(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

का० आ० 4206.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स इंडिया सीमेण्ट्स

लिमिटेड डाकघर, शंकर नगर जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिनके पीठासीन अधिकारी थिरु टी० पालानीअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

क्या इंडिया सीमेण्ट्स लिमिटेड, शंकरनगर धर्से, डाकघर शंकर नगर जिला तिरुनेलवेली के प्रबन्धतंत्र की, श्री टी० गणपति, ड्रिलर, सेजीनाल्लुर लाइम-स्टोन क्वैरी, को 28 अगस्त, 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-29011/95/75-डी० ओ०-3बी०]

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1975

S.O. 4206.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs India Cements Limited, Sankarnagar Post Office, District Tirunelveli, Tamil Nadu, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the India Cements Limited, Sankarnagar Works, Sankarnagar Post Office, District Tirunelveli, in dismissing Shri T. Ganapathy, Driller, Sezhinallur Limestone Quarry, from service with effect from the 28th August, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/95/75-D.O. III. B]

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

का० आ० 4207.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में टाटा केमिकल्स लि०, डाकघर रानावाव, जिला जूनागढ़, गुजरात के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० यू० शाह होंगे, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड, शाकघर रानावाव, जिला जूनागढ़, गुजरात के प्रबन्धतन्त्र का पत्थर खदान, रानावाव, गुजरात के ट्रक चालक श्री नयपाल सिंह बी० ठाकुर की सेवाएं 24 अक्टूबर, 1974 में समाप्त करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-29011/89/75-डी-3(डी)]

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1975

S.O. 4207.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to management of Tata Chemicals Limited, Post Office Ranavav, District Junagadh, Gujarat, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri M. U. Shah as Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the termination of services of Shri Jaipal Singh B Thakur, a Truck Driver of Stone Quarry, Ranavav, Gujarat, with effect from 24th October, 1974 by the management of Tata Chemicals Limited, Post Office Ranavav, District Junagadh, Gujarat, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No L-29011/89/75-D III B]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

का० प्रा० 4208.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) की कुरासिया कोलियरी, जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश के प्रबन्धतन्त्र से संबंधित नियोजक और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) की कुरासिया कोलियरी जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश के प्रबन्धतन्त्र की उक्त कोलियरी के ड्रेसरा में निम्नलिखित प्रतिरिक्त कार्य लेना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कोलियरी के ड्रेसरा किस अनुतोष के हकदार है और किस तारीख से?

- (क) उत्स्फोटक (शाटफायरर) बले कारतूस देकर गुराखों को भरने में उनकी सहायता करना,
- (ख) जब उत्स्फोटक शाटफायरर सीढ़ी पर चढ़ कर गुराखों को भरने में रत हो, तो ऊँचे स्थानों पर सीढ़ी को पकड़ना,
- (ग) छत की सतह और फर्श को सफा करना,
- (घ) मशीन द्वारा काटे गए फेस से अधिनियमितों को सतह पर लाक सूरख करने के लिए फेस साफ किया जा सके,
- (ङ) बले कारतूसों को हलाके में ले जाना और उनका पुनर्घातन स्थानों पर सट्टा बाधना और जैसे और जब आवश्यक हो कारतूसों को बाधने के लिए उन्हें फेसों पर ले जाना

[संख्या एल-22011/7/74-एल०आर-2/डी-2(डी)]

एस० एल० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

S.O. 4208.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kurasia Colliery, District Surguja, Madhya Pradesh, of National Coal Development Corporation Limited, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Kurasia Colliery, district Surguja, Madhya Pradesh, of National Coal Development Corporation Limited, in taking the following extra work, namely;

- (a) helping the Shotfirer in charging the holes by handing him clay cartridges
- (b) holding the ladder in high places when the shotfirer is engaged in charging the holes by climbing a ladder,
- (c) dressing the roof side and floor,
- (d) cleaning the gummings from the machine cut face to make the face clean for dilling the holes,
- (e) carrying the clay cartridges within the district and stacking the same at the convenient places and carrying the same to faces as and when required for stemming the charges,

from the dressers of the said colliery is justified? If not, to what relief the dressers of the said colliery are entitled and from what date?

[No. L-22011/7/74/II RII/DIIB]

S H. S. TYFR, Section Officer (Spl)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

आदेश

क्रा० अा० 4209.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करता वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची]

क्या पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली प्रदेश, श्री महादेव प्रसाद शुक्ल, प्रधान चपरासी की जन्म-तिथि में परिवर्तन न करना और उसकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति को प्रवर्तित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 12012/51/75/डी०-2ए]

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1975

S.O. 4209.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Punjab National Bank, Delhi Region, is justified in not altering the date of birth of Shri Mahadeo Prasad Shukla, Head Peon and enforcing his premature retirement from service ? If not, to what relief is the said workmen entitled ?

[No. L-12012/51/75/DII/A]

आदेश

क्रा० अा० 4210.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र की, श्री विरेन्द्र कुमार, अंशकालिक पास बुक लेखक की सेवाएं, 9 जुलाई, 1974 से समाप्त करते और उक्त कर्मकार को पूर्णकालिक लिपिक के रूप में नियुक्त न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 12012/71/75-डी० 2ए]

ORDER

S.O. 4210.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India, New Delhi in terminating the services of Shri Virendra Kumar, Part-time pass book writer with effect from the 9th July 1974 and in not appointing the said workmen as full time clerk is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/71/75/DII/A]

आदेश

क्रा० अा० 4211.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची]

क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र की, श्री नरद किशोर बाल्मीकी को 21 जुलाई, 1970 को और उसके पश्चात् प्रति वर्ष 21 जुलाई, को वेतन-वृद्धि न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-12012/73/75-डी०/2ए]

ORDER

S.O. 4211.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank in not granting increment to Shri Nand Kishore Balmiki on 21st July, 1970 and subsequently on 21st July every year is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/73/75/D-II/A.]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

आदेश

का० प्रा० 4212.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, मुम्बई के लिपिक श्री धार०बी० पटवर्धन द्वारा 8 जनवरी, 1975 को दिया गया त्यागपत्र स्वेच्छा से था और क्या उसे प्रबन्धतन्त्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या० एल 12012/69/75-डी०-2ए]

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1975

S.O. 4212.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the United Western Bank Limited, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the resignation letter given by Shri R. V. Patwardhan clerk of the United Western Bank Limited, Bombay on 8th January, 1975 was voluntary and whether the same was accepted by the Management? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/69/75/DII/A]

78GI/75—7

आदेश

का० प्रा० 4213.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ पटियाला से संबद्ध नियोजकों और कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच०आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय लुडियाना में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला, पटियाला के प्रबन्धतन्त्र का, उक्त बैंक की मेहम शाखा के सहायक-रक्षक श्री मागहर सिंह की सेवाएं 18 फरवरी, 1975 से समाप्त करना व्यापोजित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-12012/72/75-डी० 2ए]

ORDER

S.O. 4213.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Patiala and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

Whether the management of State Bank of Patiala, Patiala is justified in terminating the services of Shri Magher Singh, Armed Guard of the Meham Branch of the said Bank with effect from the 18th February, 1975? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/72/75/DII/A]

आदेश

का० प्रा० 4214.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ लुडियाना से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के०एन० श्रीवास्तव होंगे जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबन्धतंत्र का श्री नरेन्द्र सिंह लेखा-एवं-रोकड़ लिपिक, पीलीभीत, की सेवाएं 18 अप्रैल, 1973 से समाप्त करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल०-12012/135/73-एल०आर०-3]

ORDER

S.O. 4214.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. N. Srivastava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of Baroda was justified in terminating the services of Shri Narendra Singh, Accounts-cum-cash clerk, Pilibhit, with effect from the 18th April, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/135/73/LRIII]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4215.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सेंधी होंगे जिनका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के प्रबन्धतंत्र की उक्त बैंक के अद्वैत बाजार पटियासा स्थित शाखा के दफ्तरी एवं क्लरासी श्री करतार सिंह को लिपिक के रूप में प्रोन्नति न देने की कार्यवाही सेवभावपूर्ण और अनुचित अम-व्यवहार का कृत्य है? यदि ऐसा है तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल०-12012/81/75-ओ-2ए]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1975

S.O. 4215.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in denying promotion to Shri Kartar Singh, Daftri-cum-Peon, Adalat Bazar, Patiala of the said Bank as clerk is an act of discrimination and unfair labour practice? If so to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/81/75/DII/A]

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4216.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to Ruby General Insurance Company Limited Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd September, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A., LL.B., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 8 of 1970

BETWEEN

Workmen of Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch.

AND

Management of Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch.

APPEARANCES :

Sri M. Panduranga Rao, Advocate—for Workmen.

Shri B. K. Seshu, Hony. Secretary, Federation of A. P. Chambers of Commerce & Industry—for Management.

AWARD

This dispute is now before me for adjudication as per an order of remand dated 4-11-1974 passed by the High Court of Andhra Pradesh for reconsideration of the question whether the claimant should be reinstated in service or payment of compensation could be the adequate consequential relief.

2. Facts necessary for the disposal of the question now in issue briefly stated are these :—The petitioner claimant joined the service of the Respondent—Company in March, 1958 as a Typist-cum-Clerk. He was later promoted as Accountant in the year 1962. His services were terminated with effect from 2-9-1968. On a direction issued by the High Court, the Government of India referred the following question for adjudication by the Industrial Tribunal at Hyderabad.

“Whether the Management of the Ruby General Insurance Company Limited was justified in terminating the services of Shri M. Vishwanath, a workman of the Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch with effect from the 2nd September,

1968? If not, to what relief is Shri M. Vishwanath entitled?"

3. The reference was registered as Industrial Dispute No. 8 of 1970 and notices were directed to both the parties. The workman filed a claim statement inter alia alleging his appointment in the month of March, 1958 as Clerk and his promotion as an Accountant on 1st November, 1962 by the Respondent. On promotion as an Accountant, he was drawing Rs. 175.00 per month. He received increments from time to time and was drawing a sum of Rs. 425.00 as on the date of termination. It is however alleged that an increment of Rs. 40.00 ordered to be paid on 26-5-1967 was not given effect to. The Branch Manager of the Hyderabad Branch, Sri Preetam Singh, is said to have taken utter dislike to him, and wrote false complaints against him to the Head Office. Out of malice the said Branch Manager got him transferred to Aurangabad on 1-7-1968. The transfer is characterised as a mala fide one and intended to harass the Petitioner. The Petitioner however joined service at Aurangabad but the Branch Manager got an Order issued by the Divisional Manager on 2-9-1968 terminating the services of the Petitioner with immediate effect. This order was received by the Petitioner on 6-9-1968. It is contended that though this purported to be an order of termination it was in effect a cloak for dismissal, as by a letter dated 17 March, 1968, Several allegations of misconduct were said to have been made against the Petitioner. No opportunity was given to him to refute the allegations. The order that followed is said to be violative of principles of natural justice and illegal. As per the contract of employment, the Management is said to have no power to pass an order of termination with one month's notice. The order, is therefore said to be void and illegal. The petitioner is said to have addressed a letter dated 27th September, 1968 asking for the details of allegations so that he could answer them. But by a letter dated 5th October, 1968 the Divisional Manager is said to have informed him that his services were properly terminated and that the petitioner can collect his dues from the Branch Office after signing the vouchers. On 14-10-1968 the Petitioner was served with the letter purporting to have been issued on 6th September, 1968 that in all a sum of Rs. 825.00 would be paid to him. The Branch Manager insisted that the Petitioner should sign the final settlement Memo which the Petitioner refused and he addressed a letter to the Divisional Manager, Bombay on 16-10-1968. To this a reply was sent to him stating that any further correspondence would not be replied at all. It is contended that the notice pay was not paid as part of the same transaction of termination and therefore, the order of termination is illegal. It is also contended that the said order is the outcome of personal malice which the Branch Manager bore against the Petitioner. It is thus contended that the Petitioner is entitled to reinstatement.

4. In the counter filed by the Respondent, it was contended that the Petitioner was employed mainly in a managerial capacity as Incharge of the accounts of the Branch Office and he thus not being a workman, the Industrial Disputes Act has no application and the Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the reference. It is, however, conceded that at the time of the termination the Petitioner was incharge of the accounts section and was drawing emolument amounting to Rs. 425.00. As regards the increment of Rs. 40.00 referred in the claims statement it is urged that though the Branch Manager with good faith recommended the said increment, the Head Office rejected the same as the Petitioner was not entitled to it. It is denied that the Branch Manager bore any ill-will towards the Petitioner or that he made any complaints against him to the Head Office. It is also denied that on account of the malice of the Branch Manager, the Petitioner was transferred to Aurangabad on 1-7-1968. The order of termination dated 2-9-1968, was a termination simpliciter and was done in pursuance of the inherent right of the Management. It is denied that it was a cloak for dismissal or that it was on account of any allegations of misconduct. It is contended that in spite of many allegations against the Petitioner opportunities were afforded to him and the Petitioner was warned from time to time. The termination order is said to be in no way violative of principles of natural justice. The Management is said to have the power to pass such an order with one month's notice, and it accordingly passed a proper termination order stating that he can collect the dues from the Branch. It is denied that the Branch Manager insisted upon the Petitioner to sign any final Settlement memo. It is also denied that the termination order was the outcome of the malice of the Branch Manager. It is averred that the

Petitioner was treated by the Company very well but he started making false allegations against the Branch Manager itself. The Petitioner was advised from time to time to rectify his behaviour. The allegations made by the petitioner were said to have been enquired into by the Divisional Manager and they were found to be baseless. The warning given to him was said to be of no avail. The Petitioner started neglecting his routine work and income tax returns were not submitted by him regularly. The Petitioner gave advances to the staff members without the prior permission of the Branch Manager. The amounts were not deposited in the Bank from time to time regularly. A Memo was issued to him on 7-10-1967 to which the Petitioner replied on 11-10-1967. The language and the tenor of the reply is said to border upon in subordination for which disciplinary action could have been taken but the Management gave another opportunity to the Petitioner to improve. On transfer to Aurangabad, the Petitioner, instead of attending to the business of the Company and improving the same, is said to have picked up quarrels with M/s. Kailash Motors, Aurangabad, a valuable client of the Company which was giving a premium of Rs. 1,50,000.00 a year. The said Kailash Motors wanted the Petitioner to be transferred from that place. As the Respondent could not afford to lose the business at Aurangabad the Petitioner was asked to get back to Hyderabad and await further orders. But instead, he went to Bombay ignoring the instructions given to him by the Divisional Manager. It is thus contended that in view of the past conduct and behaviour the Management lost confidence in the Petitioner particularly when he was in charge of a responsible post of the Company. Instead of making it difficult for a petitioner to get an alternative employment, the Management considered it fit to terminate his services by way of termination simpliciter. Even after the termination the Petitioner is said to have indulged in writing articles defaming the character of the Branch Manager and undermining the reputation of the Company and its officers. In view of the alleged loss of confidence it was contended that the Petitioner is not entitled to any reinstatement. It was also urged that the Management was ready and willing to prove the charges levelled against the Petitioner before the Tribunal. Thus the claim was sought to be rejected.

5. The claimant-workman examined himself as W.W.1 and relied upon Exs. W1 to W13 by way of documentary evidence. In rebuttal the Branch Manager of Hyderabad Branch was examined as M.W.1 and the Divisional Manager of Bombay was examined as M.W.2 and Exs. M1 to M31 were relied upon by way of documentary evidence.

6. The Tribunal in the first instance held that the order of termination was bad, but instead of the order the reinstatement of the workman, it held that the Respondent should pay compensation of Rs. 4,887.50 together with a sum of Rs. 425.00 to the claimant. Aggrieved by this award the workman filed Writ Petition No. 5429 of 1972 contending that he is entitled to be reinstated. The operative portion of the order of the High Court in the Writ Petition is as follows:—

"I have already pointed out that the Tribunal must take an overall picture of the situation and consider fairly and objectively all the circumstances in favour of and against reinstatement. Since that has not been done in the present case the award of the Tribunal is quashed to that extent and the Tribunal is directed to reconsider the question whether the Petitioner should be reinstated in service or payment of compensation only should be ordered."

7. The question holding the dismissal order being bad having become final, the only point for consideration is whether the reinstatement of the workman should be ordered or the Respondent should be ordered to pay compensation only. After remand the workman has examined W.W.2 in further oral evidence. But the Management was content with the evidence already on record.

8. The law is well settled that on setting aside the dismissal order or the termination order, the employee is entitled for reinstatement. It is true that in exceptional cases where reinstatement cannot be ordered payment of compensation is the other alternative. The question therefore is whether there exist exceptional circumstances to make a departure from the ordinary rule of ordering reinstatement. His Lordship Chinnappa Reddi J. has set out in the order of

remand the factors to be considered cumulatively, for and against the claimant bearing in mind the underlying principle of industrial adjudication that the workman is entitled to the security of his tenure unless there are strong grounds which go against him. The factors in favour of reinstatement are therefore the following :

1. The ordinary rule of reinstatement.
2. The service of 10-1/2 years put in by the claimant.
3. The grant of regular increments from time to time upto the date of termination.
4. His promotion in July, 1968.
5. The circumstance that his integrity was never doubted and last but not the least the absence of any prospect of his appointment as the claimant has crossed the age of 40 years.

It was on the other hand contended by the Management that the claimant was working as an Accountant in a small establishment and he was holding a post of confidence but in that capacity he abused his powers and paid advances without the sanction or permission of the Branch Manager for which he was issued a Memo. Similarly in the capacity of an Accountant though there was a duty cast upon the claimant to submit the income tax returns, he defaulted in submitting them and this has caused untold inconvenience to the Branch. The claimant was also in the habit of proceeding on leave without prior sanction which was a breach of the discipline. Lastly the performance of the claimant at Aurangabad in connection with Kailash Motors jeopardised the interests of the Company, in the sense that on account of the claimant not keeping good relations with the said Motors, the Insurance Company was faced with the risk of losing a very valuable customer. All these circumstances led to the loss of confidence. It was thus contended that the reinstatement of such a workman is neither just nor reasonable.

9. Before advertng to the consideration of the above circumstances for or against the claimant in detail, a contention put forward on behalf of the workman deserves consideration. The arguments was that the Branch Insurance Office at Hyderabad is a commercial establishment within the meaning of Section 2(5) of the Shops and Establishments Act. M.W.1 though confronted with this aspect was not in a position to deny or affirm whether this branch was registered under the Shops and Establishments Act. However it can be said that the Insurance Establishment either it be a Branch or a Head Office is a commercial establishment within the meaning of Section 2(5) of the Shops and Establishments Act. Section 40 of the said Act lays down that the termination of the employees services can be made atleast with one month's notice in writing or wages in lieu thereof. The contention of the learned counsel for the workman is that orders of termination can both be of void and voidable nature. The first category of cases cover those which are void on account of the non-compliance of the above referred to provisions of Section 40. The latter type of cases take into their habit such cases where the termination order is held to be bad for want of proper domestic enquiry or otherwise. In cases of void orders of termination, it is contended that reinstatement follows automatically. As to the scope of Section 40 the learned counsel for the workman relied upon the judgment of Andhra Pradesh High Court rendered by his Lordship Chinnapa Reddi J. in Writ Petition No. 705 of 1973. Dealing with Section 40 of the Shops and Establishments Act it was observed :

"Where the prescribed notice is not given there can be no termination of service without payment of wages etc."

In the instant case it is contended that under Ex. W9, the order of termination, all that is said is that the workman will paid one month's notice salary in lieu of notice together with legitimate dues, but while passing the termination order the actual payment was not made. Thus the contention proceeded that as the one month's wages were not paid along with the termination order the said Order is void. It was on the other hand contended by the learned counsel for the Management that this contention is, now being raised

for the first time after remand and that as the same was not raised in the Writ Petition the workman is precluded from raising the same. Assuming that in view of the void, nature of the order reinstatement is to follow automatically, I would now proceed to consider the circumstances whether reinstatement could be ordered or compensation would be the proper remedy.

10. The contention of the Management was that before the claimant was sent to Aurangabad after some training at Bombay he was working as an Accountant which was post of confidence and that he was abused the trust reposed in him. It is alleged that without the sanction or permission of the Branch Manager he advanced amounts to the other staff members. The claimant when cross examined would however admit that without the sanction of the Branch Manager he advanced those amount only to the Peons. Though the workman would put it that he was not an Accountant, in one of his letters with regard to promotion i.e. in Ex. M 9, it is admitted by him that he was asked to handle the accounts independently; In the Memo Ex. M 1 and M 3 his designation is shown as an Accountant. From Ex. M 3 it is clear that the Branch Manager has issued a Memo on 21-10-1967 calling upon the claimant to explain as to why he paid the advances to all the staff members. Thus the payment of advances without the permission of the Branch Manager by the claimant in his capacity as an Accountant goes established. Under Ex. M 1 a Memo was issued to the claimant calling upon his explanation as to why the income tax returns are not filed by him. Ex. M 2 is the explanation given by the claimant. Under Ex. M 4 dated 23rd April, 1968 the claimant was called upon to give his explanation as to why premium amount of Rs. 820.00 received from Autofin Limited was not deposited in time. Ex. M 5 is a letter from the Divisional Manager dated 10th July 1968 calling upon the claimant as to why he proceeded on leave before obtaining prior permission for the same. These were the Memos given and explanations called before the claimant was posted to Aurangabad. I may incidentally refer that in the year 1967 though an additional increment was recommended by the Branch Manager M.W. 1, the Head Office has turned down the said recommendations. In that context the claimant addressed a few letters to the Divisional Manager. I need not advert to that correspondence for the purpose of the question now in issue. What was contended by the Management is though action could have been taken with regard to the above lapses on the part of the claimant yet it refrained from doing so and instead posted him at Aurangabad, whereafter due to the failure of the claimant to have good relations with Kailash Motors, the Company was exposed to the risk of losing a valuable customer or client. Though it is the contention of the workman that Kailash Motors took an unhelpful attitude towards him as he did not agree for certification of a false claim with withregard to the damage to a tractor etc., it certainly emerges that the Divisional Manager of this Company had to tender an apology to the said Kailash Motors. It also emerges that the relation of this claimant with Kailash Motors were no way helpful to the Insurance Company. Ex. M 22 is a letter addressed by the Divisional Manager to the claimant wherein it is recited that the claimant instead of creating goodwill and procuring other business through the influence of Kailash Motors, he made a mess and spoiled the business relations with Kailash Motors. We are not now on the question whether the stand of the claimant was correct or that out of oblique motive the Kailash Motors took an antagonistic stand against the claimant. It can nevertheless be said that the Management of the Insurance Company was exposed to risk of losing a valuable client on account of the claimant not keeping good relations with them. Under Ex. M 31 dated 28th August 1968 the Divisional Manager of this Company had to tender an apology to Kailash Motors for the misconduct of the claimant. These circumstances are urged by the Management as leading to the loss of confidence. It was on the other hand contended by the workman that even according to M.W. 2 the posting of the claimant at Aurangabad was a working promotion to him and that even prior to that, the Divisional Manager has stated in Ex. M 23 that the integrity of the claimant was never doubted. It is true that in Ex. M 23 a letter addressed by the Divisional Manager to the claimant it stands noted that his (claimant's) honesty was never doubted. But in the following sentences it is also recited that he did not like the manners of the claimant. It is further stated therein that if the claimant cannot pull on with the Manager Preetam Singh, the claimant was 'welcome to resign'. It is also the evidence

of M.W. 2 that though the claimant was sent to Aurangabad as his services as an Accountant were satisfactory, it is also his evidence that he was not satisfied with the claimant's general conduct and integrity. It was also urged by the learned counsel for the workman that the claimant was sent to Aurangabad after regular increments being given and admittedly it was a case of working promotion; if so the prior Memos of explanations called for cannot be now pressed into service to show that there was loss of confidence. In support of his contention that the earlier unsatisfactory conduct cannot be looked into, he relied upon the judgement of the Supreme Court reported in Service Law Reporter 1970 page 375. It was held therein that:

"The adverse confidential reports earlier to the crossing of the efficiency bar cannot be used in enquiry against the employee."

The further observations of this ruling are as follows:—

"It is unthinkable that if the authorities took any serious view of the charge of dishonesty and in efficiency contained in the confidential reports of 1941-42, they could have overlooked the same and recommended the case of the officer as one fit for crossing the efficiency bar in 1944."

Relying upon the above observations it was contended that the adverse memos issued to the claimant prior to his posting at Aurangabad have to be eschewed from consideration and that the Management cannot fall back upon them. Similarly the facts of the Supreme Court ruling reported in A.I.R. 1975 page 661 were relied upon to show that where increments are given or promotion is given, as appreciation of the hard working, the plea of the Management that the conduct of the workman prior to the said date led to the loss of confidence stands demolished by the very factum of granting increment or promotion. I may however note that the question of loss of confidence have to be decided on the facts of each case. It might be that even though the earlier conduct of the claimant was not very satisfactory, the fact that the Management went on giving him increments and also gave a working promotion to him by posting him at Aurangabad, would suggest that the Management was not serious in taking any action against him or at any rate the so called lapses were not such which made the Management to get rid of the employee. It is equally possible that as the claimant was not pulling on well with the Branch Manager, the Divisional Manager thought it fit to post him at Aurangabad and thus further the business prospects of the company. To my mind the Management did not treat the earlier conduct or the performance of the claimant as unsatisfactory. It might be that his general manners were not liked by the Divisional Manager but since his integrity was not doubted, his continuance in service was not only acquiesced but by posting him to Aurangabad the Company certainly wanted to press his services for its business prospects. Though it was the contention of the learned counsel for the workman that as to what happened to Kailash Motors at Aurangabad resulting in a strained relationship between the claimant and the said Motors the Management has not lead any evidence, I have already noted above that the Company stood exposed to the risk of losing a valuable client. It might be that the claimant was justified in his stand but in judging the question of loss of confidence it is the opinion formed by the employer about the suitability of the employee for the job assigned to him that is relevant even though erroneous. But if the opinion formed by it is bona fide, such an opinion is final. In the light of the correspondence referred to above wherein the Divisional Manager has to apologise to the Kailash Motors, it can only be said that the opinion formed by him about the claimant's performance is a bona fide one, though when the whole matters comes up for judicial scrutiny the stand of the Management may not be justifiable. But it can be repeated that as to the suitability of the employee the judgment of the employer if bona fide, is not subject to review by industrial adjudication. This position has to be reached in the light of the judgment of the Supreme Court reported in AIR 1972 page 1343. The question now is whether on account of this incident can it be said that the claimant has forfeited his right to continue in service. It is true that the Management was faced or was exposed to the risk of losing a valuable client who was giving business turn over of Rs. 1,50,000.00 and odd per year. But when the Management has decided to put the claimant at Aurangabad, there itself it exercised his discretion wrongly. I do

not mean to make any observations about the judgment of the Management but it can yet be said that it was putting a square peg in a round whole. The choice of putting the claimant at Aurangabad does not appear to be a judicious one. But the point is whether the workman has forfeited his right to continue in service. It can incidentally be noted that the Management contends that subsequent to the dismissal the claimant admittedly handed over two articles contained in Ex. M 6 and M 7 which contain slanderous material about the working of this Insurance Company. W.W. 1 would admit having passed them to M. W. 1 to the Branch Manager. From this admission it cannot be said that W.W. 1 the claimant herein was the author of these articles. As noted above after remand W.W. 2 is examined to show that these two articles were written at his instance by his distant relative Mr. Andrews. It is true that there is nothing in these articles to show that Mr. Andrews was their author. Equally there is nothing to show that the evidence of W.W. 2 (Mr. K. D. Xavier an erstwhile Clerk in this very Branch and who is said to have been beaten by M.W. 1 as noted in one of the complaints made by the claimant to the Divisional Manager), is unreliable or unworthy of trust. That apart, the two articles relate to a period long after the termination order and for if any reason the claimant thought it fit, even in a revengful mood to hand over the articles containing slanderous matters regarding the working of the Insurance Company, that conduct of the claimant cannot be said to be detrimental to the interest of the Company. Thus noting the factors for and against reinstatement the one circumstance that stores against the claimant is his unsatisfactory performance at Aurangabad. As against it, his integrity was never doubted, though his general manners were felt to be not pleasing. It can as well be said that any lapses on his part prior to his being posted at Aurangabad were condoned by the Management. The claimant has put in nearly 10-1/2 years of service. He is now about to cross the age of 40. It can also be said that the prospects of his seeking a job with similar emoluments is remote. It can be noted that even though he was holding the post of an Accountant in a small establishment like Branch Office and also committed some breaches, those lapses were not viewed seriously by the Management. The underlying principle of industrial adjudication is to ensure security of tenure of a workman. Above all the normal rule on setting aside the termination order is that of reinstatement. Since it is not shown by the Management that one month's wages as required by Section 40 of the Shops and Establishments Act were paid along with the order of termination that termination order is void and this also entails reinstatement. But the conduct of the claimant at Aurangabad immediately preceding the order of termination was in no way helpful may positively prejudicial to the interest of the Company. Having regard to all the circumstances discussed above, I am led to order the reinstatement of the claimant but with only 1/3rd back wages.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 26th day of August, 1975.

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined for Workmen :

W.W.1 M. Viswanath
W.W.2 K. D. Xavier

Witnesses Examined for Respondent :

M.W.1 Preetam Singh
M.W. 2 J. B. Setalwad.

Documents Exhibited For Workmen :

- Ex. W1 Letter dt. 1-5-68 from the Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Camp, Hyderabad addressed to M. Vishwanath.
Ex. W2 Letter dt. 28-5-68 of M. Vishwanath.

- Ex. W3 Letter dt. 3-6-68 from the Divl. Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.
- Ex. W4 Letter dt. 10-8-68 from M. Vishwanath addressed to Jagdishbhai.
- Ex. W5 Letter dt. 10-8-68 from M. Vishwanath addressed to the Motor Claims Department, Divisional Office, Bombay.
- Ex. W6 Letter dt. 12-8-68 of M. Vishwanath addressed to Srivyas.
- Ex. W7 Letter dt. 17-8-68 addressed to Sri Vyas.
- Ex. W8 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to M. Vishwanath.
- Ex. W9 Letter dt. 2-9-68 of Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Sri M. Vishwanath.
- Ex. W10 Certified copy of the order of the High Court in W.P. No. 2138 of 1969 dt. 5-12-1969.
- Ex. W11 Letter dt. 11-7-67 of M. Vishwanath addressed to J.B. Setalwad, Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay.
- Ex. W12 Letter dt. 15-8-63 of M. Vishwanath and copies to Preetam Singh.
- Ex. W13 Agreement dt. 28-11-63 arrived at between Ruby General Insurance Company Limited, Bombay Office, Bombay and Its staff members effective for five years from 1-1-1963 to 31-12-1967.

Documents Exhibited for Respondent :

- Ex. M1 Memo dt. 7-10-67 of Branch Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad addressed to M. Vishwanath.
- Ex. M2 Reply of M. Vishwanath dt. 11-10-67 to Ex. M1 i.e. to the Branch Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad.
- Ex. M3 Memo dt. 21-10-67 of Branch Manager, addressed to M. Vishwanath.
- Ex. M4 Memo dt. 23-4-68 of Branch Manager addressed to M. Vishwanath.
- Ex. M5 Copy of the letter of Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay dt. 10-7-68 addressed to M. Vishwanath at Aurangabad
- Ex. M6 Leader News Paper dt. 6-7-69 in which the Ruby General Insurance Company's affairs contains
- Ex. M7 Leader News Paper dt. 10-7-69 in which it contains the Ruby General Insurance Company's affairs.
- Ex. M8 Letter dt. 29-12-65 from M. Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay
- Ex. M9 Letter dt. 23-5-67 of M. Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.
- Ex. M10 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, addressed to Vishwanath.
- Ex. M11 Letter dt. 10-7-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay to Vishwanath.
- Ex. M12 Letter dt. 2-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Vishwanath.
- Ex. M13 Letter dt. 29-6-67 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay to Vishwanath.
- Ex. M14 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Sri S. C. Bafua Kailash Motors, Aurangabad.

- Ex. M15 Letter dt. 6-9-68 of Vishwanath.
- Ex. M16 Copy of the letter dt. 6-9-68 of Branch Manager, Hyderabad to Vishwanath.
- Ex. M17 Letter dt. 16-8-67 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Vishwanath.
- Ex. M18 Letter dt. 6-9-67 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.
- Ex. M19 Letter dt. 8-3-66 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.
- Ex. M20 Letter dt. 22-3-1966 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.
- Ex. M21 Letter dt. 28-3-1966 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, addressed to Vishwanath.
- Ex. M22 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.
- Ex. M23 Letter dt. 2-6-1967 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.
- Ex. M24 Letter dt. 12-8-1967 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad.
- Ex. M25 Letter dt. 16-8-1967 of J. B. Setalwad addressed to Vishwanath.
- Ex. M26 Letter dt. 6-9-1967 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad.
- Ex. M27 Letter dt. 16-9-1967 of J. B. Setalwad to Vishwanath.
- Ex. M28 Letter dt. 2-6-1967 of Setalwad to Preetam Singh.
- Ex. M29 Letter dt. 10-8-1968 of S.C. Bafna, addressed to J. B. Setalwad.
- Ex. M30 Letter dt. 12-8-1968 of S. Bafua. Kailash Motors, Aurangabad addressed to M/s. Ruby General Insurance Company Limited, Bombay.
- Ex. M31 Letter dt. 20-8-1968 of J. P. Setalwad addressed to S. C. Bafna.

T. NARSINGH RAO, Presiding Officer

[No. F. 10/2/70-LRI]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1975

कां.प्र. 4217.—केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एमको गोवा (प्राइवेट) लिमिटेड मारगाओ (गोवा) और मैसर्स सेटको प्रोसेस (प्राइवेट) लिमिटेड, मारगाओ (गोवा) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना बांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स एमको गोवा (प्राइवेट) लिमिटेड (गोवा) और मैसर्स मेटको ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (गोवा) की, श्री विठ्ठल आनन्त सावन्त, पर्यवेक्षक की सेवाएं 7 दिसम्बर, 1974 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[संख्या एल-26012/7/75-डी-4-बी०]

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1975

S.O. 4217.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Emco Goa (Private) Limited, Margao (Goa) and Messrs Metco Ores (Private) Limited, Margao (Goa) and their workman in respect of the matters specified in the Schedule here to annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No.2), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Emco Goa (Private) Limited (Goa) and Messrs Metco Ores (Private) Limited (Goa) in terminating the services of Shri Vithal Anant Sawant, Supervisor with effect from the 6th December, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-26012/7/75—D—IV.B]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4218.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर कॉम्पलेक्स की मोसाबोनी माइन्स के प्रबंध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर कॉम्पलेक्स की मोसाबोनी माइन्स के प्रबंधतंत्र की, श्री एम० सी० घोषाल, स्फोटक (ब्लास्टर) को 22-7-1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-29011/58/74-एल ग्रा 4/डी-4बी]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1975

S.O. 4218.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No.2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited in dismissing Shri M.C. Ghosal, Blaster with effect from 27-7-1974 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/58/74—LR-IV/D-IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4219.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के अधीन ठेकेदार-मैसर्स माडर्न कन्स्ट्रक्शन कन्सर्न, डाकघर बाबिल जिला केओझार से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के अधीन ठेकेदार मैसर्स माडर्न कन्स्ट्रक्शन कन्सर्न, डाकघर बाबिल, जिला केओझार, की निम्नलिखित कार्यवाहियां न्यायोचित थीं?

(1) 19 फरवरी, 1975 से आत्माराम गौड़, घनिक की पदच्युति।

(2) ठाकुरानी खान, स्थित अपने स्थापन से मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड की बोलानी लौह अयस्क खान स्थित अपने स्थापन में सर्वश्री रमेश मुण्डा, लखन गोप और मधुरा दास, खनिकों का 26 फरवरी, 1975 से स्थानान्तरण और बाद में 12 मार्च, 1975 से उनकी सेवायें की समाप्ति। यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[फाईल संख्या एल-26012/8/75-डी-4 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4219.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs Modern Construction Concern, contractors under the Messrs Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the following actions of Messrs Modern Construction Concern, Contractors under Messrs Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar were justified ?

- (1) Dismissal of Shri Atmaram Gond, Miner with effect from 19th February, 1975.
- (2) Transfer of Sarvashri Ramesh Munda, Lakhna Gope, and Mathura Das, Miners with effect from 26th February, 1975 from their establishment at Thakurani Mines to their establishment at Bolani Iron Ore Mines of Messrs Bolani Ores Limited and subsequent termination of their services with effect from 12th March, 1975.

If not, to what relief are the workmen entitled ?

[F. No. I.—26012/8/75—DIV(B)]

आदेश

का० प्रा० 4220.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल के भारत रयाना हक्ला आयरन और माइन्स हास्पेट के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भागवत होंगे, जिसका मुख्यालय बंगलूर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल की भारत रयाना हक्ला आयरन और माइन्स, हास्पेट के प्रबंधन की, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ब के उपबन्धों का अनुपालन किए बिना श्री बी० वेनकप्पा शैट्टी की सेवाएँ समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-26012/9/75-डी-4-(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी, (विशेष)

ORDER

S.O. 4220.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G.S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bharat Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet, in terminating the services of Shri V. Venkanna Chetty without complying with the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947, was justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-26012/9/75-D-LV(B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4221.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड की जामादोबा कोलियरी, डाकघर जामादोबा, जिला धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड की जामादोबा कोलियरी, डाकघर जामादोबा, जिला धनबाद के प्रबंधन की, श्रीमती सरस्वतिया, राजगीर कामिन, टिकट संख्या 26440 को, 15 मार्च, 1975 से अधिवर्षिता के कारण सेवा निवृत्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष की हकदार है ?

[संख्या एल-20012/125/75-डी-3-ए]

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1975

S.O. 4221.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Jamadoba Colliery of Messrs. Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, in superannuating Smt. Saraswati, Mason Kamin, Ticket No. 26440, from service with effect from the 15th March, 1975 is justified? If not, to what relief is the worker entitled?

[No. L-20012/125/75/D.IIIA.]

आदेश

का० प्रा० 4222—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग लिमिटेड की भाटडी कोलियरी, डाकघर-मोहुदा, जिला धनबाद के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद के न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की भाटडी कोलियरी, डाकघर मोहुदा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र का, श्री लाल बिहारी सिंह, रात्रि रक्षक को पदच्युत करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्म-कार किम अनुतोष का हकदार है और किसे तागेछ से ?

[संख्या एल-20012/158/74-एल-आर०-2/डी 3ए]

एल० के० नारायणन्, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 4222.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad, are justified in dismissing from service Shri Lal Bihari Singh, Night Guard? If not, to what relief is the said workmen entitled and from what date ?

[No. L-20012/158/74/LR II/D IIIA]

L. H. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

77 GI/75--8

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4223—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में छावनी बोर्ड, बरेली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है—

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ।

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० एन० श्रीवास्तव होंगे, जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा, और उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या छावनी बोर्ड, बरेली की, श्री लालता प्रसाद को सफाई निरीक्षक के बजाय सहायक सफाई निरीक्षक के रूप में बहाल करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-13012 (1)/75-डी-2 बी]

New Delhi, the 14th August, 1975

ORDER

S.O. 4223.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Cantonment Board, Bareilly and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. N. Srivastava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Cantonment Board, Bareilly in reinstating Shri Lalta Parshad as Assistant Sanitary Inspector instead of as Sanitary Inspector, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L—13012(1)/75—D.IIB]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4224—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ,

मतः, अथ, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क-के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

यथा मुख्य इंजीनियर नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रबन्धतंत्र को, श्री लालजी राय, आकस्मिक कर्मकार (तलमाज) की सेवाएं 3-9-74 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-42012/15/75 डी०-2बी०]

New Delhi, the 18th August, 1975

ORDER

S.O. 4224.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Public Works Department and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Public Work Department under the Engineer-in-Chief, New Delhi, in terminating the services of Shri Laljee Rai, a casual workman (Plumber) with effect from 3-9-1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-42012/15/75—D.HB]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का० ग्रा० 4225.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 22 मार्च, 1975 के पृष्ठ 1217 पर प्रकाशित भारत सरकार, धर्म मंत्रालय की अधिसूचना की संख्या का० ग्रा० 909, तारीख 11 मार्च, 1975 में—

“करार” शीर्षक के अन्तर्गत; विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषयों से संबंधित मद् (1) में, “1-12-74” के लिए “1-12-73” पढ़िए

[संख्या एल-42012(7)/75-डी०2 (बी)]

New Delhi, the 5th September, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 4225.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 909 dated the 11th March, 1975 published on pages 1217 and 1218 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd March, 1975—

Under the heading “Agreement”, in item (i) relating to specific matters in dispute, for “1-12-74” read “1-12-1973”.

[No. L-42012(7)/75-D.2(B)]

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 4226.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam and their workman, which was received by the Central Government on the 10th September, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A. LL.B., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 20 of 1975

BETWEEN

Workman of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam.

AND

The Management, Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam.

Appearance :

(1) Sri A. Lakshmana Rao, Advocate for Workman.

(2) None for Management.

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour through notification No. L-14012(2)/75-D. 2(B), dated 29th May, 1975 referred the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam and their workman under Sections 10(1)(d) and 7A of the I.D. Act for adjudication by the Tribunal on the following issue :

“Whether the action of the Management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam in retrenching Shri R. George, Sub-clerk (Stores), with effect from 9-3-75 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?”

2. The reference was registered as I.D. No. 20 of 1975 and Notices were issued to the workman and to the Management. The workman filed a claims statement, inter alia alleging that he was appointed as Sub-clerk by the respondent Management on 13-5-1974 at Rs. 200 per month. In July, 1974 the respondent asked the workman to act as a Supervisor in the Department of shore pipe-line without changing his designation and pay. The Management is said to have kept the workman for months together under a promise that it would confirm his promotion and increase his pay. Thus the workman trusting the management discharged the duties of a Supervisor, accepting the salary of a Sub-clerk. It is alleged that the management though coming from a Socialist Country has been exploiting the workmen. In many of the pay slips the designation of this workman is said to have not been shown but in the Duty Fitness Certificate the workman is said to have been shown as supervisor. In the month of January, 1975 the workers of this Company are said to have gone on strike and struck the work for about 33 days. During the said period the workman co-operated with the management and discharged his duties as a Supervisor. Though he did not join the strike the management entertained a baseless suspicion that the workman was supporting the workers on strike and thus the management issued

an ousting order dated 7-3-75. According to the management the reason for ousting him is said to be the want of vacancy. The allegation of the want of vacancy is characterised by the workman as false and incorrect. That post of a Supervisor is given to Shri A. Appa Rao who is a junior to the claimant herein. In the order of ousting it is not mentioned that the claimant was retrenched nor the retrenchment compensation was offered to the workman. It is contended that the order of ouster amounts to dismissal and the said order is said to be illegal and mala fide and against the principles of natural justice. It is urged that the management has exploited this workman for more than 8 months without changing his resignation and paying lesser wages for his services as a Supervisor. His dismissal order is said to be the outcome of suspicion by the management that this workman has been helping the workmen on strike. He thus prayed for his reinstatement with full back wages.

3. In the counter filed by the management, it is alleged that the appointment of the claimant was as a Sub-Clerk (Stores) with effect from 13-5-1974 on temporary basis in the scale of Rs. 200-8-280. It is alleged that his services were utilised as Sub-Clerk (Stores) in Shore Pipe Line from July, 1974. The claim of the claimant-workman that he was acting as a Supervisor in the Shore Pipe Line, is denied. It is further contended by the management that as the post of Sub-Clerk in stores has been abolished, the claimant was ousted from service by paying the following benefits, viz. one month's pay, 15 days pay as gratuity, bonus at 10 per cent for the year ending on 31-12-1974. It is further contended by the management that the claimant was only doing the job of a clerical nature and that he had no technical skill which is required for the post of a Supervisor. The post of Supervisor requires either Civil Engineering qualification or Licentiate in Civil Engineering or experience of at least seven years in Road and Building Construction. The claimant is said to have had no such qualifications to be employed as a Supervisor. The designation of the claimant as a Supervisor shown in Duty Fitness Certificate is said to be the result of false representation to the Medical Unit. The designation entered therein is said to be the result of declaration made by the workman himself. It is thus contended that the self declaration is of no avail and does not bind the management. It is denied that the management suspected the bona fide of this workman during the period of strike by the other workmen. If it had been so it would have instituted a domestic enquiry. It is contended that the post of Supervisor of Shore Pipe Line is given to Mr. A. Appa Rao Reddy who held the necessary qualifications, which qualifications the claimant did not possess. It is contended that the claimant did not complete the qualifying service of one year yet the management gave him the benefits of gratuity, bonus and one month notice pay as stated earlier. In giving those benefits the management is said to have acted with magnanimity. It is also denied that the ousting order amounts to a dismissal. The ousting is said to have been ordered for want of vacancy and that the workman is not entitled to retrenchment compensation. It is also contended that the retrenchment compensation is to be paid to a workman who has completed one full year of service. It is thus denied that the order is violative of any principles of natural justice. The claim of the claimant is said to be vexatious and is intended to malign the management. The management has also withdrawn an alleged earlier offer to provide the workman with the job of Sub-Clerk in Stores Department in case of any vacancy arising therein. The claim of the workman is thus resisted.

4. In a rejoinder filed by the workman, the earlier pleas are reiterated. It is also contended that Mr. A. Appa Rao Reddy had no requisite qualifications but since during the strike period he arranged the supply of labour with the help of one contractor by name Prasad Rao, the management favoured him by appointing him as Supervisor even though he was a junior to the claimant herein. It is urged by the workman that he has completed his probation period without any blemish, and he has become a regular employee as per the Service Rules and Standing Orders of this Company. It is reiterated that from July onwards he was not a clerk but was performing the duties of a Supervisor till the date of his dismissal.

5. On receiving the counter on 21-7-1975 the case was posted for enquiry to 5-8-1975. Notices were directed to both the parties accordingly. On 5-8-1975 the workman was

present for enquiry but none was present for management in spite of service of notice of the date of enquiry. The enquiry was posted to 6-8-1975. On the said date also none was present for the management. As the workman came all the way from Visakhapatnam his evidence was recorded in the absence of the management. After recording his evidence the case was posted to 19-8-1975 for further enquiry, and a notice was again directed to the management intimating the stage of the proceedings and with the direction to it that it is at liberty to participate in the proceedings. That notice was also served on the management. But in spite of service the management was absent on 19-8-1975. The workman closed his evidence, and arguments were heard and the matter was reserved for award. After some time of the closing of the matter a representative of the management appeared. He was orally informed of the steps to be taken to enable him to reopen the matter. But in spite of advising him about the procedure to be followed he has not chosen to file any petition to reopen the matter. On the other hand a further counter statement dated 23rd August, 1975 is sent through post. In this additional counter the pleas raised in the counter are again reiterated. The further contention is that the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act is attracted to the facts of the case and therefore the suggestion is that the Tribunal has no jurisdiction to entertain this reference. It may be stated that there is no foundation for this contention as the workman is directly employed by the respondent-management and not through any contractor. This contention therefore fails.

6. I would now examine the evidence of the workman and decide whether he is entitled to any relief. The claimant in addition to examining himself as W.W. 1 in Oral evidence also relied upon Ex. W 1 to Ex. W 8 in documentary evidence. His version is that he was appointed on 13th May 1974 as Sub-Clerk in Stores but no appointment letter was immediately given to him. Ex. W 1 is the appointment letter showing his appointment with effect from 13th May, 1974. Significantly enough it does not contain the date of issue. As per the terms of appointment the probation was initially for a period of 3 months. Regardless of the fact whether he worked in the Stores as Sub-Clerk or in the Shore Pipe Line either as Sub-Clerk or otherwise, his total period of service exceeded more than nine months. It is not the case of the management that his probation was extended from time to time. While the management will put in that from July, 1974 the claimant worked as a Sub-Clerk in the Shore Pipe Line, the workman would allege that his services were taken as a Supervisor in that Department. If I may say to the question whether the claimant has worked as a Supervisor or he had no qualification to hold that post or whether any junior by name A. Appa Rao Reddy was appointed to that post are not questions really now in issue. According to the management the services of the workman were terminated because the post of a Sub-Clerk is no more available. Though the workman would put it that he has been working as a Supervisor, admittedly there is no appointment letter appointing him to the post of a Supervisor. It is true that in the Medical Fitness Certificate Ex. W.W. 4 issued by the Medical Officer the designation of the workman is shown as Supervisor of the Shore Pipe Line. It is not conclusive to say that the workman was working at that time as Supervisor in the Shore Pipe Line Department. In the pay slips Ex. W. 8 series all that is found noted is that the workman is in the Shore Pipe Line Department, his designation is not shown therein. The workman as W.W. 1 put it that his designation was purposefully omitted in the said pay slips. Be that whatever it may, in the absence of his regular appointment as Supervisor in the Shore Pipe Line Section, it does not appear that any relief can be granted to him treating him as a Supervisor in that section. It would certainly emerge from the admission of the management that the claimant was later working in the Stores of the Shore Pipe Line Section. The question is whether the original post of Sub-Clerk (Stores) is abolished which necessitated retrenchment of this workman. The evidence of W.W.1 is to the following effect :

7. "It is not true to say that the post of Sub-Clerk in which I was initially appointed is abolished and thus any retrenchment was necessitated. In fact Mr. Lakshman Rao is working in the same post of a Sub-Clerk but he is now designated as a helper.

8. At one stage he has deposed.

"Mr. Vijayan Pillai, Laxman Rao and Prakash Rao joined as Sub-Clerks subsequent to my appointment. Mr. Raju joined the service of the Company one and half months after I joined. All the above four persons who are juniors to me are still working in the company in the Stores Division. But the management deliberately divided that section in November, 1974 into stores Section and Workshop. In fact the workshop is a part and parcel of the Stores."

9. From the above evidence it is clear that the juniors to the claimant herein are still continuing in service and that Mr. Laxman Rao is working in the same post which was held by the claimant herein. But that post is designated as a Helper. I have already noted above that it is not the case of the management that the services of the claimant during the probation period were in any way unsatisfactory or that his period of probation has been extended. By mere changing the designation of a post of Store Keeper to that of a Helper or by dividing the section into two could not have resulted in the abolition of a post, when it is the version of the claimant W.W.1 that the same post continues under a redesignation of a Helper and that a junior to him is still continuing in that post. Though I have held that for the purpose of this dispute, it is not necessary to go into the question whether the claimant was really working as a Supervisor or not, suffice it to say that the termination of his services on the ground of abolition of a Sub-Clerk in the Stores remains unjustified. As the said post continues and is held by a junior, and though the said post is redesignated as Helper but is substantially the same, the ground for ousting the claimant cannot be said to be justified or reasonable. The one and the only reason given by the management for ousting the claimant is the want of vacancy. In the circumstances and in the light of the evidence it does not appear to be true. Hence the ousting of the claimant-workman in the light of the above evidence is held to be unjustified. He is thus entitled to be reinstated with full back wages. The reinstatement of the workman with full back wages is therefore ordered.

10. Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 28th day of August, 1975.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined

For Workmen :

W.W. 1 Shri R. George

Witnesses Examined
For Management :

NIL

Documents Exhibited for Workmen :

- Ex. W 1.—Appointment Letter of Shri R. George as Sub-Clerk (Stores).
- Ex. W 2.—Pay Scales of monthly paid employees and employees drawing above Rs. 500/- p.m. (Appendix I).
- Ex. W 3.—Letter of the Head of the Department dated 10-2-1975 addressed to Shri R. George (in Ugo-slavian Language).
- Ex. W 4.—Duty Fitness Certificate of Shri R. George issued by the Medical Officer. Ivan Milutinovic Pim on 3-3-1975.
- Ex. W 5.—Prescription of the Medical Officer Ivan Milutinovic Pim in respect of George's health.
- Ex. W 6.—Ousting Order of Shri R. George, temporary Sub-Clerk Shore Pipe Line w.e.f. 8-3-1975.
- Ex. W 7.—Standing Orders of M/s. Ivan Milutinovic Pim-1973.
- Ex. W 8.—Pay Envelop of Shri George for the month of August, 1974 for Rs. 191.15.

- Ex. W 8(a).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of September, 1974 for Rs. 199 only.
- Ex. W 8(b).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of October, 1974 for Rs. 257 only.
- Ex. W 8(c).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of May, 1974 for Rs. 208.95.
- Ex. W 8(d).—Pay Envelop (D.A.) of Shri R. George for Rs. 260 only.
- Ex. W 8(e).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of November, for Rs. 307 only.
- Ex. W 8(f).—Pay Envelop for Shri R. George for the month of December, for Rs. 354 only.

Documents Exhibited for Management :

NIL

T. NARSINGH RAO,, Presiding Officer

[No. L 42012(2)/75-D-2(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer, (Spl.)

प्रदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

क्रा० प्र० 4227.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाज्ज अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध प्रबन्धसंज्ञ का, श्री नमार्जु-हीन, इलेक्ट्रिक प्लांट लाइट अटैचमेंट, अपर रीजेंज रिसर्च स्टेशन फाल्टा की उसके अपने कर्तव्यों के प्रतिरिक्त आउट बोर्ड मोटर इंजनों और स्टेशन बैन की सर्बिसिंग और मरम्मत करने और फाल्टा स्टेशन स्थित पम्प चलाने के लिए विशेष वेतन देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?

[संख्या एल 32012/14/75 डी-II-ए]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4227.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in refusing special pay to Shri Namajuddin, Electric Plant Light Attendant, Upper Reaches Research Station, Falta for carrying out servicing and repairs of outboard motors engines and station Van and operation of pump at Falta Station in addition to his own duties? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-32012/14/75-D. IV(A)]

आदेश

का० प्रा० 4228—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायन्त्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कलकत्ता पत्तन-न्यास के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के अधीन कार्य करने वाले विद्युत् कर्मचारीबन्ध की निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हाँ, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची के हकदार हैं ?

मांगें

- (1) प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक पारी में 8 घंटों के स्थान पर 9 घंटे कार्य करने के लिए एक घंटे के अतिरिक्त भत्ते की मंजूरी।
- (2) ऊंचाई में तार बांधने तथा जलयान सैलों के लिए बाहर काम करने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- (3) केवल थोड़े से अर्थकुशल श्रमिकों के रूप में प्रोत्साहित किए जाने की वर्तमान स्थिति के विपरीत विद्युत् स्थापन ढाँचे में और अधिक अर्थकुशल श्रमिकों के पदों का सृजन।

[संख्या एल-32011/16/74-पी०डी०/सी०एम०टी०/डी-4(ए)]

ORDER

S.O. 4228.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following demands of the Electrical Staff working under the Chief Mechanical Engineer of the Calcutta Port Trust are justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled?

DEMANDS

- (i) Granting of one hour overtime to each of the workmen for performing 9 hours of duty in each shift instead of 8 hours.
- (ii) Arrangements of transport be made for overhead wiring and vessels gangs for working outside.
- (iii) Creation of more semi-skilled labour posts in electrical set up as against the present position of having only a handful of semi-skilled labour posts and unskilled labour being promoted directly to skilled labour.

[No. L-32011/16/74-PD/CMT/D-IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

का० प्रा०—4228 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायन्त्र अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इससे उपायन्त्र अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मोर्मगाबो बन्दरगाह (गोवा) में 12 नौकरों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची-1

1. मैसर्स एजेंसियां कार्मिगल मैरिटिमा, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
2. मैसर्स एजेंसियां अल्ट्रा मैरिना प्राइवेट लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
3. मैसर्स जोगुल ब्रदर्स, मोर्मगाबो बन्दरगाह (गोवा)।
4. मैसर्स शमोदर मंगलजी एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
5. मैसर्स एलेसब्रायों पेरोरा एण्ड संज, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
6. मैसर्स माचादो एण्ड सन्ध, एजेण्ड्स एण्ड स्टीविडोअर्स प्रा० लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
7. मैसर्स गोसालिया शिपिंग प्रा० लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
8. मैसर्स लिमा लिटाग्रों एण्ड कं० मोर्मगाबो बन्दरगाह (गोवा)।
9. मैसर्स मोर्मगाबो नावोदोरा लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
10. मैसर्स राजाराम बी० रेडिज, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
11. मैसर्स बी० एम० सालगाभोकर एंड ब्रदर्स, प्रा० लि०, वास्को-डी-गामा (गोवा)।
12. मैसर्स बी० एम० डेम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मोर्मगाबो बन्दरगाह (गोवा)।

अनुसूची-2

New Delhi, the 11th September, 1975

- (क) क्या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मोर्मुगाओ स्टेवडोरगाह (गोवा) के नीमरको की, श्री राजाराम कालुराम जैसवार, अस्थायी गैंग श्रमिक (रजिस्ट्रीकरण सं० सी० आर० डब्ल्यू-17) को 7 अक्टूबर 1974 से नियाजिन देने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ।

[संख्या एल-36012 (2)/75डी-4 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1975

S.O. 4229.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of 12 Stevedores at Mormugoa Harbour (Goa) specified in the Schedule I annexed hereto and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule II hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7 A of the said Act.

SCHEDULE

1. Messrs Agencia Commercial Maritima, Vasco-da-Gama (Goa).
2. Messrs Agencia Ultramarina Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
3. Messrs Chowgule Brothers, Mormugoa Harbour (Goa).
4. Messrs Damodar Mangalji and Company (Private) Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
5. Messrs Elcsbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama (Goa).
6. Messrs Machado and Sons, Agents and Stevedores Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
7. Messrs Gosalia Shipping Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
8. Messrs Lima Leitao and Company, Mormugoa Harbour (Goa).
9. Messrs Mormugoa Navegadora Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
10. Messrs Rajaram V. Redij, Vasco-da-Gama (Goa).
11. Messrs V. M. Salgaocar and Brothers Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
12. Messrs V. S. Dempo and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa).

SCHEDULE II

- (a) Whether the action of the Stevedores of Mormugoa Harbour (Goa) specified in Schedule I in refusing employment to Shri Rajaram Kaluram Jaiswar, Temporary Gang Worker (Registration No. C.R.W.-17) with effect from the 7th October, 1974 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-36012(2)/75-D-IV(A)]

S.O.4230.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to (i) Messrs Armen George and Company (Private) Limited, (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau, (iii) Messrs G. and K. Shipping (Private) Limited, and (iv) Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

SHRI E. K. MOIDU ... Presiding Officer.

Reference No. 20 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to :

- (i) Messrs Armen George and Company (Private) Limited.
- (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau.
- (iii) Messrs G and K Shipping (Private) Limited, and
- (iv) Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri B. N. Ash, Advocate.

On behalf of Workmen.—Shri Bacha Prasad, General Secretary, Calcutta Dock Workers' Union.

State : West Bengal

Industry : Port & Dock

AWARD

By Order No. L-32012/18/74-P&D/CMT/DIV(A) dated 7th March, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the demand for bonus for the year 1973-74 in respect of the workmen employed under Messrs Armen George and Company (Private) Limited, Messrs Calcutta Shipping Bureau, Messrs G and K Shipping (Private) Limited and Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Limited, is justified ? If so, to what rate are they entitled ?”

2. Both the management as well as the union representing the workmen filed their written statements raising various contentions as regard the bonus payable to the workmen for the year 1973-74 by the specified companies mentioned in the Schedule to the Reference.

3. The case was posted to 17-9-1975 for settlement of the dispute between the parties. But, today the parties appeared and filed a settlement of the dispute. So, the date of hearing was advanced to this date and the reference is disposed of.

4. On consideration of the relevant clauses of the settlement mentioned as Annexure A to the petition, I am satisfied that the settlement is in the interest of both the employers and employees and that it is just and proper that the settlement be recorded.

5. In the result an award is passed in terms of the settlement. The terms of settlement together with the Annexure A will form part of the award.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Dated, Calcutta,

The 2nd September, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, CALCUTTA
Reference No. 20 of 1975
In the matter of an Industrial Dispute
BETWEEN

Employers in relation to the Management of

- (i) Messrs Armen George & Co. (Pvt.) Ltd., 35, Ezra Street, Calcutta-1.
- (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau, 11/1, Dacres Lane, Calcutta-1.
- (iii) Messrs G & K Shipping Private Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.
- (iv) Messrs Commercial Agencies Pvt. Ltd., 12-A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

AND

Their workmen, represented by Calcutta Dock Workers' Union, 27B, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23.

The humble joint petition, on behalf of the parties
above-named.

Most respectfully SHEWETH :

1. That the workmen, who are employed by and are on the pay-roll of the four above-named Companies, have been paid their Bonus for the year 1973-74 and they have no claim whatsoever outstanding in that behalf.

2. That the labourers hitherto employed on MMTC's work, (Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd.) by the above-named four Companies, through Labour Contractors, are members of Calcutta Dock Workers' Union, and are represented by the Union, and the claim for Bonus for the year 1973-74, as in the Issue in the instant Reference is confined to the said labourers.

3. That the petitioners had prayed for and obtained an adjournment of the hearing fixed on 1-9-75 to enable them to amicably settle the dispute out of the Tribunal. The petitioners accordingly met at a bipartite level at the Office of the first above-named Company on 1-9-75 and arrived at a Bipartite Settlement, whereby the demands, as made in this Union's Charter of Demands, dated 28th August 1975, have been amicably settled. A copy of the said Bipartite Settlement, dated 1-9-75, is annexed hereto, and is marked Annexure "A".

4. That in terms of Clauses 9 and 10 of the aforesaid Bipartite Settlement, dated 1-9-75, *Inter alia*, (i) this Union agreed to withdraw the claims for Bonus for the year 1973-74, pending before this Hon'ble Tribunal, under Reference No. 20 of 1975, and (ii) the parties agreed to jointly approach this Hon'ble Tribunal, for an Award of "Amicable Settlement".

The petitioners humbly pray that your Lordship would be graciously pleased to dispose of the instant Reference, on the basis that the demand for Bonus for the year 1973-74 stands withdrawn by the Union, and make an Award accordingly.

And, for this act of kindness, as in duty bound, the petitioners shall ever pray.

2-9-1975.

for and on behalf of
Calcutta Dock Workers Union
Sd/- Illegible,
General Secretary.

ANNEXURE "A"

SETTLEMENT IN FORM H (UNDER RULE 58)

Memorandum of settlement under section 18(1) OD Industrial Disputes Act 1947 between (1) Armen George & Co. (Pvt) Ltd., 35, Ezra Street, Calcutta-1, (2) Commercial Agencies Pvt. Ltd., 12-A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, (3) G & K Shipping Private Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 and (4) Calcutta Shipping Bureau, 11/1, Dacree Lane, Calcutta, and their handling workers represented by Calcutta Dock Workers' Union (HMS), 27-B, Circular Garden Reach Road, Kidderpore, Calcutta-23 on Bilateral Level on 1-9-1975.

PARTIES PRESENT

- (1) Representing the Handling Agents.—(1) Shri S. B. Singh, Director, Armen George & Co. (P) Ltd.
- (2) Shri H. P. Rudra, Director, Commercial Clearing Agencies Pvt. Ltd., (3) Shri S. K. Chatterjee, Director, G & K Shipping Pvt. Ltd. (4) Shri Minir Mukherjee, Partner, Calcutta Shipping Bureau.
- (2) Representing the workmen.—Shri Bacha Prasad, General Secretary, Calcutta Dock Workers Union.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The General Secretary, Calcutta Dock Workers Union (HMS) vide his letter No. CDWU/495 dated 28th August, 1975 had submitted a charter of demands on behalf of the handling workers engaged in Docks and Godowns to the four Handling Agents. The demands were (1) Enhancement of daily rates, (2) Double wages when booked on Port Working Holidays, (3) Grant of Port Closed Holidays and (4) Bonus for the year 1974-75.

The labourers hitherto engaged by the above-named Handling Agents, on MINERALS & METAL TRADING CORPORATION OF INDIA (abbreviated "MMTC") of 8, India Exchange Place, Calcutta (a Government of India Undertaking)'s work, used to be so engaged through Labour Contractors, who used to be paid charges on a tonnage basis by the Handling Agents, and the Labour Contractors paid the labourers employed by them at mutually agreed daily rates.

The existing system of engagement of labour on MMTC work, through Labour Contractors, being no longer permissible, the labour force available for the aforesaid work, has decided on the elimination of the intermediaries, and on direct employment. Accordingly, the labour force has chalked out a plan for formation of Managing Committees from amongst the labourers themselves.

The parties met on 1-9-1975 at the office of Armen George & Company (Private) Limited at 35, Ezra Street, Calcutta-1 and after prolonged discussion the parties came to an amicable settlement on the following terms and condition.

TERMS :

It is agreed by and between the parties.

1. That the labourers will constitute two separate Pools, one for the Docks and the other for Godowns respectively called the MMTC DOCK WORKERS POOL and the MMTC GODOWN WORKERS POOL, hereinafter referred to as "D. W. POOL" and "G. W. POOL".

2. That the D. W. POOL will have a strength of 100 labourers and the G. W. POOL will have a strength of 80 labourers.
3. That the two above-mentioned Pools will be run by two separate Managing Committees. The Managing Committee for the D. W. POOL will at present be formed with the following persons from among the labour force :
 1. Sri Ram Ashish Tewari.
 2. Sri Narasingh Murti.
 3. Md. Taiyab Hossain.
 4. Abul Hossain
 5. Md. Yakub.
 6. Amirullah.

The Managing Committee for the C. W. POOL will at present be formed with the following persons, from among the labour force :

1. Md. Jan.
2. Md. Anwar II.
3. Monirul Haque.
4. Rahamatullah.
5. Md. Kashim.

4. That the members of the two Managing Committees, shall be responsible for the engagement of labourers belonging to the Pool managed by the Managing Committee concerned. Such members shall be responsible for—

- (i) taking work orders from the Handling Agents;
- (ii) booking of labourers according to the requirements of the Handling Agents ;
- (iii) raising bills on the Handling Agents and receiving payment from the Handling Agents.

Payments will be made by the Handling Agents (against bills submitted) to any two members of the Managing Committee in question, duly authorised in that behalf by the Calcutta Dock Workers' Union, which shall have power to regulate the functioning of the Managing Committees and to supervise their work.

5. The labourers will be paid their charges, by the Handling Agents, through the Managing Committees, and the charges will be collected, on behalf of the Managing Committees, by two of their respective members, authorised in this behalf. The distribution of the charges among the labourers shall be the responsibility of the Managing Committees. After having made payment of any bill raised by the D. W. POOL or by the G. W. POOL, as the case may be, the Handling Agents shall have no liability whatsoever, for fair and equitable distribution among the labourers

6. The charges payable to the labourers will be as follows :—

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|
| (1) For loading | .. | Rs. 2.25 paise per tonne. |
| (2) For unloading & stocking | .. | Rs. 2.25 paise per tonne. |
| (3) For Weighment & stacking | .. | Rs. 2.25 paise per tonne. |
| (4) For removal & re-stacking | ... | Rs. 2.25 paise per tonne. |
| (5) Casual Labour | .. | Rs. 10/-per day of 8 hours |

The above rates are deemed to include 25 paise per tonne in lieu of Bonus. As regards Casual Labour, the daily rate is nett.

7. That the labourers engaged shall under no circumstances, claim and/or be entitled to any Bonus, or any Compensation, or any Notice or any payment in lieu of Notice. They shall also not be entitled to any benefits now enjoyed or as may hereafter be enjoyed by the Handling Agents' own workmen/employees on their respective pay rolls.

8. That any labourer, sustaining any personal injury, in course of his work will be entitled to medical treatment, at the cost of the Handling Agents concerned, under whom he may be serving at the time. He will also be entitled to an allowance of Rs. 2.50 paise per day for the number of days, he is unable to work, due to the injury. Payment will be made to the Managing Committee concerned.

9. Since as a gesture of goodwill the Handling Agents have agreed to give 25 Paise per tonne in lieu of Bonus from 1-4-1975, the Union agreed to withdraw the claim for Bonus for the year 1974-75. In view of amicable settlement on the demands placed by the Union, the Union agreed to withdraw the claims of Bonus for the year 1973-74, which is pending before the Central Government Industrial Tribunal under Reference No. 20 of 1975.

10. For this purpose the Handling Agents and the Union will jointly approach the learned Tribunal to give award of "Amicable Settlement".

11. This Settlement shall have retrospective effect from 1-4-1975, and shall remain in force and be binding on the parties hereto up to and inclusive of 31st March, 1977.
For the Union

For and on behalf of

CALCUTTA WORKERS UNION

Sd/- B. Prasad

General Secretary

For the Handling Agents

ARMEN GEORGE & CO. PRIVATE LTD.

Sd/- S. B. Singh
Director

COMMERCIAL CLEARING AGENCIES PRIVATE LTD

Sd/- H. P. Rudra

Director

WITNESS :

(1) Md. Taiyab Hussain
Sd/- M. Taiyab,

For G & K Shipping Pvt. Ltd.,
Sd/- S. K. Chatterjee

(2) Amirullah
Sd/- Amirullah

Director.
Calcutta Shipping Bureau

(3) Md. Jan
Sd/- Md. Jan

Sd/- M. K. Mukherjee
Partner.

(4) Manirul Haque
Sd/- Manirul Haque.

(5) Md. Kashim
Sd/- Md. Kashim.

Dated 1st September, 1975.

[No. L-32012/18/74-P&D/CMT/D-IV-(A)]

NAND LAL, Section Officer.

नई दिल्ली 3 सितम्बर, 1975

का० प्र० 4231.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिसर्स एलेक्ट्रिक आटोमेशन कम्पनी, वी० विकास एस्टेट, आर्य रोड के सामने, गोरे गांव पूर्व मुम्बई, जिसमें श्री निवास बिल्डिंग 333, मंगर बल्लभ भाई पटेल रोड, मुम्बई-4, स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों अतिव्यय निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः यत्र, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एम० 35018 (4) 75-पी० एफ० II]

भार० पी० नरुला, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4231.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Electric Automation Company, V. Vikas Estate off Aarey Road, Goregaon East, Bombay, including its branch at Shree Niwas Buildings, 333, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S-35018(4)/75-PF. II]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

का० आ० 4223.—हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री पी० माट्टू, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम और रोजगार विभाग को, श्री नालचन्ध प्रार्थी के स्थान पर कर्मचारी बीमा राज्य निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में “(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)” के शीर्षक नीचे मध्य 11 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

“श्री पी० के० माट्टू,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश सरकार,

श्रम और रोजगार विभाग,

शिमला।”

[फाईल संख्या यू-16012/8/75-एच०आई]

New Delhi, the 5th September, 1975

S.O. 4232.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh, has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P. K. Mattoo, Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Labour and Employment Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in the place of Shri Lal Chand Prarthi;

78 GI/75—9.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading “(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)”, against item 11A, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

“Shri P. K. Mattoo,

Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Labour and Employment Department,
Simla.”

[File No. U-16012/8/75-HI]

का० आ० 4233.—आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में, श्री एम० आर० पाई सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, आवास और नगरपालिका प्रशासन विभाग को श्री आर० विठ्ठल राव के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित किया है,

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, “(धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नाम निर्देशित)” शीर्षक के अधीन मध्य 7 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

“श्री एम० आर० पाई०,

सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,

स्वास्थ्य, आवास और नगरपालिका प्रशासन विभाग,
हैदराबाद।”

[फाईल संख्या यू०-16012(12)/75-एच०आई०]

S.O. 4233.—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri M. R. Pai, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Health, Housing and Municipal Administration Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in the place of Shri R. Vithal Rao;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading “(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)”, against item 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Shri M. R. Pai,

Secretary to the Government of Andhra Pradesh,
Health, Housing and Municipal Administration
Department, Hyderabad.”

[F. No. U-16012(12)/75-HI]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

पश्चिम (1) मारावा

(2) गोगलापलेम

(3) नीमानापल्ली।

[एस०-38013/12/74-एच० आई०]

का० आ० 4234.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 28 सितम्बर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 के धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

क्षेत्र	होबली	तालुक	जिला
महादेवापुरा	कृष्णाराजापुरा	बंगलौर	बंगलौर
और दयाव सन्धा गांव		दक्षिण	

[एस०-38013/11/73-एच० आई०]

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4234.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th September, 1975 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely:—

Area	Hobli	Taluk	District
Mahadevapura and Dyavasan-dra Village	Krishnarajapura	Bangalore South.	Bangalore

[No. S-38013/11/73-HI]

का० आ० 4235.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 28 सितम्बर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

विमाछापटनम जिला में गोपालापटनम, वेण्णानटा और वेंकटापुरम के राजस्व ग्रामों में बना और निम्नलिखित द्वारा परिवर्द्ध क्षेत्र —

- उत्तर (1) लक्ष्मी पुरम
(2) कृष्णारायापुरम
(3) पुरुशोथापुरम
- पूर्व (1) आदि विवरम
(2) बुच्चिराजुपालेम
- दक्षिण (1) पुलाम्बोटला पालेम
(2) मिण्डी
(3) मुलागादा

S.O. 4235.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th September, 1975, as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

The area comprising the revenue villages of Gopalapatnam, Venagunta and Venkatapuram in Visakhapatnam District and bounded by:—

- North . (1) Laxmipuram
(2) Krishnarayapuram
(3) Purushothapuram
- East . (1) Adivivaram
(2) Butchirajupalem
- South . (1) Pulambotla Palem
(2) Mundi
(3) Mulagada
- West . (1) Narava
(2) Portlapalem
(3) Cheemalapalli

[S-38013/12/74-HI].

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 4236.—यत्, बिहार राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में, श्री राम उपदेश सिंह के स्थान पर श्री आई० सी० कुमार, सचिव, बिहार सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूत-पूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 9 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री आई० सी० कुमार,
सचिव, बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना।"

[फाइल संख्या यू०-16012/11/75-एच० आई०]

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4236.—Whereas the State Government of Bihar has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri I. C. Kumar, Secretary to the Government of Bihar, Depart-

ment of Labour and Employment to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Ram Updesh Singh ;

Labour and Employment Department,
Chandigarh".

[No. U-16012(13)/75-HI]

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 7th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 9, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri I. C. Kumar,

Secretary to the Government of Bihar,
Labour and Employment Department,
Patna".

[F. No. U-16012/11/75-HI]

का० प्रा० 4237.—यतः हरियाणा राज्य सरकार ने, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुमरण में, कुमारी एम० सेठ के स्थान पर श्री पी० पी० केप्रीहान प्रायुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, कणौगढ़ को, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, "धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के धनगत, मद 11 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री पी० पी० केप्रीहान,
प्रायुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
कणौगढ़"।

[संख्या यू०-16012(13)/75 ए०प्रा०]

S.O. 4237.—Whereas the State Government of Haryana has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P.P. Caprihan Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Miss M. Seth ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. P. Caprihan,
Commissioner and Secretary to Government of
Haryana,

का० प्रा० 4238.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के श्रम-तार बोर्ड, संचार मंत्रालय के सरकारी तारमण्डार, मुम्बई के कर्मचारियों को अन्य प्रकार से बेसी ही प्रसुविधाएं प्राप्त हैं, जिनकी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन व्यवस्था की गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3195 तारीख 25 नवम्बर, 1974 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 15 जनवरी, 1975 से 14 जनवरी, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (साधारण) विनियम, 1930 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी।

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(1) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन भी गई किसी विवरणी में की गई विशिष्टियों को मर्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिष्ठित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि को बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाप्रेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(3) यह अभिनिष्ठित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के अब भी हकदार है जिनके प्रतिकल-स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, या

(4) यह अभिनिष्ठित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए मजबूत होगा, अर्थात् —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक में घोषणा करना कि वह उसे के सूचनाएं दे, जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर्श में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारनाशन कर रहा हो यह उपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी खेजा बहियां और अन्य दस्तावेजों

जो व्यक्तियों के नियोजन और मजूरी के संदाय से संबंधित हों, को प्रस्तुत करें, और उसे उनकी परीक्षा करने दें या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझे वैसी जानकारी जो वह आवश्यक समझे या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक और उसके अधिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाये या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखावही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक शायन

इस मामले में छूट को पूर्वपिक्की प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने का छूट की मंजूरी के लिए महानिदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सिफारिश विलम्ब से प्राप्त हुई थी। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियाँ जिनमें कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वपिक्की प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस० 38017/5/73-एच आर्डी]

S.O. 4238.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government Telegraph Stores, Bombay, belonging to the Government of India in the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs Board are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3185 dated the 25th November, 1974, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th January, 1975 upto and inclusive of the 14th January, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employers continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. S-38017/5/73-HI]

गई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

क्र० आ० 4239.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार (1) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला (2) विश्वेश्वरिया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलूर (3) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद (4) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान, मैसूर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 17 नवम्बर, 1974 से 16 नवम्बर, 1975 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है अर्थात्—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जहां कर्मचारी नियोजित है एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनके कि वे इस अधिसूचना में दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व अभिदायों के आधार पर हकदार हो गए हो;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है),

ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विविधियों सहित देगा जो उस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में वेनी थी।

- (5) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(1) उक्त अवधि की शुरुआत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में दी गई विविधियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की शुरुआत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के प्रय भी हकदार हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(4) यह अभिलिखित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए संभव होगा, अर्थात्—

(क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे वे सूचनाएं दें जो उपरोक्त या निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझे जाएं ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधि-योगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी लेखे बहियां और अन्य वस्तावेजों, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, को प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझे, वैसी जानकारी दें ; या

(ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए, या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य वस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना।

आवश्यकता का पान

इस मामले में छूट को पूर्वपक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने को छूट प्रदान करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश केवल जून, 1975 में ही प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियाँ, जिन में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वपक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस 38017/13/74-एच घाई]

ज० सी० सक्सेना, अवसर सचिव।

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4239.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts (1) National Aeronautical Laboratory, Bangalore (2) Visvesvaria Industrial and Technological Museum, Bangalore. (3) Regional Research Laboratory, Hyderabad and (4) Central Food Technological Institute, Mysore from the operation of the said Act for a period of one year with effect from the 17th November, 1974, upto and inclusive of the 16th November, 1975.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations ; 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received only in June, 1975. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. S. 38017(13)/74 HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली 8 सितम्बर, 1975

क्र० आ० 4240.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैगनीज की खानों में नियोजित कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जैसी कि वे उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, नियत करने के लिए, की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार, उक्त सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिध के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

मैगनीज खान

अकुशल

(1) आया (2) बटलर (3) रखवाला (4) चौकीदार (5) क्लीनर (6) ड्रेसर (7) मजदूर (8) लौडर (9) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (10) संदेशवाहक (11) तम्बर टेकर (12) कार्यालय परिचर (13) अपरासी (14) पिकर (पुरुष/स्त्री) (15) छटाईकार (16) हाइकश (पुरुष/स्त्री) (17) ट्रिपर (18) ट्रांलीवाला (19) ट्रांली ट्रिपर (20) जल वाहक (21) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।

5.80

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

(1) बैकमैन (2) बैकमैन (3) रोकड़ गाई (4) चेकर (5) रसोइया (6) धोबी (पुरुष/स्त्री) (7) फायरमैन (8) ग्रीजर (9) ग्राइंडर (10) हथौड़ा (11) मददगार (बढ़ई, कूशर प्रचालक) (12) जमादार (13) खलासी (मुलडौशर आदि) (14) कक्ष प्रभारी (15) मेट/मास्ती (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र रहित) (16) लिपिकीय कर्मचारी जो मैट्रिकुलेट न हों (17) तेलवाला (18) प्वाइंट मैन (19) सैम्पलर (20) भाण्डारक (21) अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।

7.25

कुशल

(1) असेयर (2) चर्मकार (3) उत्सफोटक (शाट फायरर) (4) बढ़ई (5) चार्जमैन (6) रसायनज्ञ (7) कम्पाऊंडर (8) शिशु परिचर (9) नक्शा नवीस (10) ड्रिलर (11) ड्राइवर (12) विजली मिस्त्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) राजगीर (16) यांत्रिक (17) दायी (18) मिस्त्री (19) सांकेकार (20) प्रचालक (21) ओवरसीयर (22) पेंटर (23) पार्सी फिटर (24) पर्यवेक्षक (25) सर्वेक्षक (26) टीनकार (27) टिम्बरमैन (28) टर्नर (29) वेल्डर (30) वायरमैन (31) वर्क सरकार (32) अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।

8.70

लिपिकीय

(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) भाण्डारपाल (5) भण्डापक (6) टाइम-कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।

8.70

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण

1. प्रस्थापित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें प्राधारी वर, जीवन निर्वाह भत्ता, आश्वासक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के या असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें उपर्युक्त अनुसूची में समुचित प्रवर्ग की उल्लिखित दरों का 70 प्रतिशत होंगी।

4. (क) अकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता का कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं,

(ख) अर्धकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अधिकांश शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता

या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ?

5. जहाँ सविदा/करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरे अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहाँ ऐसी उच्चतर दरे इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएगी और लागू की जाएगी ।

[सं० एस० 32019(10)/75-इल्यू० सी० (एम० इल्यू०)]

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 4240.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in manganese mines specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of period specified above will be considered by the Central Government.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Manganese Mines	
Unskilled :	
(1) Ayah, (2) Butler, (3) Care taker, (4) Chowkidar, (5) Cleaner, (6) Dresser, (7) Labourer, (8) Loader, (9) Mazdoor (Male/Female), (10) Messenger, (11) Number-taker, (12) Office Boy, (13) Peon, (14) Picker (Male/Female), (15) Sorter, (16) Sweeper Male/Female, (17) Trimmer, (18) Trolleyman, (19) Trolley triper, (20) Water Carrier, (21) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. P. 5.80
Semi-skilled/Unskilled Supervisory :	
(1) Bankman, (2) Brakesman, (3) Cash Guard, (4) Checker, (5) Cook, (6) Dhobi (Male/Female), (7) Fireman, (8) Greaser, (9) Grinder, (10) Hammerman, (11) Helper, (12) Carpenter, (13) Crusher operator, (14) Jamadar, (15) Khalasi (Bulldozer, etc.), (16) Lamp Room Incharge, (17) Mate/Mali (without competency certificate under MMR 1961), (18) Oiler, (19) Pointsman, (20) Sampler, (21) Storeman, (22) Other categories by whatever name called which are Semi-skilled/Unskilled Supervisory.	7.25
Skilled :	
(1) Asayer, (2) Black-smith, (3) Blaster (Shot firer), (4) Carpenter, (5) Chargeman, (6) Chemist,	

1	2
(7) Compounder, (8) Creche Attendant, (9) Draughtsman, (10) Driller, (11) Driver, (12) Electrician, (13) Fitter, (14) Foreman, (15) Mason, (16) Mechanic, (17) Midwife, (18) Mistry, (19) Moulder, (20) Operator, (21) Overseer, (22) Painter, (23) Pipe-Fitter, (24) Supervisor, (25) Surveyor, (26) Tin-smith, (27) Timberman, (28) Turner, (29) Welder, (30) Wireman, (31) Work-sarker, (32) Other categories by whatever name called which are skilled	8.70

Clerical :

(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register-keeper, (4) Store-keeper, (5) Teacher, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical	8.70
--	------

EXPLANATIONS FOR THE PURPOSES OF THIS NOTIFICATION

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 8 years of age or for disabled persons shall be 70% of the rates payable to the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skills or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skills or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[S-32019(10)/75-WC(MW)]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० आ० 4241.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार के पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1659 तारीख 27 जून, 1960 के साथ, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (III) के साथ, पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के राज्यों में स्थित अन्नक खानों में नियोजित कर्मचारों के लिए न्यूनतम

मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए तथा ऊपर विनिर्दिष्ट राज्यों से भिन्न राज्यों में स्थित अन्नक दालों में नियोजित कर्मचारियों के उन प्रवर्गों के, जो इससे उपाध्द सूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, वेय मजदूरी की न्यूनतम दरों की, जैसी कि वे उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, नियत करने के लिए की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं की, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कर्मचारियों की श्रेणियां	न्यूनतम मजदूरी की प्रतिदिन दर
1	2
	₹०.१०

अकुशल :

मजदूर (गुरु और स्त्री) क्लीनर, सफाई परिचर, संदेश वाहक / कार्यालय परिचर, पहरेदार, खलासी, सहायक, पानीवाला, मददगार, भारवाहक, कुली, माली, कोई अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

5.80

अर्धकुशल :

हथौड़ी, प्रधान कुली, अन्नक काटने वाला—श्रेणी 2, छटाईकार, ड्रेसर—श्रेणी 2, गेज कर्मकार, डिस्क कर्मकार, परिचर, रसोइया, विस्फोटक वाहक, गमैन, वाइडिंग इंजन ड्राइवर—श्रेणी 2, ग्रीधर, बेस्ट कटर, सहायक फिटर, कोई अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल प्रकृति के हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

7.25

कुशल :

ड्रिलर, उल्फोटक, मिस्त्री, अन्नक काटने वाला—श्रेणी 1, बड़ई, लोहार ड्रेसर श्रेणी 1, खनन मैट, इंजन ड्राइवर, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, सांचेकार, वैल्डर, वाहन ड्राइवर, राजगीर, वाइडिंग इंजन ड्राइवर श्रेणी 1, फायर-मेन, शाट फायरर, कम्प्रेसर ड्राइवर, यांत्रिक, पम्प फैन ड्राइवर, ग्राइन्डर, सिरदार, लेघमेन, कोई अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, लिपिकीय :

8.70

लेखापाल, टंक/आधुनिक, लिपिक कम्पाउंडर, भाण्डारक प्रभारी, पारी प्रभारी, टाइमकीपर, रोकड़िया, मिश्रगृह परिचर, पर्यवेक्षी, कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

8.70

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :-

(1) प्रस्थापित मजदूरी की न्यूनतम दरें सब सम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत

पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें डेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) जहां संविदा/करार आवि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएंगी और लागू की जाएंगी।

(4) (क) अकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हों;

(ख) अर्धकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[एस० 32019(2)/72-उल्फू० ई० (एम०-उल्फू०)]

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4241.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and also read with the notification No. S.O. 1659 dated the 27th June, 1960 of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment for revising the minimum rates of wages for employees employed in Mica Mines situated in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan and fixing the minimum rates of wages for employees employed in mica mines situated in the States other than those referred to above as specified in column 2 of the schedule annexed thereto, payable to the categories of employees specified in the corresponding entries in column 1 of the said schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the Gazette of India.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the said period will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
1	2

UNSKILLED :

Mazdoor (Male and Female) Cleaner, Scavenger, Messenger/Office Boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Coolies Mali, any other categories by what soever name called which are of unskilled nature

5.80

1	2
	Rs. P.
SEMI SKILLED :	
Ham nerman, Head Cooly, Mica cutter Grade-II Sorter, Dresser Grade II, Gauge Worker, Disc Worker, Attendant, Cook, Explosive Carrier, Gun Man, Winding Engine Driver Grade-II Shoarers Waste Cutter, Assistant fitter, any other categories, by what so ever name called, which are of semi-skilled nature.	7.25
SKILLED :	
Driller, Blaster, Mistry, Mica Cutters, Grade I Carpenter, Blacksmith, Dresser Grade-I, Mining Mate Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle Driver, Mason, Winding Engine Driver Gr. I, Fireman, Shot Firer Compressor Driver, Mechanic Pump Fan Driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by what so ever name called which are of skilled nature	8.70
CLERICAL :	
Accountant, Typist/Steno Clerk, Compunder, Storekeeper/Incharge, Shift Incharge, Time Keeper, Cashier, Creche Attendant, Supervisory, any other categories by what so ever name called which are of clerical nature.	8.70

Explanation.—For the purpose of this notification,—

(1) The minimum rates of wages proposed are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concession, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest,

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also;

(3) Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated as minimum wages;

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019(2)/72-WE(MW)]

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० प्र० 4242.—केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (I) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोक्सइट की खानों में नियोजित कर्म-कारों के उन प्रवर्गों को जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, वेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को जैसा कि वे उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, नियत करने के लिए की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों

78 GI/75--10

की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है। यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से-तीन मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी मांगो या सुझाव प्राप्त हों केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	मजदूरों की दिनप्रतिदिन न्यूनतम दर
	₹० पैसे

बोक्सईट खान

अर्धकुशल]

- (1) क्लीनर (2) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (3) खनक (4) कार्यालय परिचय (5) चपरासी (6) पिकर (पुरुष/स्त्री) (7) झाड़कश (8) चौकीदार (9) पानी बाहक (10) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों। 5.80

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

- (1) सहायक ड्रिलर (2) बुलडोजर खसारी (3) बड़ई सहायक (4) कूशर प्रचालक सहायक (5) कैटीन परिचर (6) माली (7) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र रहित) (8) मुकवम (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित) (9) सैम्पलर (10) टूल शार्पेनर (11) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल पर्यवेक्षी हैं, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों। 7.25

कुशल

- (1) चर्मकार (2) उत्स्फोटक (शाट फायरर) (3) बड़ई (4) कूशर प्रचालक (5) परिसर (6) कम्प्रेसर ड्रिलर (7) ड्रिलर (8) ड्राइवर (9) मिस्त्री (10) फिटर (11) यांत्रिक (12) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र सहित) (13) शक्तिचालित शावर प्रचालक (14) पम्प ड्राइवर (15) बिजली और पम्प हाउस प्रचालक (16) पम्प प्रचालक (17) पर्यवेक्षक (18) ट्रेक्टर प्रचालक (19) अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों। 8.70

लिपिकीय

- (1) लिपिक (2) मुंशी (3) आशुलिपिक (4) टंकक (5) अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों। 8.70

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :-

1. प्रस्थापित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए वेय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें डेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के या असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें उपर्युक्त अनुसूची में समुचित प्रवर्ग की उल्लिखित दरों का प्रतिफल होगा।

4. (क) अकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं,

(ख) अर्धकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या मशमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने के योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या मशमता अपेक्षित है और जिनके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा/करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, यहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समशी जाएंगी और लागू की जाएंगी।

[सं० एस-32019(11)/75-एस्सू०सी०/(एम० डब्ल्यू)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4242.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in bauxite mines specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
(1)	(2)
Rs. P.	
Bauxite Mines	
Unskilled :	
(1) Cleaner, (2) Mazdoor (Male/Female), (3) Miner, (4) Office Boy, (5) Pcon, (6) Picker (Male/Female), (7) Sweeper, (8) Watchman, (9) Water Carrier, (10) Other categories by whatever name called which are unskilled.	5.80

(1)	(2)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory :	Rs. P.
(1) Assistant Driller, (2) Bull-Dozer Khalasi (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Gardener/Mali, (7) Mate without competency certificate under MMR-1961, (8) Maccadam (without competency certificate under MMR-1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharpener, (11) Other Categories by whatever name called which are semi-skilled unskilled supervisory.	7.25

Skilled :	8.70
(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) Carpenter, (4) Crusher Operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Mate (with competency certificate under MMR-1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendant, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Other categories by whatever name called which are skilled.	

Clerical :	8.70
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical	

Explanations for the puposes of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages [for young persons below 18 years of age or for disabled persons shall be 70% of the rates payable to the appropriate category as specified in the schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skills or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skills or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S.32019(11)/75-WC(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4243.—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1698, तारीख 12 अप्रैल, 1972 द्वारा गठित शिमला में स्थित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

प्रतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री शमशेर सिंह कंवर को यथा पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का पीठा-सीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या एस०-11025/19/75-डी ए]

एस० एस० सहस्रनामान, उप सचिव

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4243.—Whereas, a vacancy has occurred in the office of the presiding officer of the Labour Court at Simla constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1698, dated the 12th April, 1972;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Shamsher Singh Kanwar as the presiding officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11025/19/75-DIA]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 मिनस्वर 1975

का०आ० 4244.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, वर्ष 1975-76 के दौरान कोयला खान श्रमिक गृह और साधारण कल्याण निधि के साधारण कल्याण खाने में प्राप्तियों और उसमें से व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन, वर्ष 1974-75 के लेखा विवरण सहित, तथा वर्ष 1974-75 के दौरान उक्त निधि के साधारण कल्याण खाने में से वित्तपोषण कार्यकलापों की रिपोर्ट, प्रकाशित करती है, अर्थात्:

भाग--I

1975-76 के दौरान प्राप्तियों और व्यय का प्राक्कलन साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
र०	र०
4,12,24,400	3,18,90,000

भाग--II

वर्ष 1974-75 का लेखा-विवरण साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
1. 1-4-1974 को प्रारम्भिक प्रतिशेष (—) 14,86,864	
2. वर्ष के दौरान व्यय	3,10,99,209 (क)
3. वर्ष के दौरान प्राप्ति 3,74,81,600	
4. 31-3-1975 को अन्तिम प्रतिशेष	48,85,527
	3,59,94,736
	3,59,94,736

(क) इसमें कोयला खदानों के स्वामियों को औषधालय सेवाएं बनाए रखने के लिए दिया गया 8209 र० का 'उधार'।

टिप्पणः—ऊपर दिखाए गए आंकड़े अन्तिम हैं, क्योंकि महलेखा-पाल, बिहार ने अभी 1974-75 का लेखा बन्व नहीं किया है।

भाग--III

वर्ष 1974-75 के दौरान वित्तपोषण कार्यकलापों की रिपोर्टें

1. चिकित्सा सुविधाएं :

(क) अस्पताल : तीन केन्द्रीय अस्पताल अर्थात् बनबाद, आसनसोल और मानेन्द्रगढ़ में एक-एक, और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में स्थित 12 क्षेत्रीय अस्पताल, कार्य करते रहे। बनबाद, आसनसोल और मानेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की औसत संख्या क्रमशः 300, 350 और 100 थी। चान्दा कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल की स्थापना के बारे में सक्रिय रूप से विचार जारी है। अस्पताल को बल्लारपुर में स्थापित करने के लिए अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है। तलवार कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास नियम के अस्पताल में, निधि द्वारा उस कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्था के विकल्प के रूप में यथोचित भ्रान्ती तथा भ्रान्तवर्ती अनुदान देते हुए एक विशेषबाई की व्यवस्था के बारे में सक्रिय रूप से विचार जारी है।

(ख) औषधालय :—सुग्मा कोयला क्षेत्र में एक एलोपैथिक स्थायी औषधालय, असम कोयला क्षेत्र में एक जल चिकित्सा एकक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 29 प्रायुर्वैक औषधालय कार्य करते रहे। अपेक्षित प्रायुर्वैक औषधियों के विनिर्माण के लिए छरिया कोयला क्षेत्र में पाथर-डीह में स्थापित प्रायुर्वैक औषधशाला भी कार्य करती रही।

(ग) कुटुम्ब कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र :—संगठन के प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पताल से संलग्न कुटुम्ब कल्याण केन्द्र कार्यरत रहा। इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पहले से स्थापित ऐसे केन्द्र अर्थात् महिला-स्वास्थ्य-परिवर्शकों के भारसाधन में स्वतंत्र एककों के रूप में कार्य करते रहे। चान्दा कोयला क्षेत्र के कोयला खान कर्म-कारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल, चान्दा से संलग्न ब्लाक बराबर काम करता रहा।

(घ) औषधालय सेवाओं को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता :—कोयला खदान कर्मकारों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए कोयला खदानों में कोयला खदान प्रबन्ध तंत्रों को औषधालय सेवाओं को स्तरमान सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से सहायताएं अनुदान देने की स्कीम चालू रखी गई तथा कोयला खान प्रबन्धकों को इस वर्ष के दौरान कोयला खान के कर्मकारों के लिए औषधालय सेवाएं प्रदान करने के लिए 10.72 लाख रुपये (प्राक्कलित) की रकम दी गई। कोयला खदान स्वामियों को अपने कर्मकारों के फायदे के लिए अधिक औषधालय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता देने की स्कीम भी चालू रखी गई। इस अवधि के दौरान 8,209.00 र० की राशि 'उधार' के रूप में दी गई।

(ङ) क्षयरोगी उपाय :—क्षय पीड़ित कोयला खदान कर्मकारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए संगठन के अपने यक्ष्मा अस्पतालों में 312 औषधियों की व्यवस्था के अतिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्ष्मा आरोग्यश्रमों में 61 औषधियां प्रारक्षित रही। यक्ष्मा की गृहोपचर्चा की स्कीम चालू रखी गई और इस स्कीम के अधीन इलाज कराने वाले यक्ष्मा रोगी को अनुसूची के अनुसार निर्वह भत्ता दिया जाना भी चालू रहा। उस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 6.40 लाख र० (प्राक्कलित) की राशि व्यय की गई।

(च) परिवार नियोजन सेवाएं :—कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के अस्पतालों में तथा उस प्रयोजन के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खोली गई क्लिनिकों में परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त सलाह और निरोधों

का मुफ्त वितरण बढाकर चलता रहा। कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए सहायक अनुदान के संवाय की स्कीम प्रभावशील रही आई। 11 परिवार नियोजन केन्द्र, जिनमें से धनबाद/कल्ला केन्द्रीय अस्पतालों में एक-एक और शेष 9 निधि के विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में कार्य करते रहे।

(छ) पुनर्वास :— धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक के साथ संलग्न पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे। मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में छिन्नबाड़ा स्थित पुनर्वास केन्द्र कार्य करता रहा। पश्चिमी बंगाल में सिद्धबाड़ी में पुनर्वास एवं रोगनिरुक्तालय आरम्भ करने का प्रश्न अभी भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ज) अन्य चिकित्सकीय कार्यकलाप : चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य की विधा में इस संस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं—कैंसर, कोढ़ और मानसिक रोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त बैंक चलाना, खदान कर्मचारों को ऐनकों और इल्लिम धंतावली का मुफ्त प्रदाय, मलेरिया तथा फिलेरिया केन्द्रीय संचालन कार्य आदि, आदि।

2. शैक्षिक तथा सामोद-प्रमोद विषयक सुविधाएं :

(क) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश में लाने वाले कुछ सुसंगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

(1) बहुउद्देशीय संस्थान	61
(2) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	63
(3) महिला कल्याण केन्द्र	61
(4) पोषक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	147
(5) कोयला कर्मचारों के बच्चों को छात्र वृत्तियां	546
(6) विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास	1
(7) व्यवसाय-गृह	2

(ख) खेल और क्रीड़ा : कोयला खान के कर्मचारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1974-75 के दौरान विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के आयोजन के लिए संगठन द्वारा 1,08,559 रु० की रकम खर्च की गई।

(ग) अन्य क्रिया-कलाप : इस संबन्ध में दो गई अन्य सुविधाओं में (1) शैक्षिक संस्थाओं को सहायताएं अनुदान, (2) कोयला खानों के आश्रितों को छात्रवृत्ति (3) कोयला खानों के लिए क्रीड़ा और खेल-कूद की व्यवस्था, (4) फिल्मों का प्रदर्शन, (5) खानों में दुर्घटनाओं में मरने वाले कोयला खदान कर्मचारों की पत्नियों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था आदि, हैं।

3. जल-प्रदाय स्कीम : इस वर्ष के दौरान 3,73,456 रु० की रकम जल-प्रदाय स्कीमों पर खर्च की गई है। यह संगठन, जल-प्रदाय स्कीमों में विहित के अनुसार, व्यय के कुल खर्च के 50 प्रतिशत तक सहायताएं अनुदान देती रही। पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित, निधि द्वारा अंशतः वित्तपोषित, स्कीमों कार्यधीन हैं।

कुष्ठों की खुदाई :—अब तक पूरे किए गए कुष्ठों की संख्या 259 है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान, विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 3 कुष्ठ खोदने की स्वीकृति दी गई थी।

4. सहकारी आन्दोलन : इस वर्ष कोई भी नए प्राइमरी स्टोर, सहकारी प्रत्यक्ष रोसायटी और थोक या केन्द्रीय सहकारी स्टोर नहीं खोले गए। पुनर्गठनाधीन अवधि के अन्त में कोयला खानों के कर्मचारों के सहकारी

स्टोरों और प्रत्यक्ष रोसायटियों की संख्या 581 थी। इनमें 12 थोक या केन्द्रीय सहकारी स्टोर भी थे जो संगठन द्वारा पहले ही खोले गए थे।

[सं० जेड 16018/6/75-एम II]

बी० के० सम्सेना, उप सचिव

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O.4244—In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the general welfare account of the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund during the year 1975-76 together with a statement of the account for the year 1974-75 and a report on the activities financed during the year 1974-75 from the general welfare account of the said Fund, namely :—

PART-I

Estimates of Receipts and Expenditure during 1975-76 GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt	Expenditure
Rs. 4,12,24,400	Rs. 3,18,90,000

PART-II

Statement of Account for the year 1974-75

GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt	Expenditure
1. Opening balance as on 1-4-1974	(—)14,86,864
2. Expenditure during the year	3,10,99,209(a)
3. Receipt during the year	3,74,81,600
4. Closing balance as on 31-3-1975	48,95,527
	3,59,94,736
	3,59,94,736

(a) Includes Rs. 8,209 being 'Loan' to Colliery owners for maintenance of dispensary services.

N.B. The figures shown above are provisional as the account for 1974-75 has not yet been closed by the Accountant General, Bihar.

PART-III

Report on Activities financed during the year 1974-75

1. Medical Facilities :

(a) Hospitals : The 3 Central Hospitals, one each at Dhanbad, Asansol and Manendragarh and 12 Regional Hospitals situated in different coalfields continued to function. The bed strength of the Central Hospital at Dhanbad, Asansol and Manendragarh was 300, 350 and 100 respectively. The proposal for the establishment of a Regional Hospital in Chanda Coalfield remained under active consideration. The Hospital has finally been decided to be set up at Ballarpur. Provision of a specialised ward in the National Coal Development Corporation's Hospital in Talcher Coalfield by giving suitable recurring and non-recurring grant as an alternative to Fund's providing a Regional Hospital in that Coalfield remained under active consideration.

(b) Dispensaries : One Allopathic Static dispensary in Mugma Coalfield, one Mobile Medical Unit in Assam Coalfield and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields continued to function. The Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in Jharia Coalfield to manufacture required Ayurvedic Medicine also continued to function.

(c) Family Welfare and Maternity and Chief Welfare Centres : A family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals of the Organisation remained in operation. Besides, 8 such Centres already established by the Organisation in various coalfield areas also continued to function as independent units under the charge of qualified Lady Health Visitors. For the benefit of the colliery workers in Chanda Coalfield, the block attached to the Government Hospital, Chanda continued to function.

(d) Financial Assistance for Improving Dispensary Services : With a view to encourage the colliery management for improving the standard of dispensaries at the collieries for the benefit of colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 10.72 lakhs (estimated) was paid to the colliery managements during the year for providing medical facilities to the colliery workers. In order to encourage the colliery owners to provide more dispensary services for the benefit of their workers, the scheme of payment of financial assistance was also continued. A sum of Rs. 8,209.00 was paid as loan during the period.

(e) Anti T.B. Measures : For the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T.B. besides provision of 312 beds at the Organisation's own T.B. Hospitals, 61 beds remained reserved for them in different T.B. Sanatoria. The Scheme of Domiciliary T.B. treatment continued to function and payment of subsistence allowance to the T.B. patients undergoing treatment under the Scheme also continued to be made according to schedule. A sum of Rs. 6.40 lakhs (estimated) was incurred on this scheme during the period.

(f) Family Planning Services : Free advice on Family Planning continued to be given and contraceptives supplied free of cost at the coal Mines Labour Welfare Fund's Hospitals and at the clinics opened for the purpose in various coalfields. The scheme for the payment of grant-in-aid to the colliery owners for the Family Planning work continued to be in force. 11 Family Planning Centres one each at the Central Hospital Dhanbad/Kalla and the remaining 9 at the different Regional Hospitals of the Fund were in operation.

(g) Rehabilitation : The Rehabilitation Centres attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to function. The Rehabilitation Centre at Chhindwara in Madhya Pradesh Coalfield continued functioning. The question of commissioning the Rehabilitation-cum-Convalescent Home at Sidhabari in West Bengal Coalfield remained on its way.

(h) Other Medical Activities : Other important activities of the Organisation on the medical and public health sides were provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental cases, running of Blood Bank at the Central Hospitals Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures to the colliery workers, Malaria and Filariasis Control Operation etc. etc.

2. Educational and Recreation Facilities :

(a) Some relevant statistics high lighting the important activities on this account are given below :—

(i) Multipurpose Institutes	61
(ii) Adult Education Centres	63
(iii) Women Welfare Centres	61
(iv) Feeder Adult Education Centres	147
(v) Scholarship to the children of Colliery Workers	546
(vi) Boarding Houses for school going children	1
(vii) Holiday Homes.	2

(b) Games and Sports : Games and Sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year 1974-75 for organising various games and sports, a sum of Rs. 108559/- was spent by the Organisation.

(c) Other Activities : Other important facilities provided in this connection comprise of (1) grant-in-aid to the Educational Institutions (2) scholarship to wards of coal miners (3) provision for games and sports amongst coal miners (4) exhibition of films (5) provision for financial assistance to the wives and school going children of colliery workers who died of accident in mines.

3. Water Supply Schemes :

During the year, a sum of Rs. 3,73,356/- has been spent on Water Supply Schemes. The Organisation continued to pay grant-in-aid as prescribed in the Water Supply Scheme upto 50% on the total cost of scrutinised expenditure to the colliery managements. Two integrated water supply schemes executed by the State Governments of West Bengal and Bihar partly financed by the Fund remained under execution.

Sinking of wells :

Total number of wells so far completed is 259. During the period under report, sanction was accorded to sinking of one well.

4. Co-operative Movement :

No new Primary Stores, Credit Co-operative Societies and Wholesale or Central Co-operative Stores were opened during the year. The total number of Co-operative Stores and Credit Societies of colliery workers at the end of the period under review stood at 581. These included 12 Wholesale or Central Co-operative Stores already opened and continued functioning for colliery workers.

[No. Z 16016/6/75-MII]

B. K. SAXENA, Dy. Secy.

